राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 39

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, सोमवार, 19 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



शिखर की टीम पहले इम्तिहान में पास, श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे सात विकेट से जीता

>> 12

संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार : मोदी

मानसून सत्र आज से ▶ सत्र से पहले पीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, 33 दलों के 40 प्रमुख नेताओं ने लिया हिस्सा

विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए कसी कमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने पर होगा। इसी क्रम में ठीक एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सरकार संसद में स्वस्थ और उपयोगी प्रत्येक बहस के लिए तैयार है।

सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों के सुझावों को सुना। बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से ज्यादा नेता मौजूद थे। इनमें कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सपा से डा. रामगोपाल यादव, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा, तृणमूल से डेरेक-ओ ब्रायन आदि मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि नियमों के तहत उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर वह चर्चा के लिए तैयार हैं। बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में राजग के सहयोगी दलों में अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल और लोजपा से पशुपति पारस भी शामिल हुए। इन दोनों ही नेताओं को हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है।



नई दिल्ली में रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला(बाएं) और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय(दाएं)। एएनआइ

सरकार की दो दर्जन विधेयक पारित कराने की योजना

मानसून सत्र को लेकर सरकार ने कामकाज को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत संसद में दो दर्जन बिल पारित कराने की योजना है। इनमें 17 नए विधेयक हैं, जबकि तीन अध्यादेश भी हैं, जिन्हें विधेयक के रूप में पारित कराया जाएगा। वैसे भी अध्यादेश की अवधि सिर्फ छह माह की ही होती है, ऐसे में सरकार को इन्हें पारित करना जरूरी है। इनमें एक दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए गठित आयोग से जुड़ा है।

नए मंत्रियों की होगी परीक्षा

मानसून सत्र में नए मंत्रियों की परीक्षा भी होगी। उन्हें विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना होगा। वहीं, मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों का सदन में परिचय कराया जाएगा। साथ ही दोनों सदनों की बैठक व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या टीका लेने वालों को ही प्रवेश

मानसून सत्र में सिर्फ उन्हें ही शामिल होने की अनुमति होगी, जिनके पास 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी। या फिर उन्होंने वैक्सीन की डोज ले रखी हो।

विपक्ष ने सरकार की कड़ी घेराबंदी की बनाई रणनीति

मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इससे साफ है कि सत्र के शुरुआती दिन हंगामेदार होंगे। फिलहाल विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, उनमें कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन, वैक्सीन की कमी, पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कृषि कानून विरोधी आंदोलन जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं, सत्ता पक्ष भी बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं और उत्तर प्रदेश में सामने आए मतांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकता है।

कोरोना पर एनेक्सी में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे मोदी पेज>>3

मुंबई पर टूटा बारिश का कहर, 30 की मौत

आफत की बारिश ▶ चेंबूर में भूस्खलन के चलते छोटी पहाड़ी पर बने घरों पर तड़के दीवार गिरने से 19 लोगों की गई जान

एक महीने के भीतर महानगर ने पांच बार गरज के साथ तूफान का किया सामना

राज्य ब्यूरो, मुंबई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शनिवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश के कारण महानगर में कई स्थानों पर भूस्खलन एवं मकान गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं। जलशोधन केंद्र एवं पंपिंग स्टेशन में भी बारिश का पानी भर जाने से मुंबई में पेयजल का संकट पैदा हो गया है।

राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तो सिर्फ तीन घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई, जो अतिवृष्टि की श्रेणी में आती है। मुंबई के कई इलाके ऐसे रहे, जहां 350 मिमी. तक बरसात हुई। रविवार शाम साढ़े सात बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, भाईंदर में 238.5 मिमी, मीरारोड में 222 मिमी, सांताक्रूज में 130 मिमी, जुहू एयरपोर्ट परिसर में 133 मिमी और महालक्ष्मी में 167 मिमी बरसात दर्ज की गई है। भारी बरसात के कारण 11 स्थानों पर भूस्खलन या मकान ढहने की घटनाएं हुईं। चेंबूर क्षेत्र के न्यू भारत नगर में भूस्खलन के बाद एक दीवार ढह जाने से अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं। इसी प्रकार विक्रोली में एक दोमंजिला घर गिरने से 10 लोगों की जान गई। भांडुप में दीवार गिरने से एक युवक के मारे जाने की खबर है।

महानगर की दोनों नदियां उफान पर : मुंबई में माह भीतर गरज के साथ तूफान की यह पांचवीं घटना है। इससे पहले नौ, 11, 12 व 16 जुलाई को भी तूफान के बाद भारी बारिश हुई थी। मूसलधार बारिश से मुंबई की मीठी एवं दहिसर नदी उफान पर हैं। इनके आसपास के इलाकों में भूतल पर रहने वालों के घरों में पानी भर गया है। भारी बरसात का असर मुंबई से सटे ठाणे एवं पालघर जिलों में भी देखने को मिला। ठाणे के मीरा रोड और पालघर के वसई क्षेत्र में इमारतों के भूतल में तीन-चार फुट तक पानी भर गया।

- प्रधानमंत्री मोदी ने जान-माल के नुकसान पर दुख जताया, मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के स्वजन को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया है
- देश की आर्थिक राजधानी में भारी बरसात से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त, यातायात व्यवस्था चरमराई



मुंबई के चेंबूर के भरत नगर इलाके में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से कई घर ढह गए। दर्दनाक हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य में जुटे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) के जवान व स्थानीय नागरिक। समीर मारकंडे, मिड-डे

पंपिंग सेट में भी पानी भरा, सप्लाई बाधित भारी बरसात का असर आज मुंबई को जलापूर्ति करनेवाले भांडुप स्थित जलशोधन केंद्र एवं पंपिंग स्टेशन पर भी पड़ा। पंपिंग स्टेशन में रात को ही बरसाती पानी घुसने लगा। एहतियातन सुबह करीब 2.40 बजे पंपिंग स्टेशन की विद्युत आपूर्ति भी काटनी पड़ी। जिसका असर मुंबई की जलापूर्ति पर भी पड़ रहा है। बीएमसी द्वारा मुंबईवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। पंपिंग स्टेशन को दुरुस्त करने का काम अभी भी चल रहा है।

घरों से पानी निकालने में बाधा : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से जलभराव वाले इलाकों से पानी खींचकर समुद्र में फेंकने के लिए कई भारी पंपिंग सेट्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन रविवार सुबह करीब पांच बजे समुद्र में ज्वार का समय होने के कारण ये पंपिंग सेट भी जलभराव रोकने में कामयाब नहीं हो सके।

लोकल ट्रेन सेवा बाधित : रविवार होने कारण ज्यादातर मुंबईवासी घर में ही रहे, लेकिन जो निकले, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें रुक-रुक कर चलीं, किंतु मध्य एवं हार्बर रेलवे की लोकल ट्रेनें पटरी पर पानी भर जाने के कारण बाधित हुईं।

कई क्षेत्रों में 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना : मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे एवं कोंकण क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई है।

अफगानिस्तान ने पाक से राजदूत को वापस बुलाया

काबुल, रायटर

अफगान राजदूत को अगवा कर उसे यातनाएं देने की शर्मनाक घटना के बाद अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान से अपने राजदूत और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अफगान विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल की बेटी सिलसिला अलीखिल को इस्लामाबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने अगवा कर यातनाएं दी थीं। घायल सिलसिला का अभी इलाज चल रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'दोषियों की गिरफ्तारी व सजा होने और सुरक्षा संबंधी खतरे पूरी तरह खत्म होने तक अफगान सरकार ने राजदूत और सभी वरिष्ठ राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का फैसला लिया है।' पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अब तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है।

तालिबान आतंकियों की मदद के आरोपों से घिरी पाकिस्तान सरकार की परेशानी इस घटना से बहुत बढ़ गई है। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक, पाकिस्तान ने रविवार को बताया कि अफगान राजदूत की बेटी ने अपहरण से पहले जिन टैक्सियों पर सवारी की थी, उनके चालकों से पूछताछ की गई है और मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

सिलसिला अलीखिल का उस वक्त अपहरण किया गया, जब वह टैक्सी से कहीं जा रही थीं। अलीखिल राजधानी के एफ-9 पार्क इलाके में पाई गई थीं और उनके शरीर पर प्रताड़ना के निशान थे। गृह मंत्री शेख राशिद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'पुलिस अफगान राजदूत की बेटी के मामले की जांच कर रही है। अपहरणकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' उन्होंने बताया कि पहला टैक्सी चालक उन्हें खाद्दा बाजार लेकर गया, दूसरा चालक रावलपिंडी और तीसरा चालक दमन-आई-कोह से लेकर आया।

इस बीच, अलीखिल ने पुलिस को बताया कि वह उपहार खरीदने गई थीं। लौटते वक्त पांच मिनट के सफर के बाद टैक्सी चालक वाहन सड़क किनारे ले गया। वहीं एक अन्य व्यक्ति आ गया और उस पर चिल्लाने लगा। फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। अलीखिल ने कहा, 'मैं डर के मारे बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने खुद को गंदे स्थान पर पाया। इसके बाद मैंने पास के एक पार्क में जाने के लिए टैक्सी की और वहां से अपने पिता के सहयोगी को फोन किया, जो मुझे घर लेकर गए।'

- राजदूत अलीखिल की बेटी को अगवा कर यातनाएं देने के बाद उठाया कदम
- अफगान सरकार ने इस्लामाबाद से सभी राजनयिकों को भी बुलाया



इस्लामाबाद में स्थित दूतावास के मुख्यद्वार पर लगा बोर्ड। फाइल/इंटरनेट मीडिया



घायल सिलसिला अलीखिल का चल रहा है इलाज। सौ. ट्विटर

अफगानिस्तान में भारतीय परियोजनाओं पर खतरा बढ़ा पेज>>3

विरोध दरकिनार, सिद्धू ही बने पंजाब कांग्रेस के 'सरदार'

- संगत सिंह गिलजियां, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और नागरा बने कार्यकारी अध्यक्ष
- सुनील जाखड़ की छुट्टी, कांग्रेस हाई कमान ने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की



पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद लोगों का अभिवादन करते नवजोत सिंह सिद्धू। एएनआइ

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

फायर ब्रांड नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए 'सरदार' होंगे। पार्टी हाईकमान ने 48 दिन की मशक्कत और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध को दरकिनार करते हुए रविवार रात सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। उनके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें दोआबा से पिछड़े वर्ग से संगत सिंह गिलजियां, माझा से अनुसूचित जाति से सुखविंदर सिंह डैनी, मालवा से हिंदू सवर्ण वर्ग से पवन गोयल और सिख समुदाय से कुलजीत सिंह नागरा के नाम शामिल हैं।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को यह फैसला लेने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करने वाले सांसदों व नेताओं को फोन कर संकेत दे दिए थे कि पार्टी सिद्धू को ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी। नियुक्ति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं चली, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कि वह सिद्धू के साथ तभी चलेंगे जब वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। तमाम विरोध के बावजूद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया।

पार्टी ने पंजाब के तीनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। सबसे बड़े मालवा क्षेत्र से दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें एक हिंदू सवर्ण वर्ग से और दूसरा सिख चेहरा है। सवर्ण वर्ग से फरीदकोट प्लानिंग बोर्ड के टकसाली कांग्रेसी पवन गोयल और सिख वर्ग से फतेहगढ़ साहिब से दूसरी बार विधायक बने कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नागरा सिक्कम, नगालैंड और त्रिपुरा के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी थे। उन्हें प्रभारी पद से हटा दिया गया है।

युवा कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह डैनी को अनुसूचित जाति वर्ग से माझा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। डैनी अमृतसर जिले के जंडियाला से विधायक भी हैं। उन्हें पिछली बार राहुल गांधी के कोटे से विधानसभा का टिकट मिला था। पिछड़ा वर्ग को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। इस वर्ग की शिकायत थी कि उसे न तो सत्ता में और न ही संगठन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष बने संगत सिंह गिलजियां उड़मुड़ के विधायक हैं।

भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत, कांग्रेस में बने प्रदेश अध्यक्ष पेज>>4

ईडी की जांच

न्यूजक्लिक पोर्टल के विदेशी निवेश में मिला चीन कनेक्शन

कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना की प्रचार शाखा से जुड़ा रहा है मुख्य निवेशक नेविले राय सिंघम,

नई दिल्ली, एएनआइः मीडिया पोर्टल पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनीलांड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि कंपनी ने न्यूज मीडिया कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) मानकों का उल्लंघन कर शेयरों की कृत्रिम तरीके से कीमतें बढ़ाकर 9.59 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हासिल किया। ईडी सूत्रों ने बताया कि चीन निवासी विदेशी नागरिक नेविले राय सिंघम ने मैसर्स वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए के जरिये कंपनी में पैसा लगाया था।

सरकार ने सितंबर, 2019 में डिजिटल न्यूज में सरकारी मंजूरी के बाद 26 फीसद एफडीआइ की घोषणा की थी। इससे ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को इसमें कमी लाने के लिए कहा था। मानकों के मुताबिक, ऐसी कंपनी का सीईओ भारतीय नागरिक होना चाहिए और साल में 60 दिन से ज्यादा काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों की सुरक्षा मंजूरी भी जरूरी है। सूत्रों ने जांच के हवाले से बताया कि 2018 से 2021 के बीच न्यूजक्लिक को विदेश से मिले 28.46 करोड़ रुपयों का मुख्य स्रोत सिंघम ही है। वह कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) की प्रचार शाखा के साथ भी जुड़ा था। ईडी की जांच संदिग्ध धन, संदिग्ध चरित्र और चीन कनेक्शन की बात करती है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक एफआइआर दर्ज की थी और इसके आधार पर ही ईडी ने इस साल फरवरी में न्यूजक्लिक के परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने एफडीआइ की 26 फीसद सीमा से बचने के लिए शेयरों की कीमतों को जबर्दस्त तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित करके (10 रुपये के शेयर पर 11,510 रुपये प्रीमियम) निवेश हासिल किया था।



नेविले राय सिंघम। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

एक्टिविस्ट, नेता और विदेशी ताकतें गिरोह बनाकर सरकार को कर रहीं बदनाम : भाजपा

नई दिल्ली : न्यूजक्लिक पर सरकार को बदनाम करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कुछ नेताओं राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के अंदर टूलकिट चलाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। मीडिया की चादर ओढ़कर पोर्टल चलाने वाले यह कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिनके साथ कुछ विदेशी ताकतें हैं और देश के कुछ मुख्यधारा के नेता भी हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है। पात्रा ने कहा, पूरी दुनिया में जब हमारी वैक्सीन नीति की सराहना हो रही है, ऐसे में देश और वैक्सीन नीति को कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनमें कुछ संस्थाएं और विदेशी पोर्टल भी शामिल हैं। (पेज-3)

केरल ने बढ़ाई चिंता, करीब 40 फीसद नए केस यहीं से

नई दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर केरल और महाराष्ट्र को छोड़कर आमतौर पर पूरे देश में लगभग खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 10 हजार के आसपास नए मामले मिल रहे हैं, लेकिन उनमें स्थिरता बनी हुई है। सबसे चिंताजनक स्थिति केरल में बनी हुई है। यहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल में सर्वाधिक नए मामले पाए जा रहे हैं। (पेज-6)

खेल गांव पहुंचा भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल

टोक्यो : ओलिंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए रविवार सुबह टोक्यो पहुंचा। हवाई अड्डे पर कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद उन्होंने खेल गांव में प्रवेश किया। भारत के पहले जत्थे में 88 सदस्य शामिल हैं। इस बीच निशानेबाज और मुक्केबाज क्रोएशिया और इटली से जापान की राजधानी पहुंचे। (पेज-12)

जागरण विशेष

कूनो में चीते बसाने से पहले जानवरों का टीकाकरण



ग्वालियर : देश से 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। उससे पहले कूनो के आसपास के 48 गांवों के पालतू पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। (पेज-5)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

मोदी सरकार के चलते पाक एफएटीए की ग्रे लिस्ट में

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा, नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिशों से ही पाकिस्तान एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। संसद के मानसून सत्र से पूर्व सरकार की विदेश नीति पर भाजपा नेताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब चीन के दबाव में नहीं आएगा।

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

'भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के विकल्प खुले'

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ गठजोड़ से परहेज नहीं करने का संकेत दिया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है। भाजपा के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अन्य राजनीतिक दलों से गठबंधन को लेकर हमारे विकल्प खुले हैं।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

'लिव इन में रहने वाले शादीशुदा कर्मी की बर्खास्तगी अनुचित'

प्रयागराज : शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुचित करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस गलती के लिए यह कठोर दंड है, इसके लिए छोटा दंड दिया जा सकता है। कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्तगी का आदेश रद करते हुए बकाया वेतन के बगैर उसे बहाल कर दिया है। साथ ही विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए छूट दी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

सरकार और श्रमिक यूनियन के बीच अब हर सप्ताह संवाद

नई दिल्ली : मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मैन्यूफैक्चरिंग को गति प्रदान करने के लिए सरकार और श्रमिक यूनियनें अब लगातार संवाद करेंगी। इससे ना केवल कारोबार के अनुकूल औद्योगिक माहौल तैयार हो सकेगा बल्कि उत्पादन में आने वाले व्यवधान को दूर किया जा सकेगा। इस दिशा में नए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर शुक्रवार को श्रमिक यूनियन से सीधा संवाद करने का फैसला किया है।

मनी लांड्रिंग मामले में देशमुख के दो आवासों पर ईडी की छापेमारी

नागपुर : मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के नागपुर जिले में स्थित दो आवासों पर छापेमारी की। ईडी की दो अलग अलग टीमों ने सुबह करीब छह बजे छापेमारी की शुरुआत की। एक अधिकारी ने बताया कि देशमुख के वाडविहीरा गांव स्थित पैतृक आवास में तलाशी दोपहर 12 बजे के आसपास पूरी हो गई। वहीं, कटोल शहर में स्थित परिसर पर तलाशी चल रही है। (पेज-3)

संयुक्त किसान मोर्चा को संसद मार्च की नहीं मिली अनुमति

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा को मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया है। रविवार को सिंघु बार्डर के निकट एक रिसोर्ट में पुलिस अधिकारियों और किसान मोर्चा के नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बैठक हुई। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकाल का हवाला देते हुए मोर्चा को यमुना पार के किसी अन्य जगह पर धरना देने को कहा है। दूसरी तरह, किसान संगठन संसद मार्च की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। (पेज-5)

39 लोकल ट्रेनों को पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है उत्तर रेलवे ने। ये ट्रेनें कोरोना संक्रमण की वजह से निरस्त की गई थीं। इनमें से कई ट्रेनें एनसीआर के शहरों में चलेंगी। फिलहाल इन सभी को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 जुलाई, 2021

अधिवक्ता पैनल पर आसान नहीं सरकार की राह

टकराव ▶ राजनिवास से दिल्ली सरकार के पैनल को मंजूरी मिलने की संभावना नहीं के बराबर

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

उपराज्यपाल के बार-बार कहने पर भी केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दिल्ली पुलिस के पैनल को दरकिनार कर अपने ही अधिवक्ता पैनल पर मुहर भले लगा दी हो, लेकिन इस प्रकरण में दिल्ली सरकार की राह इतनी आसान भी नहीं है। राजनिवास से दिल्ली सरकार के इस निर्णय को मंजूरी मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच आगे तनाव बढ़ना भी तय है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो दिल्ली सरकार का निर्णय कहीं न कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसी के चलते सरकार शुरू से ही इस आंदोलन का समर्थन करती रही है और हर कदम पर कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के साथ भी खड़ी रही है। दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता पैनल का विरोध करके भी वह एक बार फिर यह संदेश देने में कामयाब रही ही है कि वह केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन नहीं करती और इनका विरोध करने वालों के साथ है।

दूसरी तरफ, राजनिवास की नजर में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा, राष्ट्रध्वज का अनादर, कानून के शासन का उल्लंघन और ऐतिहासिक लाल किले में तोड़फोड़ असामान्य मामला है। राजनिवास की निगाह में पूर्व निर्धारित एजेंडे और निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों ने 26 जनवरी को जानबूझकर मीडिया की उपस्थिति में ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार करने के उद्देश्य से किए गए थे। यही वजह है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विगत एक जुलाई को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ हुए वर्चुअल संवाद में भी यह स्पष्ट किया था कि दिल्ली पुलिस शुरू से इस प्रकरण में काम और जांच कर रही है। लिहाजा कोर्ट में इस बाबत पैरवी करने के लिए भी वह अपने ही हिसाब से लोक अभियोजकों की नियुक्ति करना चाहती है। इसलिए उसके पैनल को स्वीकृति दे देनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से किसानों का विरोध नहीं है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। बाद में एलजी ने इन सभी तर्कों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

जानकार बताते हैं कि कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता पैनल को ही मंजूरी दे सकते हैं।

राजनिवास और सरकार में बढ़ी तकरार

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

सरकारी कामकाज को लेकर उपराज्यपाल निवास और दिल्ली सरकार के बीच फिर रार बढ़ रही है। अधिकारों को लेकर शांत लड़ाई में चिनगारियां छूट रही हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर जिस तरह माहौल गरमा रहा है, उससे अब विवाद और बढ़ने के आसार हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है, जबकि राजनिवास संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 के आधार पर काम कर रहा है।

विवाद गरमाने की शुरुआत उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली दंगा व किसानों के मामले में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज करने के साथ ही हो गई थी। शनिवार को उस समय विवाद और बढ़ गया, जब दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बंद करें। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पत्र भी उपराज्यपाल को लिखा है। उसमें कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार गत मार्च में संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 के आधार पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर रही है। राज्य सरकार अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को आधार मान रही है। अब यही टकराव की मुख्य वजह बनती जा रही है।

दिल्ली सरकार का दावा: सुप्रीम कोर्ट के चार जुलाई, 2018 के आदेश में उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। संविधान में कहीं भी उपराज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आने वाले विषयों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की सीधे बैठक बुलाएं, निर्णय लें और उन्हें दिशा निर्देश जारी करें। उपराज्यपाल को पुलिस, भूमि और पब्लिक आर्डर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इन तीन विषयों को छोड़कर सरकार चलाने के बाकी सभी विषयों पर उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार काम करेंगे। देश की राजधानी होने के नाते उपराज्यपाल को संविधान में यह वीटो पावर दी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के किसी निर्णय से सहमत नहीं होने की स्थिति में अलग राय व्यक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि उपराज्यपाल को यह अधिकार बेहद चुनिंदा स्थितियों में यदा-कदा बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में यह है प्रविधान : दिल्ली में सरकार का मतलब राज्यपाल होगा। दिल्ली विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इसमें उपराज्यपाल को दिया गया है। दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर उपराज्यपाल से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब सात दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि दिल्ली सरकार को शहर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से सलाह लेनी होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यह विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाएगा।

अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश जामिया में सिपुर्द-ए-खाक



अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष की कवरेज के दौरान जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अंतिम विदाई के मौके पर नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नमाजे जनाजा पढ़ते लोग। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष की कवरेज के दौरान मारे गए फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके जनाजे में बड़ी संख्या में जामिया के छात्र भी शामिल हुए।

मालूम हो कि समाचार एजेंसी रायटर के लिए काम करने वाले दानिश कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबान के हमले की चपेट में आ गए थे। पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली के ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद यहीं से 2007 में पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उनके परिवार में जर्मन मूल की पत्नी और दो बच्चे हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जनसंपर्क अधिकारी अहमद अजीम ने बताया कि कुलपति ने दिवंगत फोटो पत्रकार के परिवार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके शव को जामिया कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत दी थी। दानिश के पिता अख्तर सिद्दीकी जामिया के शिक्षा संकाय के डीन थे। 2018 में उनको विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

एयर इंडिया के विमान से भारत लाया गया शव : दानिश सिद्दीकी का शव एयर इंडिया के विमान से देर शाम भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से शव को उनके जामिया नगर स्थित आवास ले जाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद दानिश के शव को जामिया के स्कूल परिसर में रखा गया, जहां नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में ही सिपुर्द ए खाक कर दिया गया।

न्यूज गैलरी

दिल्ली हाई कोर्ट कोलेजियम ने भेजी न्यायाधीशों की सूची

नई दिल्ली: स्वीकृत पदों से कम क्षमता के साथ काम कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट ने और अधिक न्यायमूर्ति हासिल करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। हाई कोर्ट कोलेजियम ने कई नामों पर लंबे विचार-विमर्श के बाद अधीनस्थ न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट में आठ नामों की सिफारिश की है। हाई कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश सूची में पूनम बंबा, यशवंत कुमार, नीना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप एल मेंदीरत्ता, राजीव मेहरा, स्वर्णकांत शर्मा और सुधीर कुमार जैन का नाम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार कोलेजियम ने गिरीश कठपालिया, धर्मेश शर्मा और दीपक जगोत्रा के नामों पर भी विचार किया, लेकिन व्यापक मूल्यांकन के बाद उन्हें प्रस्तावित नहीं किया। सामान्य तौर पर सर्विस कोटे से नामों को सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार दोनों द्वारा जल्दी मंजूरी मिल जाती है, लेकिन बार के नामों की गहन जांच की जाती है। (जासं)

राजधानी में कांवड़ यात्रा पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी में कोरोना के संबंध में स्थिति अभी पूर्णतः ठीक नहीं है। इसलिए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम से कांवड़ पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। (राब्यू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि में दो नए कोर्स शुरू

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय ने दो नए कोर्स शुरू किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित करने के अवसर पर इग्नू की ओर से यह शुरुआत की गई। आनलाइन माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर इन दोनों कोर्स को लांच किया गया। इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव ने कहा कि आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोर्स के माध्यम से छात्रों को साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। कोर्स में दाखिले के इच्छुक छात्र 31 जुलाई तक इग्नू के दाखिला पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। (वि)

दिल्ली में साढ़े चार माह बाद कोरोना से एक भी मौत नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

51 नए मामले आए और 80 मरीज ठीक हुए

राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 0.07 फीसद रह गई है। इस वजह से कोरोना के नए मामले भी बहुत कम हो गए हैं। रविवार को 51 नए मामले आए और 80 मरीज ठीक हुए। इससे दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 600 से कम हो गई है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। पिछले करीब साढ़े चार माह में यह पहला मौका है जब दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इससे पहले दो मार्च को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना के कहर से मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। इस वजह से तीन मई को दिल्ली में 448 मरीजों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक 14 लाख 35 हजार 529 मामले आए हैं। इनमें से 14 लाख नौ हजार 910 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 25,027 है। मृत्यु दर 1.74 फीसद है। मौजूदा समय में दिल्ली में 592 सक्रिय मरीज हैं।

टैंकर ने कार को मारी टक्कर, तीन की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में जल बोर्ड के टैंकर ने एक कार में जबर्दस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार को काटकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जिसमें सन्नी, परमजीत और परमजीत के चार माह का बेटे निक्कू को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद टैंकर चालक विवेक मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सन्नी और परमजीत नांगलोई में अपने परिवार के साथ रहते थे।

भाजपा व आप का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आप का आरोप, भाजपा नेताओं ने सुंदरलाल बहुगुणा के खिलाफ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल
- भाजपा ने कहा, उत्तराखंड के लोगों पर अभद्र बयानबाजी कर रही है आप

अगले वर्ष होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासत गरमा गई है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने पर्यावरणविद स्व. सुंदरलाल बहुगुणा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जबकि भाजपा का आरोप है कि आप उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ अभद्र बयानबाजी कर रही है।

रविवार सुबह आप मुख्यालय पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर वे सड़क पर बैठकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसे भाजपा राजनीति से जोड़कर देख रही है। भाजपा के एक सांसद ने पर्यावरणविद स्व. बहुगुणा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो माफी योग्य नहीं है।

उधर, दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर उत्तराखंड के वीर सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा मुख्यालय से आप के मुख्यालय की ओर प्रदर्शन करते हुए कूच किया। लेकिन पुलिस ने उन्हें भी कुछ ही दूर पर रोक दिया। ऐसे में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं आ सके।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की धरती वीरों की धरती कहलाती है। यहां हर घर में सैनिक हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह से सैनिकों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया वह न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि शर्मनाक भी है।

नोएडा में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने टेलीकाम विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा में संचालित फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। दस्ते ने दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपित देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआइपी) के जरिये आने वाली काल को सामान्य वाइस काल में बदलकर देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे थे। एटीएस ने मामले में ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है।

आरोपितों ने लंदन के पते पर एक फर्जी कंपनी भी पंजीकृत कराई थी। मौके से लैपटॉप, राउटर, सिम, मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान हरदोई के सदर बाजार निवासी अभय मिश्रा, राजस्थान के झुनझुनू निवासी शम्स ताहिर खान उर्फ तुषार शर्मा के रूप में हुई है। दोनों मौजूदा समय में नोएडा के सेक्टर 151 स्थित जेपी अमन अपार्टमेंट में रह रहे थे।

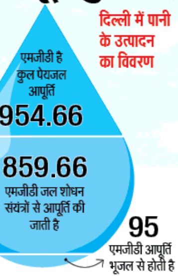
एटीएस के मुताबिक आरोपित आल सल्यूशन सर्विसेज नाम से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर रहे थे। आरोपितों ने वोडाफोन कंपनी से सौ चैनल का पीआरआइ सर्वर ले रखा था। एस्टेरिस्क साफ्टवेयर के जरिये इंटरनेट गेटवे को बाइपास कर विदेशों से आने वाली इंटरनेट कॉल को सामान्य कॉल में बदलकर लोगों की बात कराते थे। लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पर केवल भारतीय नंबर डिस्प्ले होता था। इससे देश को आर्थिक नुकसान के साथ इंटरनेट गेट वे बाइपास होने की वजह से सुरक्षा को खतरा था। आरोपितों ने अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम मार्केट में अपनी साख बनाने के लिए लंदन के पते पर आइपीजीएबी नेटवर्क लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी पंजीकृत कराई थी। इंटरनेट मीडिया में अपनी कंपनी का प्रचार करते थे। एटीएस आरोपितों से यह जानने के प्रयास में जुटी है कि इस धंधे को वह कब से संचालित कर रहे थे। इसमें कितने लोग शामिल हैं। इंटरनेट काल को सामान्य काल में बदलने का तरीका कहां व किससे सीखा। इस धंधे से उन्होंने अब तक कितनी रकम जुटाई है और इस रकम को कहां निवेश किया है। इसके साथ एटीएस यह जानने का प्रयास भी कर रही है कि आरोपितों के कितने व कहां फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं।

यह सामान किया बरामद : एटीएस ने एक लैपटॉप, तीन राउटर, एक डी लिंक स्विच, एडॉप्टर, पावर केबल, इथरनेट पोर्ट, दो टर्मिनेशन बॉक्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वोडाफोन की एसआइपी टंक आउटर केबल, चार मोबाइल, चार सिम, एक एप्पल घड़ी, एक डोंगल, आठ डेबिट कार्ड, पहचान पत्र।

रिकार्ड आपूर्ति से दूर हुई नीर की पीर

हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद जल संकट से परेशान लोगों को न सिर्फ राहत मिली है, बल्कि जल बोर्ड ने भी 955 एमजीडी (मिलियन गैलन डेली) पानी की आपूर्ति कर नया रिकार्ड भी बना दिया है। इससे पहले एक दिन में इतना पानी दिल्ली वालों कभी नहीं मिला है। इधर, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि जल बोर्ड उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम पानी का शोधन कर रहा है। इससे दिल्ली में पेयजल आपूर्ति सामान्य हो गई है।

दिल्ली में पानी के उत्पादन का विवरण



100 एमजीडी पानी कम आपूर्ति करने का आरोप लगाया था दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर

राजधानी के संयंत्रों से पेयजल आपूर्ति की स्थिति

संयंत्र	क्षमता	पेयजल आपूर्ति
वजीराबाद	135	134.30
चंद्रावल	90	95.75
भागीरथी	110	114.23
सोनिया विहार	140	141.62
हैदरपुर	216	235.45
नांगलोई	40	43.61
द्वारका	50	52.48
बवाना	20	20
ओखला	20	22.16

955 एमजीडी पानी की आपूर्ति 24 घंटे में हुई

948.50 एमजीडी पानी की आपूर्ति एक जून को जल बोर्ड ने की थी

935 एमजीडी पानी की औसतन आपूर्ति सामान्य तौर पर की जाती है

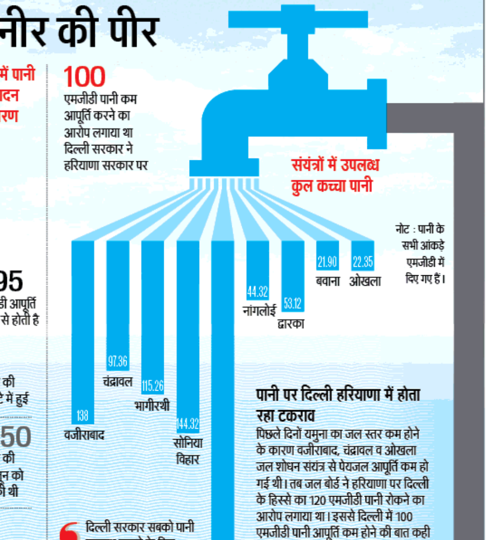
20 एमजीडी पानी की आपूर्ति बढ़ी है



दिल्ली सरकार सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है और जल बोर्ड के इंजीनियर इसके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री दिल्ली

संयंत्रों में उपलब्ध कुल कच्चा पानी



नोट : पानी के सभी आंकड़े एमजीडी में दिए गए हैं।

पानी पर दिल्ली हरियाणा में होता रहा टकराव

पिछले दिनों यमुना का जल स्तर कम होने के कारण वजीराबाद, चंद्रावल व ओखला जल शोधन संयंत्र से पेयजल आपूर्ति कम हो गई थी। तब जल बोर्ड ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का 120 एमजीडी पानी रोकने का आरोप लगाया था। इससे दिल्ली में 100 एमजीडी पानी आपूर्ति कम होने की बात कही गई थी। इस बाबत जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उधर, हरियाणा ने पलटवार करते हुए कहा था कि दिल्ली का एक लोटा पानी भी नहीं रोका गया, बल्कि यमुना में पानी कम होने के बाद हरियाणा के हिस्से का पानी दिल्ली को दिया गया। अब हरियाणा से अधिक पानी छोड़े जाने से अब यमुना का जल स्तर भी बढ़ गया है।

(प्रस्तुति: रणविजय सिंह) जागरण इन्फो

अध्ययन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मेटरोलाजी पुणे के एक नए अध्ययन में आया सामने, सितंबर से दिसंबर 2020 के दौरान दिल्ली से एकत्र किए गए आंकड़ों पर किया गया विश्लेषण

कोरोना को घातक बना रहा है ब्लैक कार्बन उत्सर्जन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मेटरोलाजी द्वारा किए गए नए अध्ययन से पता चलता है कि ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कोरोना वायरस को और घातक बना रहा है। एल्सेवियर जर्नल में प्रकाशित यह शोध सितंबर से दिसंबर 2020 तक दिल्ली से एकत्र किए गए आंकड़ों और 24 घंटे के पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 एवं ब्लैक कार्बन (बीसी) के औसत पर आधारित है।

पीएम 2.5 का मतलब सूक्ष्म कणों से है, जो शरीर में गहराई से प्रवेश करते हैं और फेफड़ों और श्वसन नली में सूजन पैदा करते हैं। इससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय और श्वसन संबंधी समस्याएं होने का खतरा होता है। पीएम 2.5 में ब्लैक कार्बन (जिसे अक्सर कालिख कहा जाता है) में पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। लगभग 40 फीसद बीसी उत्सर्जन खुले बायोमास जलने के लिए जिम्मेदार है, 40 फीसद जीवाश्म ईंधन जलने के लिए और शेष 20 फीसद जैव ईंधन जलने के लिए जिम्मेदार है।

इस अध्ययन के लेखक अदिति राठौड़ और गुफरान बेग ने बताया कि यह केवल ब्लैक कार्बन है जो बायोमास जलने के दौरान उत्सर्जित होता है और वायरस को ले जाता है। वरिष्ठ विज्ञानी और सफर इंडिया के संस्थापक-परियोजना निदेशक बेग ने बताया, नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से दिल्ली सबसे बुरी तरह प्रभावित थी। हालांकि जब न्यूनतम मृत्यु के साथ लगभग छह महीने के बाद स्थिति सामान्य हो रही थी, तो अचानक संक्रमण की संख्या में 10 गुना वृद्धि के साथ एक उलटफेर का सामना करना पड़ा। यह पराली जलने की घटनाओं से मेल खाता था। पराली जलने की घटनाएं थमने के बाद यह संख्या घट गई। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक ब्लैक कार्बन की सांद्रता सीधे तौर पर उस गति से मेल खाती है जिस गति से संक्रमण सर्दी की शुरुआत और पराली जलाने की अवधि के बाद फैलता है।

अध्ययन में कहा गया है कि ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि सीधे तौर पर पराली जलाने से प्रेरित पीएम 2.5 सांद्रता के अतिरिक्त योगदान से संबंधित है, जो पराली जलाने वाले क्षेत्रों से बाहरी रूप से ले जाया जाता है। पहले किए गए एक अन्य अध्ययन में बेग और उनके सहयोगियों ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों में लंबे समय तक उच्च जोखिम के कारण कोविड-19 के संक्रमण की संभावना अधिक होती है।

पीएम 2.5 की सघनता के कारण ही महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में कोविड-19 के मामले अधिक संख्या में सामने आए थे।

एम्स में बढ़ रहीं संक्रमित बच्चों के लिए सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- एम्स ट्रामा सेंटर में तैयार किए जा रहे दो नए आइसीयू वार्ड, खरीदे गए 40 वेंटिलेटर

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एम्स में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके तहत दो अतिरिक्त आइसीयू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे ट्रामा सेंटर में आइसीयू बेड बढ़ जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार बच्चों को ध्यान में रखकर तैयारियों पर अधिक जोर है। इसलिए 40 अत्याधुनिक वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। इनका इस्तेमाल कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज में हो सकेगा।

तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एम्स सहित कई संस्थानों के डाक्टर विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका को गलत बता चुके हैं, लेकिन बच्चों के इलाज की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। एम्स में भी कमेटी गठित की गई है, जिसमें पीडियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष को शामिल किया गया है और बच्चों के इलाज की जरूरतों के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं।

ट्रामा सेंटर के प्रमुख डा. राजेश मल्होत्रा ने कहा कि नर्सों व आइसीयू तकनीशियनों को भी बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए विशेष दक्षता की जरूरत होती है। आक्सीजन आपूर्ति की क्षमता भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। मौजूदा समय में ट्रामा सेंटर में 265 बेड हैं। इनमें 71 आइसीयू बेड शामिल हैं। दो नए आइसीयू वार्ड बढ़ने से ट्रामा सेंटर में 28 आइसीयू बेड बढ़ जाएंगे। इससे आइसीयू बेड बढ़कर 99 हो जाएंगे। वहीं कुल बेड बढ़कर 293 हो जाएंगे। बच्चों के इलाज के लिए ब्रोंकोस्कोपी मशीन भी खरीदी जा रही है। कोरोना के कई मरीजों को डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक अतिरिक्त डायलिसिस मशीन भी खरीदी जा रही है। इससे चार डायलिसिस मशीन उपलब्ध हो जाएंगी।

ट्रामा सेंटर में कोरोना के इलाज के लिए ईसीएमओ (एक्स्ट्राकारपोरेल मेम्ब्रेन आक्सीजनेशन) मशीन भी लगाने की तैयारी चल रही है। डा. राजेश मल्होत्रा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से कई मरीजों के फेफड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं। ईसीएमओ मशीन से आक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से ईसीएमओ मशीन भी खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ निजी अस्पतालों में इसकी सुविधा है। एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां कोरोना के इलाज के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी।

22 जुलाई से दिल्ली एयरपोर्ट का टी2 टर्मिनल फिर शुरू होगा। अभी एयरपोर्ट का सिर्फ टी3 टर्मिनल काम कर रहा है। टी2 टर्मिनल पर परिचालन शुरू होने से रोजाना लगभग 200 फ्लाइट (100 लैंडिंग व 100 टेक आफ) का संचालन होगा।

कोरोना पर एनेक्सी में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे पीएम

- विपक्ष का सवाल, संसद चल रही होगी तो सदन के बाहर संबोधन क्यों

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को पार्लियामेंट एनेक्सी में कोरोना महामारी पर दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। सरकार की इस घोषणा पर एतराज जताते हुए विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि जब संसद सत्र चल रहा होगा तो बाहर संबोधन करने की जरूरत क्या है। यह बेहद अनियमित है और इसका मकसद मानकों की अनदेखी करना है। पार्लियामेंट एनेक्सी संसद भवन परिसर में एक अलग इमारत है।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ-ब्रायन ने कहा, 'संसद के बाहर जाने की जरूरत क्या है। कोई भी संबोधन सदन में होना चाहिए। यह संसद की अनदेखी करने का एक और तरीका है। संसद का मजाक बनाना बंद कीजिए।' उन्होंने आगे कहा, 'सांसद किसी कान्फ्रेंस रूम में प्रधानमंत्री या इस सरकार से महामारी पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहते।'

10 मिनट से कम रहे पीएम : ओ-ब्रायन

ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए दावा किया कि वह बैठक में 10 मिनट से भी कम समय तक रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह मोदी ही हैं, जिन्होंने 2014 से प्रधानमंत्री के तौर पर बैठक में शरीक होने की परंपरा शुरू की।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, उनकी पार्टी का हमेशा से यह रुख रहा है कि जब संसद सत्र चल रहा हो तो सरकार को जो कुछ कहना है वह सदन में कह सकती है।

पवार ने नहीं किया विरोध : ओ-ब्रायन ने दावा किया कि बैठक में मौजूद विपक्षी नेताओं अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, सतीश मिश्रा ने सरकार की इस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी नेताओं में सिर्फ राकांपा प्रमुख शरद पवार ने इस एलान को सिरे से खारिज नहीं किया।

एमपीलैड बहाल करने की मांग : बैठक में कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों ने एमपीलैड फंड्स (स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि) को बहाल करने की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मसले को सरकार के समक्ष उठाएंगे। याद दिला दें कि कोरोना महामारी के चलते एमपीलैड फंड्स को स्थगित कर दिया गया था।



नई दिल्ली में रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता। प्रेट्र

केंद्रीय मंत्री मुरुगन के माता-पिता अभी तक हैं खेतिहर मजदूर

चेन्नई आइएएनएस : बेटा केंद्रीय मंत्री बन चुका है और तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है, फिर भी बुजुर्ग दंपती ने जीवनयापन के लिए खेतों में काम करना बंद नहीं किया है।

यह दंपती और कोई नहीं, हाल ही में मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी, सूचना प्रसारण राज्यमंत्री बनाए गए एल. मुरुगन के माता-पिता लोगनाथन और वरुदाम्माल हैं। दोनों नामक्कल जिले के कोनुर गांव में रह रहे हैं और स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर रहे हैं।

जब मुरुगन के मंत्री बनने की जानकारी मिली तब खेत में कर रहे थे काम : एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री के माता-पिता दलित समुदाय से आते हैं। जिस समय मुरुगन के केंद्रीय मंत्री बनने की जानकारी मिली उस समय दोनों खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटे के मंत्री बनने से उन्हें बेहद खुशी है, लेकिन वे अपना काम करते रहेंगे। वे आज भी अपने गांव में एक छोटे घर में रहते हैं।

मोदी सरकार के चलते पाक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में

विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया जानती है भारत अब चीन के दबाव में नहीं आएगा

- सरकार ने दुनिया को अहसास कराया, आतंकवाद किसी एक देश की नहीं, हर किसी की समस्या

नई दिल्ली, एएनआइ : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिशों से ही पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अब चीन के दबाव में नहीं आएगा।

संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार की विदेश नीति पर भाजपा नेताओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। सरकार की सराहना करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 या जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से आतंकवाद को वैश्विक चिंता का विषय बनाना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रों को यह अहसास कराया कि आतंकवाद किसी एक देश की नहीं, बल्कि हर किसी की समस्या है। बताया जाता है कि जयशंकर ने नेताओं से कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं एफएटीएफ आतंकवाद के लिए फंडिंग पर नियंत्रण रखता है और आतंकवाद का समर्थन करने वाले काले धन से निपटता है। हमारे प्रयासों से ही पाकिस्तान एफएटीएफ की नजर में है और उसे ग्रे सूची में रखा गया है।'



दो टूक : विदेश मंत्री एस. जयशंकर। जागरण आर्काइव

जयशंकर ने कहा कि चीन की तरफ से हमें दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा और भारत ने दोनों ही चुनौतियों का डटकर सामना किया। पहली चुनौती डोकलाम में मिली, जहां चीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी चुनौती लद्दाख में मिली जब चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने की कोशिश की। कोरोना महामारी का सामना करते हुए भी हमने जमीनी स्तर से लेकर कूटनीतिक स्तर पर इस चुनौती का भी मुंहतोड़ जवाब दिया।

एफएटीएफ ने भारत की मनी लांड्रिंग रोधी व्यवस्था की समीक्षा फिर टाली

- आतंकियों को वित्तीय मदद रोकने के उपायों का मूल्यांकन भी अगले साल सितंबर में होने की संभावना
- कोरोना महामारी के चलते दूसरी बार टला कार्यक्रम, मूल रूप से पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में ही होनी थी समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए एफएटीएफ ने भारत की मनी लांड्रिंग रोधी और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा एक बार फिर टाल दी है। अधिकारियों ने बताया कि अब यह समीक्षा अगले साल की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि पेरिस मुख्यालय वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था द्वारा भारती की एंटी-मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग विरोधी व्यवस्था का आकलन मूल रूप से पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में ही किया जाना था, परंतु एफएटीएफ सचिवालय ने कोरोना के चलते इसे इस साल फरवरी तक के लिए टाल दिया था।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरोना महामारी के फिर फैलने के बाद एफएटीएफ के आपसी मूल्यांकन के कार्यक्रम को फरवरी में शुरू नहीं किया जा सका और अब इसके अगले साल सितंबर में शुरू होने की संभावना है। इस मामले के जानकार एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस पुनर्निर्धारित आकलन कार्यक्रम के अनुसार भारत की मनी लांड्रिंग रोधी, आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने से रोकने के लिए किए गए उपायों, प्रासंगिक कानूनी ढांचे और उन उपायों को लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका की तकनीकी मूल्यांकन का काम अगले साल सितंबर में शुरू होगा। उसके बाद एफएटीएफ विशेषज्ञों की एक टीम फरवरी, 2023 में हालात का जायजा लेने के लिए भारत आएगी।

एफएटीएफ की वार्षिक बैठक अक्टूबर, 2023 में होने की उम्मीद है। इसमें भारत द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन होगा। एफएटीएफ विशेषज्ञों द्वारा मौके का दौरा करने के 10 महीने बाद इसकी आपसी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित होगी।



एफएटीएफ की वार्षिक बैठक अक्टूबर, 2023 में होने की उम्मीद है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

क्या है एफएटीएफ

एफएटीएफ मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह अर्थव्यवस्था और वित्तीय लेनदेन में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करती है। एफएटीएफ सदस्य देशों में इस बात की समीक्षा करता है कि वहां एफएटीएफ द्वारा तय मानकों का कितना पालन हो रहा है। एफएटीएओफ ने भारत की मनी लांड्रिंग रोधी और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन 10 साल पहले 2010 में की थी।

मनी लांड्रिंग मामले में देशमुख के दो आवासों पर ईडी की छापेमारी

कसा शिकंजा

- रिश्वत एवं वसूली से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी
- भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से देना पड़ा था त्यागपत्र

नागपुर, प्रेट्र : मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर जिले में दो आवासों पर छापेमारी की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईडी की दो अलग-अलग टीमों ने यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कटोल शहर में देशमुख के आवास और कटोल के समीप वाडविहीरा गांव में उनके पैतृक घर पर छापे मारे। छापेमारी की शुरुआत सुबह करीब छह बजे हुई। अधिकारी ने बताया कि देशमुख के कटोल स्थित परिसर पर तलाशी अभी चल रही है, जबकि वाडविहीरा में तलाशी दोपहर 12 बजे के आसपास पूरी हो गई।

ईडी कथित तौर पर करोड़ों रुपये के रिश्वत एवं वसूली से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इस मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसने इन दोनों और राकांपा नेता के मुंबई तथा नागपुर में स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए देशमुख को समन भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

ईडी ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। हाई कोर्ट ने सीबीआइ को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए रिश्वत के आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। देशमुख ने आरोपों से इन्कार किया है।



महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। जागरण आर्काइव

इस साल नहीं होगा सीयूसेट का आयोजन : यूजीसी

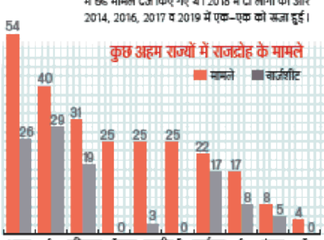
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक में दाखिले के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूसेट) इस साल नहीं होगी। यूजीसी ने रविवार को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पुरानी व्यवस्था के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिला लेने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शनिवार को ही पुराने पैटर्न से दाखिला लेने का एलान कर चुका है। यूजीसी की तरफ से शनिवार को नए शैक्षणिक सत्र के लिए जारी की गई गाइडलाइन में स्नातक में दाखिले के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। इसके बाद कई केंद्रीय विवि ने इस पर यूजीसी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसी क्रम में यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए वे पुरानी व्यवस्था के तहत दाखिले को अंतिम रूप दें।

छह साल में राजद्रोह के सिर्फ छह मामलों में दोष सिद्ध

राजद्रोह को लेकर ब्रिटिश काल में बने कानून के तहत 2014 से 2019 के बीच देश में 326 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 141 मामलों में चार्जशीट दायर हुई और केवल छह मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह को लेकर आइपीसी की धारा 124 का बहुत दुरुपयोग हुआ है। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया है कि विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ब्रिटिश काल में आए इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। (इनपुट : प्रेट्र)

कब कितने मामले?

मंत्रालय के मुताबिक, 2019 में सबसे ज्यादा 93, 2018 में 70, 2017 में 51, 2016 में 16, 2014 में 14 और 2015 में छह मामले दर्ज किए गए थे। 2018 में दो लोगों को और 2014, 2016, 2017 व 2019 में एक-एक को सजा हुई।



कैग ने की पारिवारिक पेंशन योजना को लेकर असम सरकार की खिंचाई

गुवाहाटी, प्रेट्र : भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने अनुकंपा पारिवारिक पेंशन (सीएफपी) योजना को लेकर असम सरकार की खिंचाई की। उसने राज्य सरकार को योजना की समीक्षा की सलाह देते हुए कहा कि यह न सिर्फ कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, बल्कि इससे राजकोष पर हर साल करीब 156.91 करोड़ रुपये का भार बढ़ा है।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत वर्ष 2019 की रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि राज्य सरकार ने सीएफपी मद में अलग से बजट आवंटन के लिए नहीं कहा। सभी व्यय को पेंशन मद में दिखाया जाना नई योजना का उल्लंघन है। मेडिकल आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए या सेवा में रहते हुए मारे गए कर्मियों के योग्य वारिसों की नियुक्त में देरी के कारण वर्ष 2017 से पहले लागू अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति (सीए) योजना का प्रभावी प्रबंधन नहीं किया गया। उसकी विसंगतियों को दूर करने के बजाय राज्य सरकार ने सीएफपी योजना शुरू कर दी।

कैग ने कहा, 'राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (एआइएस) के अधिकारियों को शामिल करने के लिए सीएफपी योजना के लाभों को बढ़ा दिया, जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। राज्य ने केंद्र से विमर्श किए बगैर ऐसा किया।' रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी तथा इससे होने वाली मौतों व संक्रमित मामलों की उच्च दर के कारण आने वाले वर्षों में राजकोष पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

एक्टिविस्ट, नेता और विदेशी ताकतें गिरोह बनाकर सरकार को कर रहीं बदनाम : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा- विदेश से 30 करोड़ रुपये की हुई फंडिंग, पात्रा ने कहा- देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल है न्यूजक्लिक पोर्टल
- पूरी दुनिया में जब हमारी वैक्सीन नीति को सराहा, कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की

विदेशी फंडिंग से चल रहे एक पोर्टल न्यूजक्लिक पर सरकार को बदनाम करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने देश के अंदर भी कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के अंदर टूलकिट चलाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। मीडिया की चादर ओढ़कर पोर्टल चलाने वाले यह कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिनके साथ कुछ विदेशी ताकतें हैं और देश के कुछ मुख्यधारा के नेता भी हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है।

पात्रा ने कहा कि न्यूजक्लिक में कुछ विदेशी ताकतें पैसा भेजती थीं। वेबसाइट से जुडी कंपनी ने 9.59 करोड़ की एफडीआइ को स्वीकार किया है। इनमें मुख्य रूप से विदेश के तीन लोग शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने अलग-अलग एजेंसियों के जरिये 30 करोड़ रुपये भी हासिल किए हैं। पात्रा ने कहा कि पूरी दुनिया में जब हमारी वैक्सीन नीति की सराहना हो रही है, ऐसे में देश और हमारी वैक्सीन नीति को कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनमें कुछ संस्थाएं और विदेशी पोर्टल भी शामिल हैं। यह पूरा षड्यंत्र विदेशी फंडिंग के जरिये रचा जा रहा है।

इसी तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कोर्ट ने भी उसे अच्छा प्रोजेक्ट बताते हुए आगे बढ़ाने के लिए कहा था। इसी तरह कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर गलत बातें की जा रही हैं। पात्रा ने कहा कि यह स्थिति तब है, जब हमारी सरकार किसानों को भगवान मानती है। पात्रा का परोक्ष निशाना कांग्रेस पर था। कुछ दिन पहले पात्रा ने ही कांग्रेस पर टूलकिट का आरोप लगाया था, जिसमें विदेशी मीडिया को साथ लेकर सरकार को घेरने की बात थी।

मालूम हो कि सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की ओर से सरकार को कठघरे में खड़ा करने की जो रणनीति तैयार की गई है उसमें कोरोना और वैक्सीन नीति भी है, जबकि भारत विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश बन गया है।



भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। जागरण आर्काइव

नापाक इरादे

भारत की ओर से निर्मित प्रतिष्ठानों को तबाह करना चाहता है पाकिस्तान, पाक खुफिया एजेंसी ने तालिबान और अपने लड़ाकों को दिया हमले का निर्देश, पिछले दो दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं का किया है निर्माण

अफगानिस्तान में भारतीय परियोजनाओं पर खतरा बढ़ा

नई दिल्ली, एएनआइ : अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए जारी जंग के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने भारत की ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं को निशाने पर ले लिया है। आइएसआइ ने तालिबान और अफगान सेना से लड़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकों को भारत द्वारा तैयार किए गए प्रतिष्ठानों को तबाह करने के निर्देश दिए हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान व अन्य आतंकवादी संगठनों को पाक सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ संचालित कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि अशरफ गनी सरकार से लड़ने के लिए पाकिस्तान के 10 हजार से अधिक लड़ाके अफगानिस्तान पहुंच गए हैं।

अफगानिस्तान की निगरानी करने वाले सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी और तालिबान लड़ाकों को विशेष निर्देश के साथ भारत द्वारा निर्मित संपत्तियों को निशाना बनाने और वहां भारतीय सद्भावना के किसी भी प्रतीक को हटाने के लिए भेजा गया है।

बताते चलें कि पिछले दो दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं का निर्माण किया है। इन्हें लगाने में भारत ने न सिर्फ अरबों डालर खर्च किए हैं, बल्कि इनके साथ उसके रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं।

अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तकरीबन 500 छोटी-बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र को समर्थन देने के तहत भारत ने काबुल में संसद भवन का निर्माण भी किया है। भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था और उसके शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हक्कानी नेटवर्क सहित पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकी समूह वहां भारत के खिलाफ वर्षों से सक्रिय हैं।



असमंजस में भारतीय पक्ष : भारतीय पक्ष इस मुद्दे पर भी असमंजस में है कि क्या उसे काबुल में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। अभी तक कट्टरपंथी इस्लामी समूह द्वारा कोई आश्वासन या संकेत नहीं दिया गया है जिसे भारत के विरोध के रूप में देखा जाए।

काबुल हवाई अड्डे पर नजर : भारतीय एजेंसियां काबुल हवाई अड्डे की स्थिति पर भी करीब से नजर रखे हुए हैं, जो अब बहुत लंबे समय तक अमेरिकी सुरक्षा में नहीं रहने वाला है। बगराम हवाई अड्डे सहित अमेरिकियों के अधीन कई हवाई क्षेत्र तालिबान के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष के कारण खाली हो गए हैं।

कामगारों को बाहर जाने को कहा : नागरिक कार्यों में लगे भारतीय कामगारों को भी बाहर जाने को कहा गया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वैपकास के कुछ अधिकारी बांध परियोजनाओं के लिए वहां रुके हुए थे। भारत ने हाल ही में काबुल शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहतूत बांध परियोजना का एलान किया था।

शिकायतों की छानबीन के लिए जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई : सीवीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने लोकपाल द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रारंभिक जांच के लिए अब तक जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि, लोकपाल को अस्तित्व में आए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाला लोकपाल मार्च 2019 में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार एक जांच निदेशक होगा, जो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने के लिए केंद्र सरकार को जांच निदेशक की नियुक्ति करनी है। सीवीसी ने आरटीआइ के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है, केंद्र सरकार द्वारा जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच करने के लिए आयोग को मामले प्राप्त हो रहे हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी



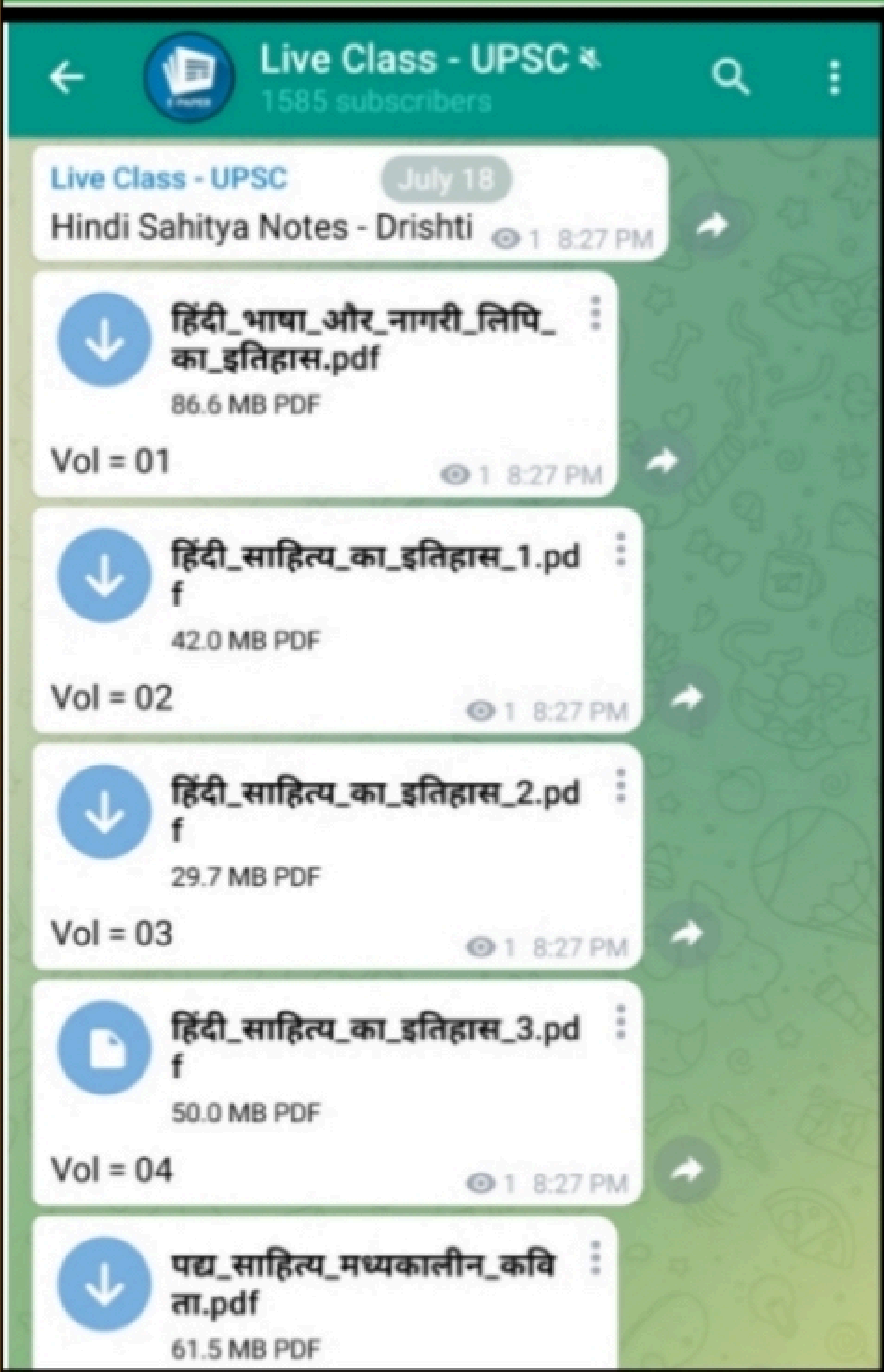
Vikas Divyakriti Sir Hindi literature Full Course

Year - 2020-21
Total - 157 Video lectures + 20 Booklet Pdf

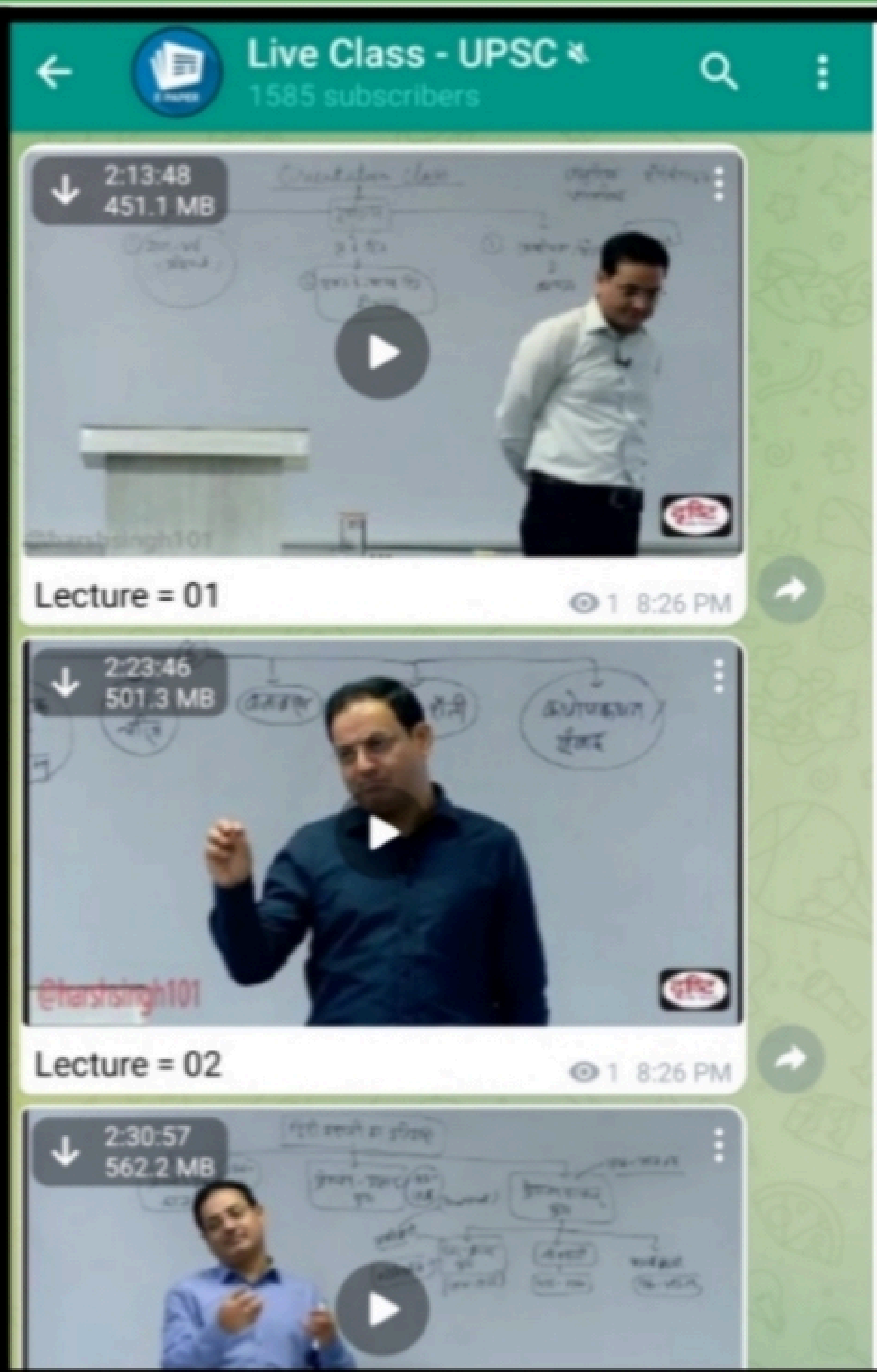
👉(Real Price - 40000/-)
👉We Provide only ₹1499 ✅

दृष्टि The Vision

Contact on Telegram 👉 @prakashstudy24







11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इन भाषाओं में हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमी, पंजाबी और उड़िया शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के विकल्प खुले : प्रियंका

सियासत ▶ कांग्रेस महासचिव ने दिए गठजोड़ से परहेज न करने के संकेत

कहा, पार्टी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभाव, मेरी जिम्मेदारी संगठन मजबूत करना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ से परहेज न करने का संकेत दिया है। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है। भाजपा के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अन्य राजनीतिक दलों से गठबंधन को लेकर हमारे विकल्प खुले हैं।

जैसी परिस्थिति, वैसा निर्णय: प्रियंका प्रदेश कांग्रेस के मीडिया व कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर मीडिया से बातचीत कर रही थीं। उनसे सवाल हुआ कि उप्र के मौजूदा परिदृश्य में बहुकोणीय चुनावी मुकाबले में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए क्या



लखनऊ में रविवार को पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा करती प्रियंका गांधी वाड्रा। एएनआइ

कांग्रेस अन्य दलों से गठबंधन करेगी? इस पर प्रियंका ने कहा, 'इस बारे में हमारा दिमाग खुला हुआ है। हमें गठजोड़ से हिचक नहीं है।' हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को नुकसान हो। आगे जैसी परिस्थितियां होंगी, हम उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे।

प्रियंका के इस बयान को लखनऊ आने से पहले राहुल गांधी के साथ उनकी चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। कांग्रेस महासचिव का यह बयान उस समय आया है, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि बड़ी पार्टियों का स्ट्राइक रेट कम है। इसलिए वह छोटे दलों से गठबंधन के इच्छुक हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया था।

बातचीत के दौरान प्रियंका ने यह स्वीकार किया कि पार्टी के पास आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभाव है। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करने की है ताकि वह उप्र में रहे न रहें, पार्टी आगे बढ़ती रहे। इस दिशा में वह लगातार प्रयासरत हैं। पंचायत स्तर तक कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा तैयार हो चुका है। एक से डेढ़ महीने में पार्टी संगठन को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अपने और राहुल गांधी के उप्र दौरों को भाजपा की ओर से राजनीतिक पर्यटन कहे जाने को उन्होंने मिथ्यारोप बताया। उन्होंने कहा कि यद्यपि कोरोना महामारी के कारण वह डेढ़ साल बाद लखनऊ आई हैं लेकिन प्रदेश में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनका संवाद और संपर्क लगातार जारी रहा। उन्होंने अगस्त या सितंबर में लखनऊ फिर आने के संकेत दिए। कौल हाउस में कुछ कांग्रेसी नेताओं से रविवार को मुलाकात के बाद प्रियंका दोपहर में दिल्ली वापस लौट गईं।

अयोध्या से आगाज, अब ब्राह्मणों को रिझाएगी बसपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, नारा उप्र की फिजां में फिर गूंजने वाला है। बसपा दलित-ब्राह्मण गठजोड़ को 14 साल बाद दोहराने को बेताब है। पार्टी ने चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए रामनगरी अयोध्या को चुना है, जो हिंदुओं खासकर ब्राह्मणों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहीं, अभियान की कमान आजमाए चेहरे महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है। ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम प्रदेश भर में चलाने की तैयारी है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि ब्राह्मण समाज के जिन लोगों ने यूपी में भाजपा की सरकार बनवाई, वे अब पछता रहे हैं। बसपा अब फिर से ब्राह्मण समाज को जागरूक करेगी, क्योंकि उनका हित सिर्फ बसपा सरकार में ही सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मणों को 2007 की तरह बीएसपी से जोड़ने के लिए 23 जुलाई से मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर अभियान अयोध्या से शुरू होगा। इसकी कमान पार्टी महासचिव और सांसद सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है।

मायावती ने उम्मीद जताई कि ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान-सम्मान, सुरक्षा व तरक्की के लिए फिर से बसपा से जुड़कर सूबे में लोकप्रिय सरकार बनवाएंगे।

संघ की सलाह, मतांतरण और लव जिहाद पर तेज हो वार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- समन्वय बैठक में योगी के काम पर संतोष, सरकार की वापसी के लिए गहन मंथन
- जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए किया सतर्क, अल्पमत में न आ जाए हिंदू आबादी

उप्र विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा की फिर सत्ता में वापसी के लिए सेवा के साथ ही राष्ट्रवाद के अस्त्र को भी धार देने की पूरी तैयारी है। समन्वय बैठक में सरकार के कामकाज का आकलन कर संतुष्टि की मुहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठनों ने लगाई है। सेवा को राजनीति का आधार बनाने की इस परंपरा को जारी रखने की सलाह के साथ मतांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सरकार को और कड़ाई से काम करने के लिए कहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी संघ का स्पष्ट संदेश है कि हिंदू अल्पमत में न आने पाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में सरकार, भाजपा और अनुषंगिक संगठनों के साथ हुई। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सह सरकार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डा. दिनेश शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा रखा। बताया कि कोरोना काल में सरकार ने किस तरह गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरण से लेकर अन्य कदम उठाए। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने संगठन के कार्यक्रम-अभियानों की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संघ की ओर से सरकार और संगठन के कामकाज पर संतोष जताया। कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत पर सेवा के कार्य प्रशंसनीय हैं। राजनीति इसी तरह सेवा के आधार पर ही होनी चाहिए। इसे आगे बढ़ाएं। अनुषंगिक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी सरकार के काम की सराहना करते हुए अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही संघ पदाधिकारियों का जोर इस बात पर रहा कि समाज के हित के लिए भाजपा सरकार की सत्ता में वापसी बहुत आवश्यक है।

मिशन-2022 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा भी संघ की रणनीति में है। सीएम योगी द्वारा मतांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए उठाए गए कदमों को सही बताते हुए सलाह दी गई कि इस पर और सख्ती से काम करने की जरूरत है। इससे अच्छा संदेश समाज में जाएगा। प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून भी समन्वय बैठक की चर्चा का हिस्सा बना। संघ का स्पष्ट मत था कि प्रदेश की तरक्की के लिए आबादी पर नियंत्रण अच्छी बात है, लेकिन इस कानून को लागू ऐसे किया जाए कि हिंदू अल्पमत में न आने पाए। बैठक में भाजपा की ओर से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह व प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे।

येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी ढूंढ़ना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पार्टी की रणनीति के अलावा येदियुरप्पा की पसंद का भी रखा जाएगा ध्यान
- नए नेतृत्व पर सहमति बनने के बाद ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे का किया जाएगा एलान



कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। एएनआइ

अब जबकि यह तय हो चुका है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पद छोड़ेंगे तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नया चेहरा ढूंढ़ना। एक ऐसा चेहरा जो भाजपा की बदल रही रणनीति पर भी खरा उतरे और येदियुरप्पा को भी रास आए। ऐसा चेहरा जो भाजपा के सबसे प्रभावी समर्थक वर्ग लिंगायत को थाम कर रख सके और वोक्कालिगा, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण सबको आकर्षित कर सके। यूं तो दौड़ में कई नाम हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कोई ऐसा नाम भी उभर सकता है, जो नेतृत्व परिवर्तन के बाद नैरेटिव बदलने में सक्षम हो। संभावना है कि ऐसे नाम पर कोई सहमति बनने के बाद ही येदियुरप्पा के इस्तीफे की घोषणा होगी।

कर्नाटक की राजनीति में भाजपा, कांग्रेस और जदएस के मतदाता आम तौर पर जातिगत आधार पर बंटे हुए हैं। 1989 में कांग्रेस की ओर से वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद से ही लिंगायत का रुख भाजपा की ओर हो गया। कांग्रेस उसके बाद से कभी भी सबसे प्रभावी समुदाय लिंगायत का विश्वास नहीं जीत पाई। वोक्कालिगा समुदाय के नेता भले ही हर दल में हों, लेकिन जदएस और देवेगौड़ा परिवार ही उसके नेता माने जाते हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, पिछड़ों के बीच खुद के लिए रास्ता तैयार किया। बताया जाता है कि इस्तीफे की परोक्ष पेशकश के साथ ही येदियुरप्पा ने नए मुख्यमंत्री के चुनाव में दखल की भी शर्त रखी है।

रोचक तथ्य यह है कि 2011 में पद से हटने के बाद येदियुरप्पा ने वोक्कालिगा सदानंद गौड़ा को अपनी पसंद बनाया था। वह दौर था जब येदियुरप्पा पार्टी में संभवतः कोई प्रतिस्पर्धी लिंगायत लीडर नहीं चाहते थे। आज के दौर में वह चाहेंगे कि कमान लिंगायत के हाथ में ही रहे। जाहिर तौर पर इसी में उनके पुत्र की भी राजनीतिक भलाई होगी। दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में लीक से हटकर चलने वाली भाजपा की सोच विस्तार पर केंद्रित है। ऐसा विस्तार जिसमें पार्टी किसी एक समुदाय से न बंधी हो। यही कारण है कि पार्टी के अंदर ब्राह्मण नेतृत्व की बातें भी उठ रही हैं। लेकिन एक डर भी है कि कहीं वीरेंद्र पाटिल वाली स्थिति न बन जाए। जाहिर है कि नेतृत्व चुनाव जटिल है।

दूसरी तरफ येदियुरप्पा ने अपने मुख्यमंत्री काल के दो साल पूरे होने पर 26 जुलाई को विधायक दल की बैठक जरूर बुलाई है, लेकिन इसे लेकर असमंजस है कि वह उसी दिन इस्तीफे की घोषणा भी करेंगे। वैसे भी उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री को उन्होंने यह जरूर भरोसा दिलाया है कि वह जब कहेंगे तत्काल घोषणा की जाएगी। लेकिन येदियुरप्पा तिथि, काल पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति भी हैं और इस्तीफा देते वक्त भी वह इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से उनके पुत्र के भविष्य का तार जुड़ा होगा।

मप्र की मंत्री ने कहा, सेल्फी लेने वाले 100 रुपये जमा कराएं

नईदुनिया, इंदौर : मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने सेल्फी लिए जाने से समय खराब होने का तर्क देते हुए उनके साथ हर सेल्फी पर 100 रुपये शुल्क लगाने की बात कही। शनिवार को वह भाजपा के खंडवा जिला कार्यालय पहुंचीं तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। वह इस जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं।

पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेल्फी लेने में वक्त बहुत खराब होता है। इससे हमें कहीं जाने में देरी हो जाती है। संगठनात्मक दृष्टि से यह विचार किया गया है कि मंडल कार्यकारिणी में जो जितनी सेल्फी लेगा, वह 100 रुपये के शुल्क के हिसाब से राशि पार्टी के कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा, ताकि यह राशि संगठन के ही काम आए। इसके साथ ही मंत्री ने बुके (गुलदस्ता) की जगह बुक (किताब) देकर सम्मान करने का भी सुझाव दिया ताकि पुस्तक किसी के काम आ सके। प्रभारी मंत्री ठाकुर की यह नसीहत इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रही है।

एनएचआरसी की तर्ज पर बंगाल सरकार भी तैयार करेगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

पड़ताल

- हिंसा से जुड़े मामलों में राज्य पुलिस सीधे पीड़ितों से करेगी बात
- पुलिस प्रशासन ने कहा-दुष्कर्म, हत्या से जुड़े मामले उसे नहीं मिले हैं

अब बंगाल सरकार भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की तर्ज पर आम लोगों से बात कर चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट तैयार करने पर विचार कर रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में दुष्कर्म, हत्या से जुड़े जिन मामलों का जिक्र किया है, वे उसे नहीं मिले हैं। लिहाजा इसकी सच्चाई जानने के लिए वह सीधे पीड़ितों से बात करेगी। बताते चलें कि चुनाव बाद हिंसा पर एनएचआरसी ने पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की गई है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट के कई बयानों को पुलिस समझ नहीं पा रही है। उदाहरण स्वरूप चुनाव बाद हिंसा में दुष्कर्म के आरोप हैं, लेकिन सरकार को आयोग की रिपोर्ट का संबंधित हिस्सा नहीं मिला है। कई पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 430 पन्नों के 'एनेक्सचर-आइ' को हाथ में मिले बिना इस मुद्दे को समझना मुश्किल है, क्योंकि राज्य में चुनाव के बाद दुष्कर्म की कोई घटना नहीं घटी है। आयोग की रिपोर्ट में लगभग 250 मामलों का विवरण है। शिकायतकर्ताओं की संख्या दो हजार के करीब है। कुछ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि यही वजह है कि वे लोगों की बातें सुनने की सोच रहे हैं। क्योंकि राज्य को जल्द ही अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि जिला पुलिस की रिपोर्ट बयान देने में उपयोगी साबित हो सकती है। बताते चलें कि चुनाव बाद हिंसा की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने पहले ही जिलों से पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने को कहा है।

कानून के जानकारों ने कहा-हाई कोर्ट के लिए राज्य सरकार की रिपोर्ट खास मायने नहीं रखेगी : कानून के जानकारों का कहना है कि दरअसल राज्य सरकार अपने बचाव के लिए यह रिपोर्ट तैयार कर रही है। कोर्ट में अगर जरूरत पड़े तो वह आम लोगों से बात की गई रिपोर्ट का सहारा लेगी। मगर हाई कोर्ट के लिए यह रिपोर्ट खास मायने नहीं रखेगी। अब कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह इसे तवज्जो देता है या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट एनएचआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसी के निर्देश पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

सीआइडी ने पूर्व सुरक्षाकर्मियों और डाक्टरों को किया तलब

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भाजपा विधायक व विस में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके बाडीगार्ड शुभाब्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआइडी ने उनके तत्कालीन सुरक्षाकर्मियों व उस समय कांथी अस्पताल में तैनात डाक्टरों को तलब किया है। उन सब से बात कर सीआइडी शुभाब्रत की मौत के बारे में जानकारी लेगी। इससे पहले पिछले बुधवार और शनिवार को सीआइडी की टीम सुवेंदु के घर पहुंची थी और जहां उनके सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उस बैरक का मुआयना किया था।

इस मामले की जांच करने सीआइडी की टीम चक्रवर्ती के 11 साथियों से पूछताछ कर चुकी है। सीआइडी की टीम गुरुवार को तमलुक में मानिकतला जिला पुलिस लाइन पहुंची थी। पुलिस लाइन में ही शुभाब्रत के साथ उस समय तैनात 11 पुलिस कर्मियों से सीआइडी टीम ने करीब छह घंटे तक पूछताछ की थी।

ममता के दिल्ली सफर के दौरान मुकुल राय भी जाएंगे राजधानी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली सफर के दौरान मुकुल राय भी राजधानी जाएंगे। मुकुल हाल में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे हैं। अपनी पुरानी पार्टी में वापसी के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा होगा। मुकुल ममता के साथ दिल्ली जाएंगे या अलग से, यह अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि दोनों नेताओं के एक साथ दिल्ली में होने को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ममता मुकुल को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती हैं, जबकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ममता से पहले ही मुकुल वहां पहुंच जाएंगे।

तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी 21 जुलाई की रात दिल्ली जा रहे हैं। उसके अगले हफ्ते मुख्यमंत्री दिल्ली जा रही हैं यानी मानसून सत्र के समय तृणमूल का शीर्ष नेतृत्व राजधानी में मौजूद रहेगा।

सूत्रों ने बताया कि तृणमूल भाजपा विरोधी सभी दलों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इसमें मुकुल की भी अहम भूमिका होगी। वे दिल्ली में भाजपा विरोधी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने इस बाबत पिछले दिनों अकाली दल के राज्यसभा सदस्य नरेश गुजराल से मुलाकात की थी। तृणमूल के पक्ष में एक बात यह है कि उसकी कांग्रेस व वामदलों को छोड़कर किसी भी अन्य भाजपा विरोधी दल के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं है। दूसरी तरफ हालिया संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देने के बाद भाजपा विरोधी दलों की भी तृणमूल पर नजर है। ऐसे में तृणमूल संसद में भाजपा विरोधी दलों की अगुआई कर सकती है। तृणमूल संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है।

भाजपा से शुरुआत, कांग्रेस में बने प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- अरुण जेटली के जरिये भाजपा में आए सिद्धू उनसे ही हो गए थे दूर
- 2004 में कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को हराया था



नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल/इंटरनेट मीडिया

पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना राजनीतिक सफर 2004 में शुरू किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जरिये भाजपा में आए सिद्धू ने अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को एक लाख से ज्यादा वोटों से हराया।

सिद्धू ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की इजाजत मिलने के बाद 2007 में उन्होंने अमृतसर से ही उपचुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस नेता सुरिंदर सिंगला को हराया। 2009 में सिद्धू ओपी सोनी को हराकर तीसरी बार संसद पहुंचे। 2014 में भाजपा ने सिद्धू को टिकट नहीं दिया था। बाद में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था, लेकिन सिद्धू राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सरकार बनने पर सिद्धू को स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया। सिद्धू ने 2019 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

विवादों से रहा है सिद्धू का पुराना नाता

सिद्धू के बतौर खिलाड़ी और राजनेता के रूप में विवादों से पुराना नाता रहा है। भाजपा में रहते हुए सिद्धू ने हमेशा ही पार्टी पर अकाली दल से नाता तोड़ने का दबाव बनाया। 2014 में जब बादल परिवार के कहने पर अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ने आए तो सिद्धू अपने राजनीतिक गुरु के साथ कभी भी दिखाई नहीं दिए। 2019 में उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कमेंट किया कि वह पंजाब के कैप्टन हैं लेकिन उनके कैप्टन राहुल गांधी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू ने बठिंडा में चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन पर बादलों के कारोबार में 75-25 की हिस्सेदारी बता कर मोर्चा खोल दिया था। लोकसभा में पांच सीटें हारने के बाद कैप्टन ने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया। सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया गया। इसके विरोध में सिद्धू ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया था। बतौर खिलाड़ी सिद्धू मुहम्मद अजहरूद्दीन की कप्तानी में खेलने से मना कर इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ कर वापस आ गए थे।

माझा ब्रिगेड आया सिद्धू के करीब

प्रदेश में कांग्रेस की कप्तानी बदलने के लिए माझा के मंत्री भी सिद्धू के साथ आ गए। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा अब सिद्धू कैंप में शामिल हो गए हैं। जबकि कैप्टन के धुर विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी पहले से ही सिद्धू के साथ थे। माझा ब्रिगेड पहले सुनील जाखड़ के साथ चल रही थी। वहीं विधायकों में परगट सिंह, कुलबीर जीरा, बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, कुशलदीप सिंह ढिल्लों आदि भी सिद्धू के साथ रहे।

चर्चा

31 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकती है नए अध्यक्ष की घोषणा, आरसीपी दे चुके हैं पद छोड़ने का संकेत, केंद्र में मंत्री बनने पर नीतीश ने उन्हें दी है बधाई

उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं जदयू के नए अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, पटना

संभव है कि इस महीने के आखिर में जदयू को नया अध्यक्ष मिल जाए। 31 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जदयू एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत का हिमायती रहा है। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी नए अध्यक्ष का मनोनयन कर दे। पिछली बार पटना में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह संगठन में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बने थे।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने तारीख तय होने के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के जंतर-मंतर स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 75 सदस्य शामिल होंगे।

...तो अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा : आरसीपी सिंह ने रविवार को दिल्ली में कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। ऐसी चर्चा है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन दिनों वे जिलों का दौरा कर संगठन और सरकार की स्थिति से अवगत हो रहे। उनके इस फीडबैक अभियान की रविवार को मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की है।



उपेंद्र कुशवाहा।



आरसीपी सिंह। फाइल

रविवार को पटना में जदयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसे दिल्ली से वर्चुअल मोड में आरसीपी सिंह और पटना से नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया। आरसीपी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें जिम्मेदारी बेशक दिल्ली की मिली हो, लेकिन संगठन के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार की सोच के अनुरूप उनकी कोशिश संगठन में महिलाओं को 50 फीसद स्थान देने की होगी। नीतीश कुमार के काम की मिसाल पूरे देश में नहीं है।

केंद्र में इस्पात मंत्रालय संभालने के लिए आरसीपी सिंह को बधाई देते हुए नीतीश ने कहा कि आरसीपी के पास काफी अनुभव है। विश्वास है कि वे बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जनता के बीच जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि कहां क्या कमी रह गई है।

जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल करना प्रधानमंत्री की उदारता: दिल्ली में आरसीपी ने कहा कि मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उसके बाद राज्यसभा में पार्टी के नेता के पद को रामनाथ ठाकुर को सौंप दिया था। इसलिए अगर पार्टी चाहेगी तो मैं अपने किसी साथी को अध्यक्ष का पद दे दूंगा।

उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी में आए तो उन्हें संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। पहले ऐसा कहां होता था! आरसीपी ने कहा कि 40 वर्षों का मेरा सार्वजनिक जीवन है। मैंने जो भी काम किया है, ईश्वर की दया से काफी सफलतापूर्वक किया है। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने की बात है तो इस पर पार्टी की सहमति थी। भाजपा के पास खुद संख्या पर्याप्त है। यह तो प्रधानमंत्री की उदारता है कि उन्होंने अपने घटक दल को मंत्रिमंडल में स्थान दिया।

कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार में लोगों की दृढ़ आस्था : जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की उपलब्धियों को अगर हम जनता तक पहुंचा दें तो हमारी पार्टी दोगुनी बड़ी हो जाएगी। नीतीश कुमार के प्रति आज भी लोगों में वही आस्था है। लोगों में यह विश्वास है कि नीतीश कुमार के रहते उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम लोगों के खिलाफ साजिश होती रहेगी, लेकिन हमें साजिश करने वालों से लड़ना है।

ओवैसी की वजह से सरकार बनी तो छोड़ दूंगा उप्र : मुनव्वर राना

जासं, रायबरेली



मुनव्वर राना ने एआइएमआइएम के नेता को बताया वोट कटवा। फाइल/इंटरनेट मीडिया

उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी की वजह से भाजपा की सरकार बनी तो यूपी छोड़कर कोलकाता चला जाऊंगा। यह बात शायर मुनव्वर राना ने रायबरेली में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचने पर मीडिया से कही। पारिवारिक विवाद में उलझे मशहूर शायर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा के एजेंट है और वह हर चुनाव में भाजपा को समर्थन देते हैं। ओवैसी के समर्थन से यूपी में भाजपा की सरकार बनती है तो वह उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने आतंकवादियों पर सरकार की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि एटीएस ने आतंकवादी नहीं, बल्कि प्रेशर कुकर पकड़ा है। मैं भी प्रेशर कुकर खरीद कर लाया था, लेकिन मैंने एटीएस के डर से उसे वापस कर दिया कि कहीं इसमें भी कुछ फिट न कर दिया जाए।

आतंकवाद, धर्मांतरण व जनसंख्या बिल पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे देश का हिंदू इतना कमजोर नहीं है। हिंदू एक संजीदा व बेहतरीन कौम है, जो किसी के बहकावे में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, क्योंकि दो बच्चे तो आतंकवादी कार्रवाई में मार दिए जाएंगे। एक बच्चा कोरोना से मर जाएगा। एक बच्चा सड़क हादसे में चला जाएगा। इसलिए लोग यह चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा हों, ताकि एक बच्चा तो कम से कम परिवार का सहारा बन सके।

3.9 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए गुजरात के कच्छ इलाके में। भूकंप का केंद्र बिंदू भचाऊ से 19 किलोमीटर दूर था। जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण कच्छ तबाह हो गया था।

न्यूज गैलरी

देश की पहली महिला डाक्टर को गूगल की डूडल श्रद्धांजलि

कोलकाता : सर्च इंजन गूगल ने रविवार को देश की पहली महिला चिकित्सक कादंबिनी गांगुली की 160वीं जयंती पर विशेष ग्राफिक वाला डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी। डूडल में पृष्ठभूमि में कलकत्ता मेडिकल कालेज अस्पताल की मुख्य इमारत की तस्वीर के साथ गांगुली का छायाचित्र बनाया गया है। इसे बेंगलुरु के कलाकार ओद्दरिजा ने बनाया है। गांगुली का जन्म 18 जुलाई, 1861 को हुआ था। वह और चंद्रमुखी बासु स्नातक करने वाली भारत की पहली महिलाएं थी। (राब्यू)



कादंबिनी का ग्राफिक्स। इंटरनेट मीडिया

तीर्थपुरोहित करेंगे सीएम के केदारनाथ दौरे का विरोध

रुद्रप्रयाग : तीर्थपुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण के विरोध का फैसला लिया है। वहीं केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थपुरोहितों का धरना जारी है। केदारनाथ में धरना देते हुए आचार्य संजय तिवारी, नवीन शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार में जो भी मुख्यमंत्री केदारनाथ आ रहे हैं, वह महज प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने आ रहे हैं। उनका समस्याओं से लेना-देना नहीं है। (संस)

अब जम्मू एयरपोर्ट से भी रात में उड़ान भरेंगे विमान

जम्मू : जम्मू एयरपोर्ट से 23 जुलाई से रात की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। गो एयर ने दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी रविवार को ट्विटर पर दी। डा. जितेंद्र ने लिखा कि पांच वर्षों से इस दिशा में हो रही मेहनत रंग लाई है। गो एयर इसके लिए राजी हो गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर 23 को गो एयर शाम करीब छह बजे दिल्ली से जम्मू पहुंचेगा। रात आठ बजे जम्मू एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। (राब्यू)

शोपियां में सुरक्षाबलों के घेरे में दो से तीन आतंकी

जम्मू : दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चक सादिक खान क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच रविवार देर रात को मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेरा हुआ है ताकि आतंकी भाग न सकें। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों के घेरे में दो से तीन आतंकी फंसे हुए हैं। यह मुठभेड़ रात को उस समय शुरू हुई जब सुरक्षाबलों को क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान चलाना शुरू किया। इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। (राब्यू)

संयुक्त किसान मोर्चा को संसद मार्च की अनुमति नहीं

पुलिस का इन्कार ▶ किसी अन्य जगह पर धरना देने का विकल्प सुझाया

किसान नेता नहीं हुए तैयार, आज दोबारा होगी बैठक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा को मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया है। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकाल का हवाला देते हुए मोर्चा को यमुना पार के किसी अन्य जगह पर धरना देने को कहा है। दूसरी तरह, किसान संगठन संसद मार्च की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं।

रविवार को सिंघु बार्डर के निकट एक रिसोर्ट में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त जसपाल सिंह, उत्तरी बाहरी जिले के डीसीपी राजीव रंजन सिंह, एसीपी विवेक भगत आदि के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की करीब दो घंटे तक बैठक हुई। मोर्चा के नेता पुलिस के सुझाए विकल्प पर राजी नहीं हुए। इस कारण बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोबारा बैठक होगी। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का, युद्धबीर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल सहित सात प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि संसद भवन पर 22 जुलाई से रोज दो सौ किसान धरना देने पहुंचेंगे, जिन्हें परिचय पत्र जारी किया जाएगा। उनमें उनके आधार कार्ड व मोबाइल नंबर आदि भी होंगे। इसकी सूची मोर्चा के पास रहेगी और उसे पुलिस को भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा।

टीकरी बार्डर पर भी हुई बैठक : टीकरी बार्डर पर भी रविवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व मोर्चा के नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें प्रदर्शनकारियों की तरफ से बूटा सिंह, अमरीक सिंह, गुरप्रीत सिंह मान आदि शामिल हुए। बूटा सिंह ने बताया कि टीकरी बार्डर क्षेत्र में 17 संगठन धरना दे रहे हैं। प्रत्येक से पांच किसान रोज सिंघु बार्डर जाएंगे। सभी को अपना आधार कार्ड और संयुक्त किसान मोर्चा से जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसे गले में पहनकर अनुशासन बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि जहां पर पुलिस रोकेगी, वहीं पर प्रदर्शनकारी रुक जाएंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो वे गिरफ्तारी देंगे। जमानत भी नहीं कराएंगे।

इस बार सतर्कता बरत रही दिल्ली पुलिस

गौरतलब है कि गत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की अनुमति देने का पुलिस का अनुभव अच्छा नहीं रहा और प्रदर्शनकारियों ने जमकर हिंसा व उपद्रव किया था। यहां तक कि ऐतिहासिक लाल किले पर तोड़फोड़ की गई। तिरंगा उतारकर दूसरा झंडा फहरा दिया गया। माना जा रहा है कि पुलिस इस बार पूरी सतर्कता बरत रही है।

पांच सितंबर की महापंचायत में तय होगी 'रणनीति' : नरेश टिकैत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन को गति देते हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सिसौली (मुजफ्फरनगर) में हुई मासिक पंचायत में जल्द ही चुनावी बिगुल फूंकने का एलान कर दिया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि पांच सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कालेज मैदान में होने वाली महापंचायत में उप्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। चौधरी टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, इसपर आखिरी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। वह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेंगे।

शनिवार को सिसौली में हुई मासिक पंचायत में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पांच सितंबर को चुनावी बिगुल फूंकने का एलान किया था। रविवार को दैनिक जागरण से बात करते हुए भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि चुनावी रणनीति पर आखिरी निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पांच सितंबर को जीआइसी में होने वाली महापंचायत में लेंगे।

अब टिकैत व चढ़ूनी के समानांतर आंदोलन चलाएंगे गुणी प्रकाश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- कुरुक्षेत्र के मथाना में बैठक कर बनाएंगे रणनीति
- अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए बनाया जाएगा दबाव

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के लिए भाकियू (मान गुट) ने ताल ठोक दी है। आल इंडिया किसान कोआर्डिनेशन कमेटी से ताल्लुक रखने वाली भारतीय किसान यूनियन (मान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद भूपेंद्र सिंह मान और प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश हैं। गुणी प्रकाश ने सोमवार को कुरुक्षेत्र जिले के मथाना में भाकियू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें किसानों के नाम पर उपद्रव मचाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी तय होगी।

गुणी प्रकाश ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनका राज्य स्तरीय कार्यक्रम मथाना में करने का एलान किया था। तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। गुणी प्रकाश अपनी टीम के साथ लगातार बैठकें कर आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके दो बड़े मुद्दे हैं। पहला तो यह कि किसान संगठनों के नाम पर राज्य में चल रहे हिंसा और उपद्रव को रोका जाए। सरकार ऐसे उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि अराजकता का माहौल खत्म हो सके। दूसरी मांग है आस्ट्रेलिया में गिरफ्तार करनाल जिले के विशाल जूड की रिहाई। खालिस्तानियों के विरोध में विशाल जूड ने आस्ट्रेलिया में भारतीय ध्वज फहराया था, जिस पर उसे गिरफ्तार कर वहां जेल में डाल दिया गया है। गुणी प्रकाश के अनुसार सत्तारूढ़ दल के नेताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आम किसान सीधा-सादा है। उसे इन कृषि कानूनों का फायदा होने वाला है, लेकिन टिकैत और चढ़ूनी सरीखे लोग कुछ राजनीतिक दलों के हाथों में खेलकर किसानों को बदनाम करने पर लगे हैं। कोई किसान यह नहीं चाहेगा कि सरकार के लोगों को बंधक बनाकर पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए और आतंक बढ़ा दिया जाए। गुणी प्रकाश के अनुसार किसान संगठनों के आंदोलन के जरिये लोगों की धार्मिक व राजनीतिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। सिंघु और टीकरी बार्डर अब अपराध का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मथाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर सोमवार को अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी।

कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे राष्ट्रपति

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राष्ट्रपति और देश की सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राम नाथ कोविन्द कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे के लिए अभी तक अधिकारिक शेड्यूल नहीं आया है।

राष्ट्रपति अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति वर्ष 2019 में बिगड़े मौसम के कारण द्रास में कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब वह 22वें कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 27 जुलाई को कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह में भी हिस्सा लेंगे।

दोनों केंद्र शासित प्रदेश में तैयारियां शुरू : राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के तीन दिवसीय दौरे को सुरक्षित बनाने के लिए लद्दाख व कश्मीर में तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जम्वाल ने दौरे तक पुलिस कर्मियों के छुट्टी जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कुछ दिनों में राष्ट्रपति दौरे को लेकर अधिकारिक शेड्यूल आ जाएगा। कश्मीर विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षा समारोह 27 जुलाई को होना है। करीब नौ साल बाद दीक्षा समारोह होने जा रहा है। कश्मीर विश्वविद्यालय का 18 वां दीक्षा समारोह 27 सितंबर 2012 को हुआ था।

यूपी बोर्ड में अब नहीं पढ़ाए जाएंगे टैगोर और डा. राधाकृष्णन, बंगाल में बवाल

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के कोर्स को लेकर सियासी हो हल्ला मच रहा है। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर समेत कई जाने माने रचनाकारों की रचनाएं नहीं हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी हटाए जाने से बंगाल में मुद्दा गरमा गया है। तृणमूल कांग्रेस इसे गुरुदेव का अपमान बताकर इसका जबरदस्त विरोध कर रही। वहीं, यूपी बोर्ड का दावा यही है कि उसने कोई बदलाव नहीं किया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल कहते हैं कि हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट में हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है वही पढ़ाया जाएगा। हम कुछ भी जोड़ घटा नहीं रहे हैं। बाजार में जो किताबें हैं वो बोर्ड से मान्य भी नहीं है।

डा. एस राधाकृष्णन की रचना भी नहीं : बाजार में एनसीआरटी बेस्ड जो किताबें हैं, उनमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति डा. एस राधाकृष्णन की रचना भी नहीं है। टैगोर की कहानी द होम कमिंग पूर्व में 12वीं में पढ़ाई जाती थी। डा. एस राधाकृष्णन का निबंध द वूमेंस एजुकेशन और एएल बाशम का द हेरिटेज आफ इंडिया भी किताबों में नहीं है। आरके नारायणन की कहानी एन एस्ट्रोलाजर्स डे और मुल्क राज आनंद की कहानी द लास्ट चाइल्ड भी विद्यार्थी नहीं पढ़ सकेंगे। बात 10 वीं कक्षा की करें तो किताब से सरोजनी नायडू की कविता द विलेज सांग को भी हटा दिया है। सी राजगोपालाचारी, डब्ल्यूएम रायबर्न तथा आर श्रीनिवासन की रचनाएं भी हटाई गई हैं। पहले कक्षा 12 वीं के सिलेबस में व्याकरण को छोड़कर चार किताबें थीं, लेकिन एनसीआरटी सिलेबस की वजह से सिर्फ दो किताबें फ्लेमिंगो और विस्टा पढ़ाई जाएंगी। द फ्लेमिंगो में अनीस जंग की लास्ट स्प्रिंग, विलियम डगलस की डीप वाटर और लुई फिशर की इंडिगो जो द लाइफ आफ महात्मा गांधी से ली गई हैं। कविता खंड में विद्यार्थी कमला दास, पाब्लो नेरुदा और जान कीट्स की कविताएं पढ़ सकेंगे।

बंगाल में मुद्दा गरमाया : यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी हटाए जाने का मुद्दा बंगाल में गरमाता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसे गुरुदेव का अपमान बताकर इसका जबरदस्त विरोध कर रही है। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने इसपर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे सूबे की संस्कृति का अपमान बताया है। भाजपा को बंगाल की संस्कृति का महत्व पता ही नहीं है। तृणमूल की छात्र इकाई की ओर से गुरुदेव के जोड़ासांको स्थित जन्मस्थल पर इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया।

10वीं की किताब में नए रचनाकार

कक्षा 10 वीं में फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन में अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला, एन. फ्रैंक तथा एंटन चेखोव की रचनाएं हैं। पोएट्री सेक्शन में राबर्ट फ्रास्ट, वाट व्हिटमैन और विलियम बटलर येट्स की रचनाओं को शामिल किया है। सप्लीमेंट्री बुक में रस्किन बांड, राबर्ट आर्थर, एचजी वेल्स तथा के ए अब्बास की रचनाएं हैं।

गंभीर जी समझाइए, नहीं तो नौकरी खा जाऊंगी

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग : मुंबई से त्रियुगीनारायण पहुंची सूफी गायिका समरजीत रंधावा प्रशासन से खफा दिखीं। यही नहीं, इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में वह प्रशासन के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती सुनाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही, ऊखीमठ के एसडीएम को नौकरी से हटवाने की बात कहती भी सुनाई पड़ रही हैं।

सूफी गायिका के रविवार को इंटरनेट मीडिया पर दो वीडियो वारयल हुए। वीडियो त्रियुगीनारायण मंदिर परिसर का मालूम पड़ रहा है। वीडियो में गायिका अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही हैं। कह रही हैं कि वह शूटिंग के लिए यहां आई हैं। हालांकि फोन पर दूसरी तरफ से कौन बात कर रहा और क्या बात कर रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हां, गायिका रुद्रप्रयाग जिले के अधिकारियों की शिकायत करती सुनाई दे रही हैं। बातचीत के क्रम में वह ऊखीमठ के एसडीएम का नाम लेकर उनके व्यवहार पर नाराजगी जाहिर कर रही है, कह रही है कि प्रशासन के पास उनकी परेशानी सुनने तक का समय नहीं है। त्रियुगीनारायण मंदिर परिसर में कुछ स्थानीय लोग स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। गायिका उनका समर्थन करते हुए भी प्रशासन पर निशाना साध रही हैं।

उत्तर भारत में बुधवार तक हो सकती है जमकर बारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 21 जुलाई (बुधवार) और देश के पश्चिमी समुद्र तटीय इलाकों में 23 जुलाई (शुक्रवार) तक जमकर बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है।

विभाग के मुताबिक, 21 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान एवं मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और उससे लगते उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश) में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। सोमवार को दिल्ली और चंडीगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, अगले पांच-छह दिनों के दौरान पश्चिमी समुद्र तट और उससे लगे इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

अब तक 26 प्रतिशत कम हुई बारिश : मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इस बार देशभर में जुलाई में बारिश 26 प्रतिशत कम रही है।

उत्तरकाशी में बादल फटने से दो मकान गिरे, एक लापता

जासं, उत्तरकाशी : उत्तरकाशी जिले में रविवार देर शाम शुरू हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुख्यालय के निकटवर्ती गांव निराकोट और कंकराड़ी में बादल फटने के बाद उफान के साथ आया मलबा घरों में घुस गया। इससे दो मकान ध्वस्त हो गए। जबकि एक मोटर पुल और कई पैदल मार्ग पानी के सैलाब के साथ बह गए, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हालांकि अंधेरा होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी।

बिहार में नदियां फिर उफान पर



रविवार को हुई बारिश के बाद पटना में बिहार विधानसभा परिसर में जमा पानी जागरण

जागरण टीम, पूर्णिया

रविवार को मौसम के अचानक करवट लेने से भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई समेत बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में घोघा चुनने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई जबकि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सात लोगों की जान चली गई और सात अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए।



ट्रेन के चालक की तत्परता से बची बुजुर्ग की जान...

मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर मुंबई-वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन के चालक की तत्परता से एक बुजुर्ग की जान बच गई। दरअसल, कल्याण स्टेशन के पास ट्रैक पार करते समय यह बुजुर्ग ट्रैक पर गिर पड़े। उन्हें गिरा देखकर स्टेशन के मुख्य मार्ग निरीक्षक संतोष कुमार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर ट्रेन के चालक एसके प्रधान ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर बुजुर्ग के प्राण बचा लिए। एएनआइ

मुस्लिम युवक ने लिए फेरे, पुरोहित फंदे पर लटका मिला

जागरण संवाददाता, मैनपुरी : उप्र के मैनपुरी में मेडिकल स्टोर संचालक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला के साथ सात फेरे लिए। युवक के तीन बच्चे और महिला के दो बच्चे हैं। शनिवार शाम को फोटो वायरल होते ही ये शादी चर्चा का विषय बन गई। रविवार तीसरे पहर पुरोहित के अपने कमरे में फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद दवा व्यवसायी परिवार सहित लापता है, जबकि महिला और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। शनिवार शाम को कस्बे में शादी की एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई। फोटो में नजर आ रहे चेहरे स्थानीय ही थे, सो लोगों में चर्चा शुरू हो गई।

'लिव इन में रहने वाले शादीशुदा कर्मी की बर्खास्तगी अनुचित'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुचित करार दिया है। अदालत ने कहा है कि इस गलती के लिए यह कठोर दंड है, इसके लिए छोटा दंड दिया जा सकता है। कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्तगी का आदेश रद करते हुए बकाया वेतन के बगैर उसे बहाल कर दिया है। साथ ही विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए छूट दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने गोरेलाल वर्मा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के आधार पर किसी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि नौकरी से बर्खास्तगी की सजा बहुत कठोर है। यह उत्तर प्रदेश सरकार सेवक आचरण नियमावली 1956 के संदर्भ में अनुचित भी है। कोर्ट ने कहा है कि याची को बर्खास्तगी की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी गोरेलाल पर आरोप है कि वह पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पति-पत्नी की तरह रहने का दोषी पाया गया है। दोनों से तीन बच्चे भी हैं।

जागरण विशेष

कूनो में चीते बसाने से पहले पालतू गाय, भैंस और बकरियों का टीकाकरण

करीब 70 साल पहले विलुप्त हुए वन्यप्राणी को देश में दोबारा लाने के लिए की जा रही है खास तैयारी, मप्र के 48 गांवों में बरती जा रही सतर्कता

हरिओम गौड़ • ग्वालियर

देश-दुनिया में इस समय कोरोना टीकाकरण की चर्चा है, वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से सटे इलाके में अलग ही टीकाकरण चल रहा है। दरअसल, देश से करीब 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीतों को अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर यहां बसाया जाएगा। उससे पहले कूनो की पांच किलोमीटर की परिधि में बसे 48 गांवों के पालतू पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है ताकि इनके कारण कोई बीमारी वन्यजीवों से होते हुए चीतों तक न पहुंच पाए।

जिन गांवों में यह टीकाकरण किया जा रहा है, उनमें 4,144 पालतू पशु हैं। इनमें भैंस, गाय, बकरा और बकरी शामिल हैं। इनका टीकाकरण तीन माह में पूरा होना है। कूनो प्रबंधन के अनुसार अभी तक रक्षा ट्राइओवेक वैक्सीन की 1,692 डोज मिली हैं। इनसे कराहल और विजयपुर ब्लॉक में पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। बता दें कि इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर द्वारा संरक्षित जीवों की सूची में चीते को शामिल किया गया है। जंगली चीतों की सबसे बड़ी आबादी अफ्रीकी देश नामीबिया में निवास करती है।

टीकाकरण इसलिए जरूरी: वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आसपास के पालतू पशुओं का टीकाकरण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ग्रामीणों के पालतू पशु राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भी चरने के लिए जाते हैं, जहां चीतल, हिरण, खरगोश आदि शाकाहारी वन्यजीव हैं। चीता भोजन में इन शाकाहारी वन्यजीवों को ही पसंद करता है। अगर ग्रामीणों के पालतू पशुओं से ऐसे रोग राष्ट्रीय उद्यान के शाकाहारी वन्यजीवों में फैले तो इसका चीते की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए यह वैक्सीनेशन जरूरी है।

यह है कूनो प्रोजेक्ट: कूनो पालपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। सबसे पहले 1981 में वन्य जीवों के रहने के लिए यहां 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 2018 में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मप्र का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। पिछले 35 साल से यहां गुजरात से शेर लाकर बसाने के प्रयास चल रहे थे, लेकिन उनकी शिफ्टिंग में कई प्रकार की राजनीतिक और प्रशासनिक अड़चनें आईं। आखिरकार यहां पर चीतों को बसाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। केंद्र द्वारा विभिन्न स्तरों पर चीतों को बसाने के नजरिए से इस राष्ट्रीय उद्यान का परीक्षण कराया गया। सभी प्रकार की जांच में यह स्थान चीतों के लिए मुफीद पाया गया। इसके बाद ही विशेष तैयारियां की जा रही हैं।



कूनो राष्ट्रीय उद्यान से सटे बागचा गांव में टीकाकरण करते पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग के कर्मचारी • नईदुनिया

नवंबर में नामीबिया से लाए जाएंगे 14 चीते

- कूनो में चीतों के लिए विशेष बाड़े का निर्माण अगस्त तक पूरा करना होगा।
- नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथारिटी (एनटीसीए) चीतों के लिए बनाई जा रही व्यवस्था का निरीक्षण करेगी।
- 14 चीते लाने के लिए जुलाई अंत तक आयात शुल्क जमा कर परमिट लिया जाएगा।
- इसी दौरान पिंजरे और अन्य उपकरण भी खरीदे जाएंगे।
- सितंबर- अक्टूबर में अफ्रीकी देश नामीबिया जाकर चीता लाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
- इस दौरान लाए जाने वाले चीतों का टीकाकरण किया जाएगा।
- नवंबर माह में चीतों को लाया जाएगा।



"शाकाहारी पशुओं को जो रक्षा ट्राइओवेक वैक्सीन लग रही है, वह इनको तीन जानलेवा बीमारियों लंगड़ी बुखार, गलघोंटू, खुरपका या मुंहपका से बचाती है। ये तीनों संक्रमित रोग हैं, जो शाकाहारी जानवरों में बहुत तेजी से फैलते हैं और महामारी बन जाते हैं। वैक्सीनेशन से महामारी नहीं फैलेगी।"

डा. सचिन उपाध्याय, पशु एवं वन्यजीव विशेषज्ञ



"क्षेत्र में पालतू पशुओं के टीकाकरण के साथ मवेशियों को अन्य बीमारियों से बचाने के लिए दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। इसकी पशु चिकित्सक निगरानी कर रहे हैं। जितने टीके मिले थे, वह लगभग पूरे लग चुके हैं। बाकी पशुओं को भी जल्द टीके लग जाएंगे। तीन माह में टीकाकरण का काम पूरा किया जाना है।"

पीके वर्मा, डीएफओ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

18 साल बाद बाल विवाह के पिंजरे से हुई आजाद

रंजन दवे, जोधपुर : महज दो साल की उम्र में ब्याह दी गई संजू को अब 18 साल बाद उस पिंजरे से मुक्ति मिल गई है और वह मनचाही उड़ान भर सकेगी। पारिवारिक न्यायालय ने उसके बाल विवाह को निरस्त कर दिया है।

टोंक जिले के रानोली ग्राम की संजू ने अपने बाल विवाह को निरस्त कराने के लिए सारथी ट्रस्ट से संपर्क किया था। ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डा. कृति भारती ने बताया कि 2003 में महज दो साल की उम्र में संजू का विवाह समाज के दबाव में परिवार के बड़े-बुजुर्गों ने करवा दिया था। इससे मुक्ति की उसमें छटपटाहट थी। उन्होंने टोंक आकर बाल विवाह निरस्त का वाद दायर कराया था। इसके बाद उसके परिवार पर काफी दबाव बनाया गया। इसके चलते संजू के पिता पुरुषोत्तम का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इससे वह एक बार तो टूट गई, लेकिन उन्होंने उसका हौसला बनाए रखा।

केरल ने बढ़ाई चिंता, करीब 40 फीसद केस यहीं से

बढ़ी चिंता ▶ बीते 24 घंटे में पूरे देश में 41,157 और अकेले केरल में 16,148 नए मामले सामने आए

टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ के पार, पिछले एक दिन में लगाई गईं 51 लाख से अधिक डोज

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर केरल और महाराष्ट्र को छोड़कर आमतौर पर पूरे देश में लगभग खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 10 हजार के आसपास नए मामले मिल रहे हैं, लेकिन उनमें स्थिरता बनी हुई है। सबसे चिंताजनक स्थिति केरल में बनी हुई है। यहां मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल में सर्वाधिक नए मामले पाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 41 हजार से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इनमें से लगभग 40 फीसद यानी 16,148 मामले सिर्फ केरल से हैं। इस दौरान राज्य में 114 लोगों की मौत हुई है। इससे ज्यादा 124 मौतें महाराष्ट्र में ही हुई हैं।

माना जाता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत भी केरल से ही हुई थी। सच यह भी है कि देश में महामारी की शुरुआत ही केरल से हुई थी। पिछले साल 30 जनवरी को देश में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला केरल में ही पाया गया था, चीन के वुहान से लौटी मेडिकल की एक छात्रा संक्रमित मिली थी। अभी जो वहां के हालात नजर आ रहे हैं, उससे यह डर लगने लगा है कि कहीं तीसरी लहर की वजह भी केरल ही न बन जाए। यह भी मंथन का विषय बना हुआ है कि केरल ही केंद्र बिंदु क्यों?

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	41,157
कुल सक्रिय मामले	4,22,660
24 घंटे में टीकाकरण	51.01 लाख
कुल टीकाकरण	40 .49 करोड़

देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की 40.49 करोड़ डोज लगाई गईं

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह सात बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 40 .49 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें पिछले 24 घंटे के दौरान लगाई गईं 51.01 लाख डोज भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र की तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41.99 करोड़ डोज मुहैया कराई गई हैं और जल्द ही 15.75 लाख डोज और उपलब्ध करा दी जाएंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2.56 करोड़ डोज बची हुई हैं।



जम्मू-कश्मीर में कोरोना की जांच के लिए युवती का स्वैब सैंपल लेता मेडिकलकर्मी। एएनआइ

रविवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	41,157
कुल मामले	3,11,06,065
सक्रिय मामले	4,22,660
मौतें (24 घंटे में)	518
कुल मौतें	4,13,609
ठीक होने की दर	97.31 फीसद
मृत्यु दर	1.33 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.13 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.08 फीसद
जांचें (शनिवार)	19,36,709
कुल जांचें (शनिवार)	44,39,58,663

रविवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके

राजस्थान	3,20,695
बिहार	1,40,770
महाराष्ट्र	1,17,219
हरियाणा	59,157
छत्तीसगढ़	57,298
जम्मू-कश्मीर	39,744
उत्तराखंड	24,838
झारखंड	22,522
दिल्ली	10,767
उत्तर प्रदेश	6,173

यात्रा प्रतिबंधों के कारण इटली नहीं लौट पा रहे भारतीय छात्र

- पढ़ाई हो रही प्रभावित, निवास परमिट में भी आ सकती है अड़चन
- परमिट के अनुसार छह महीने से अधिक समय तक इटली से बाहर नहीं रह सकते

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूरोपीय देशों में यात्रा प्रतिबंध लागू होने के कारण इटली के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के सामने परेशानियां पैदा हो गई हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान परिवार के साथ रहने अथवा किसी अपने की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वे स्वदेश तो लौट आए, लेकिन अब वापस विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं।

पिछले साल कोविड की पहली लहर की विभीषिका को याद करते हुए कई भारतीय छात्र अपने घरों को लौट आए थे। 28 अप्रैल को इटली ने विमान सेवा पर रोक लगा दी और उनमें से कई छात्र भारत में ही फंस गए, जबकि इटली के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। रोम स्थित सैपिएंजा यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहे जीशान अहमद बहन के कोरोना पीड़ित होने की बात सुनकर घर लौटे थे। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह भी कोरोना की चपेट में आ गए। वह कहते हैं, 'इटली में अब सबकुछ सामान्य हो चुका है और मैं यहां फंसा हुआ हूं।' इसी विश्वविद्यालय से एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे अलीगढ़ निवासी ओवैस आर. खान कहते हैं, 'यूनिवर्सिटी में आनलाइन व आफलाइन परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हम विदेश मंत्रालय से मामले को इटली के समक्ष उठाने का आग्रह कर रहे हैं। अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। मेरे लिए स्थिति पिछले साल जैसी ही है। पिछले साल मैं इटली में फंस गया था और इस साल अपने घर पर फंस हूं।'

विटा-सैल्यूट सैन राफेल यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र निहाल विक्रम सिंह कहते हैं कि समस्या सिर्फ यात्रा में देरी होने की नहीं है, बल्कि निवास परमिट और भारतीय टीकों की मान्यता से भी जुड़ी है। वह कहते हैं, 'निवास परमिट के अनुसार हम छह महीने से अधिक समय तक इटली से बाहर नहीं रह सकते। मैं मेडिकल का छात्र हूं। थ्यूरी की कक्षाएं तो आनलाइन हो जाएंगी, लेकिन यह मेरे लिए काफी नहीं है।' इस बीच नौ जुलाई को इटली में भारत की राजदूत डा. नीना मल्होत्रा ने भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें दूतावास की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत कराया। सभी प्रभावित लोग सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं।

पुलिस की सख्ती, चार बैरियरों से 1253 वाहन लौटाए

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर पुलिस की सख्ती रविवार को भी जारी रही। पुलिस ने बिना दस्तावेजों के दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले 1235 वाहनों को वापस लौटाया। हालांकि, रविवार को बारिश होने के कारण दूसरे राज्यों से कम ही पर्यटकों की आमद हुई। पुलिस ने आशारोड़ी, महाराणा प्रताप चौक, किमाड़ी व कुठाल गेट पर बैरियर लगाए थे।

इस दौरान आशारोड़ी चेकपोस्ट पर दूसरे राज्यों से पहुंचे वाहनों की चेकिंग की। जिन पर्यटकों के पास होटल की बुकिंग, 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट व स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, ऐसे 28 चौपहिया और 50 दोपहिया वाहनों को लौटा दिया। इसके बाद किमाड़ी में चेकिंग के दौरान बिना दस्तावेजों के पहुंचे 250 चौपहिया और 380 दोपहिया, कुठाल गेट पर 125 चौपहिया व 85 दोपहिया वाहनों को लौटाया। मालदेवता, सहस्रधारा व गुच्चुपानी में पुलिस बल तैनात रहा। घूमने आए व्यक्तियों को वापस लौटा दिया।

'दूसरों के मुकाबले भारत कोरोना से अधिक मजबूती से निपट रहा'

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत बेहतर संसाधनों वाले कई अन्य देशों के मुकाबले कोरोना महामारी से कहीं ज्यादा मजबूती से निपट रहा है।

नकवी ने कहा कि महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं और पीएम-केयर्स के तहत देशभर में 1,500 से ज्यादा आक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं। पिछले साल जनवरी में देश में मेडिकल आक्सीजन का उत्पादन 900 मीट्रिक टन प्रतिदिन था जो अब बढ़कर 9,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है।

उत्तर प्रदेश में रेडिको खेतान द्वारा लगाए जा रहे मेडिकल आक्सीजन संयंत्रों में एक (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलासपुर) के उद्घाटन अवसर पर नकवी ने कहा कि 20 क्यूबिक मीटर प्रतिघंटे की क्षमता वाले छह मेडिकल आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना बिलासपुर (रामपुर), बिल्हौर (कानपुर), भगवंतपुर (प्रयागराज), महोबा (महोबा), मंझनपुर (कौशाम्बी) और मानिकपुर (चित्रकूट) में की जा रही है।



मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की दलील। फाइल

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बेहतर सुविधाओं और संसाधनों के साथ-साथ समाज द्वारा बरती गई एहतियात और आत्मसंयम से देश कोरोना से मुक्त हो सकता है। नकवी ने कहा कि जब पिछले साल देश में कोरोना की पहली लहर आई थी तो महामारी से निपटने के लिए संसाधनों का अभाव था, लेकिन एक साल के अंदर देश वेंटीलेटर्स, दवाओं, पीपीई किट, एन-95 मास्क, कोरोना की टेस्टिंग लैब, आइसीयू बेड्स, कोरोना के अस्पतालों और मेडिकल आक्सीजन इत्यादि के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है।

कोरोना काल में भी हिंदी पढ़ने भारत को आकुल दुनिया

प्रभजोत कौर, आगरा : भारत की सबसे सरल, सहज और सुगम भाषा है हिंदी। ये हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति का सेतु है। इसी हिंदी भाषा को सीखने-पढ़ने के लिए पूरी दुनिया व्याकुल रही है। कोरोना काल में जब पूरे संसार की तमाम गतिविधियां प्रभावित हैं, उस दौर में भी हिंदी का ककहरा सीखने के लिए विश्व के तमाम देशों के युवा भारत आने को आकुल हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चेतना और संस्कृति का प्रसार करने वाले केंद्रीय हिंदी संस्थान में 30 देशों के 110 विदेशी छात्रों के आवेदन आए हैं। ये पहला मौका है,जब 30 देशों से आवेदन आए हैं, इससे पहले अधिकतम देश 28 ही रहे हैं। नए देश सेंट्रल अमेरिका के बताए जा रहे हैं। संस्थान में विदेशी अभ्यर्थियों के लिए 100 सीटें आरक्षित हैं। हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार जिस गति से हुआ, विदेशी युवाओं में भी हिंदी सीखने की ललक बढ़ती गई। कोरोना काल से पहले के वर्षों में 100 सीटों के सापेक्ष आवेदनों की संख्या 150 तक पहुंचती रही है।

जांच फर्जीवाड़े में बदरीनाथ व पौड़ी के डाक्टरों से पूछताछ

कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़ा

- कुंभ में सेक्टर प्रभारी के तौर पर तैनात थे तीनों चिकित्सक

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआइटी ने बदरीनाथ और पौड़ी के तीन डाक्टरों से पूछताछ की। तीनों ही चिकित्सक कुंभ मेले में सेक्टर प्रभारी के तौर पर तैनात थे। इस मामले में एसआइटी सोमवार के बाद कभी भी गिरफ्तारियां कर सकती है।

हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए कोरोना जांच फर्जीवाड़े में एसआइटी की टीम अभी तक मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत पंत व मल्लिका पंत के साथ ही नलवा लैब हिसार, डाक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली, फर्म व लैब के बीच डीलिंग कराने वाले डीलर मुंबई निवासी अनुदेश गोयल से कई बार पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुंभ में सेक्टर प्रभारी बनाए गए चिकित्सकों से भी पूछताछ की जा रही है। रविवार को चमोली जिले के बदरीनाथ में तैनात एक और पौड़ी में तैनात दो चिकित्सकों से एसआइटी ने पूछताछ की। उनसे सैंपल कलेक्ट करने वालों, लैब के बारे में सवाल किए। उनसे पूछा गया कि उनकी तैनाती कहां पर रही। तैनाती के दौरान उनका प्रमुख काम क्या था। इसके साथ ही कितने व्यक्तियों की जांच प्रतिदिन होती थी, जैसे सवालों के जवाब पूछे गए। एसआइटी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ आरोपितों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सोमवार के बाद कभी भी गिरफ्तारी होनी तय है। वहीं, विवेचनाधिकारी राजेश साह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पड़ताल में अहम जानकारियां मिली हैं। इससे दोषियों के खिलाफ सुबूत जुटाने में मदद मिलेगी और सख्त कार्रवाई हो पाएगी।

नेपाल के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे भारतीय श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : नेपाल के बैतड़ी जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां रणशैनी त्रिपुरा सुंदरी मेले में इस बार भारत के श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना के चलते नेपाल ने भारत से लोगों के प्रवेश पर दो दिन के लिए रोक लगाई गई है। भारत में कार्य कर रहे नेपालियों को भी पुल पर स्थित नेपाल भंसार कार्यालय मे एंटीजन टेस्ट कराना होगा।

नेपाल स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नेपाल के अलावा भारतीयों का भी आस्था का केंद्र है। मंदिर में दो दिवसीय धार्मिक मेला रविवार से शुरू हो गया है। भारत के विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले नेपाली नागरिक भी इस मौके पर मंदिर जाते हैं। कोरोना को देखते हुए मेले में भीड़ अधिक नहीं जुटे इसके लिए नेपाल प्रशासन ने दो दिन प्रवेश पर पाबंदी का निर्णय लिया है। नेपाल के बैतड़ी में कोविड व्यवस्थापन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैतड़ी के सहायक सीडीओ खगेंद्र भारती ने बताया कि रविवार और सोमवार को भारत से मेले में आने वालों पर रोक लगाई गई है।

राष्ट्रीय फलक

कोरोना से बचाव के लिए मैदान में उतरेगी विहिप

राज्य ब्यूरो, फरीदाबाद

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से बचाव के लिए देशभर के एक लाख गांवों और शहरी बस्तियों में जनजागरण अभियान चलाएगी। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद भी करेगी।

विहिप प्रबंध समिति व प्रन्यासी मंडल की दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बैठक का समापन रविवार को हो गया। संकल्प लिया गया कि कोरोना के प्रति जागरूक करने के अतिरिक्त महामारी में पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक बताई जा रही तीसरी लहर से निपटने के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि संकट के समय पर अकेली सरकार ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज महामारी से मुक्ति के लिए कार्य करे।

राष्ट्रीय अभिशाप है मतांतरण, जल्द मिलनी चाहिए मुक्ति : विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मतांतरण पर रोक के लिए 11 राज्यों ने अब तक कानून बनाए हैं, लेकिन यह समस्या राष्ट्रव्यापी है। संयुक्त महामंत्री डाक्टर सुरेंद्र जैन ने इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव भी बैठक में रखा। हैदराबाद के जी सत्यम ने इसका अनुमोदन किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मठ-मंदिर हिंदू समाज की आत्मा : बैठक में देशभर के मठ-मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि मठ-मंदिर न केवल आस्था अपितु चिरंजीवी शक्ति के केंद्र और हिंदू समाज की आत्मा हैं। इन्हें सरकारी नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। समाज को स्वयं इनकी देखरेख व संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए केंद्रीय कानून बनाए ताकि संत और भक्त इनकी धार्मिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं परंपराओं के अनुरूप स्थापित कर सकें। आलोक कुमार का यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। दो दिन चली यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही।

नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ईसाई बन चुके लोग करेंगे घर वापसी

जागरण संवाददाता, गया

बिहार में गया के दुबहल गांव स्थित बाजितपुर के जो लोग मतांतरण कर ईसाई बन गए थे, वे 25 जुलाई की सुबह विधि-विधान के साथ अपनी सनातन संस्कृति में वापस लौट आएंगे। उन्हें अपनी भूल का अहसास हो चुका है कि पूर्वजों की जड़ों से कट जाना उचित नहीं है। 'दैनिक जागरण' ने मतांतरण के मुद्दे पर समाज और प्रशासन का ध्यान लगातार आकृष्ट किया था कि प्रलोभन और अंधविश्वास के शिकंजे में जकड़कर किस तरह मतांतरण का खेल चल रहा है।

रविवार को हिंदू जागरण मंच गयाजी के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी बातें सुनी। उन्हें कहा कि वे परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, अपनी पहचान और संस्कृति को खो देना कतई उचित नहीं है। फैसला उन्हें करना है। इसके बाद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव में निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया। इसमें गांव के ही युवा रहेंगे। समिति खास तौर से अनुसूचित जाति की बस्तियों में मतांतरण के लिए प्रेरित करने वाले मिशनरी के सदस्यों पर नजर रखेगी। ग्रामीणों ने कहा कि बहुत बड़ी भूल हुई है। जो भी ईसाई बने हैं, वे 25 जुलाई को घर वापसी कार्यक्रम में शरीक होकर हिंदुत्व की अपनी पहचान से जुड़ जाएंगे।

देशभर में 100 कथावाचकों को उतारेगा विहिप

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों में मतांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद अनोखी पहल करने जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर में भारतीय सनातन संस्कृति की अलख जगाने और भारतीय संस्कारों का पालन करने की सीख दी जाएगी। इसके लिए देशभर में 100 कथावाचकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

बागपत में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व मतांतरण, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बागपत

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व मतांतरण के मामले में पुलिस ने सात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपित व उसके मां-बाप को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। किशोरी सात माह की गर्भवती है। इसको लेकर पंचायत भी हुई थी। इस दौरान कोतवाली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा।

बागपत कोतवाली क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को साढ़े तीन साल पूर्व संप्रदाय विशेष के युवक शहजाद ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। शहजाद एक बच्ची का पिता है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर शहजाद बेटी से दुष्कर्म करने लगा। शहजाद के साथी समीर और जन्नत ने भी डरा धमका कर बेटी से दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर भी शहजाद ने बेटी से शादी नहीं की। दबाव बनाया तो शहजाद ने छह जुलाई को शादी करने के बहाने बेटी को अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया। आरोप है कि आठ जुलाई को शहजाद के भाई बिलाल और फरमान ने भी बेटी से दुष्कर्म किया। दस जुलाई को बेटी डरी सहमी घर पर पहुंची। 17 जुलाई को हालत बिगड़ने पर उसने पूरी घटना बताई।

जयपुर की महिला का कश्मीर ले जाकर कराया मतांतरण

जागरण संवाददाता, जयपुर : पति की प्राइवेट नौकरी से घर का गुजारा नहीं चल रहा था। परेशानी ज्यादा थी। इस दौरान करीब आए युवक शाहीद ने हमदर्दी दिखाई। वह भी अच्छी कमाई के झांसे में आ गई, लेकिन यह बहुत भारी पड़ा। कश्मीर ले जाकर उसका मतांतरण किया गया। बंधक बनाकर छह लोग दुष्कर्म करते रहे। इस दौरान एक बेटी भी हो गई। एक साल बाद किसी तरह दरिंदों के चंगुल से निकलकर उसने कोर्ट के जरिये मुकदमा दर्ज कराया है। 25 वर्षीय महिला ने कोर्ट में दायर इस्तगासे में अपने साथ हुई अमानवीय यातनाओं की जानकारी दी है। इसके मुताबिक वह पति और पांच साल के बेटे के साथ जयपुर के प्रतापनगर इलाके में किराए के मकान में रहती है। पति प्राइवेट नौकरी करता है।

कल्याण सिंह को बढ़ी सांस की तकलीफ, आक्सीजन थेरेपी दी



लखनऊ के एसजीपीजीआइ में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सौ. सूचना विभाग, उप्र

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शनिवार रात सांस लेने में तकलीफ और पेट फूलने की दिक्कत होने पर आक्सीजन सपोर्ट पर लिया गया। नए संक्रमण व सेप्सिस की आशंका को देखते हुए एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल का उपचार शुरू कर दिया गया है। हालांकि, सेहत नियंत्रण में है। जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार दोपहर पीजीआइ पहुंचकर कल्याण सिंह से मिलकर स्वास्थ्य लाभ के बारे में बातचीत की।

सदन में मतांतरण का मामला उठाएंगे झारखंड के सांसद

- प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद से यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया जा रहा है

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में मतांतरण हमेशा से ही संवेदनशील विषय रहा है। भाजपा जहां इस मसले पर खुलकर अपना विरोध दर्ज कराती रही है वहीं, राज्य के अन्य राजनीतिक दल इस संवेदनशील विषय पर टिप्पणी से परहेज करते रहे हैं। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद से भाजपा इस मसले पर मुखर रही है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी भाजपा सांसदों ने एक बार फिर इस मसले को सदन में उठाने का मन बनाया है। झारखंड के भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने दैनिक जागरण से इस विषय पर अपने विचार साझा किए।

मैंने पिछले सत्र में मतांतरण का मुद्दा संसद में उठाया था। इस सत्र में मैं एक बार फिर इस मुद्दे को उठाऊंगा। जिन लोगों ने मतांतरण करा लिया है, उनके आरक्षण का लाभ स्वत: समाप्त हो जाएगा।
-संजय सेठ, सांसद, रांची

यदि कोई जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण या धर्मांतरण कराता है, तो यह संज्ञेय अपराध है। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इसे संसद में अवश्य उठाऊंगा।
- विद्युत वरण महतो, सांसद, जमशेदपुर

धर्मांतरण एक अत्यंत ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा है। मौका मिलने पर निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहूंगा क्योंकि झारखंड राज्य में भी इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आते रहती हैं।
-विष्णु दयाल राम, सांसद पलामू

मतांतरण गलत प्रवृति है। इस पर हमलोग गंभीर हैं। पूर्णरूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। लालच, दबाव और कुप्रभाव में मतांतरण घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ कतई नहीं मिलना चाहिए।
सुनील कुमार सिंह, सांसद, चतरा

चार महीने में हुई मतांतरितों की घर वापसी

राधाकिशन शर्मा. बिलासपुर (नईदुनिया)



विश्व हिंदू परिषद के कांकेर जिले के अध्यक्ष रामचरण कोर्राम की अगुवाई में गोंड़ व साहू समाज के मतांतरितों ने घर वापसी की। - सौ. विहिप

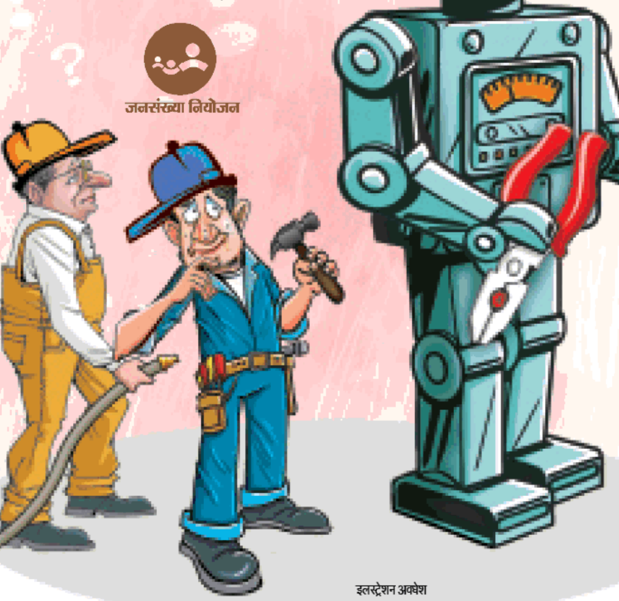
छत्तीसगढ़ में मतांतरित लोगों की घर वापसी के प्रयास में चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। धर्म जागरण मंच के पदाधिकारियों ने जब मतांतरितों से वजह पूछी तो अधिकांश ने यही बताया कि समाज में बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता। समाज प्रमुख दुर्व्यवहार करते हैं। तीज त्योहार के दौरान भी समाज में उपेक्षित किया जाता है। इसी से दुखी होकर चार महीने पहले मतांतरण कर लिया था। मंच के पदाधिकारियों ने समाज प्रमुखों से चर्चा की। आपस में समन्वय बैठाया तो बात बन गई। कोटा ब्लाक के 20 परिवार के 80 लोग घर वापसी को राजी भी हो गए। मंच के पदाधिकारियों ने इसी महीने समाज प्रमुखों के बीच पैर धोकर और गले में तुलसी की माला पहनाकर इन लोगों की घर वापसी कराई है।

बिलासपुर जिले के कोटा ब्लाक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मतांतरण की जानकारी मिली। धर्म जागरण मंच के अलावा प्रदेश भाजपा के मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने मतांतरित आदिवासियों से संपर्क साधना शुरू किया। गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। मतांतरित आदिवासियों का कहना था कि समाज के बीच उनको वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार हैं। परिवार के सदस्यों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अपनों के व्यवहार से दुखी आदिवासी मिशनरियों के संपर्क में आए और मतांतरित हो गए। इस पर मंच के पदाधिकारियों ने आदिवासियों को उनका सम्मान लौटाने और समाज में अपनों के बीच मिल-जुलकर रहने का प्रस्ताव रखा। फिर समाज प्रमुखों से चर्चा की। इसे बाद मतांतरित आदिवासियों की घर वापसी कराई गई।

कोटमीकला के अलावा आसपास के मतांतरित आदिवासी अब मुख्यधारा में लौट आए हैं। धर्म जागरण मंच के पदाधिकारी राजेश मिश्रा ने बताया कि आठ महीने पहले बिलासपुर शहर के जूना, सरकंडा, दयालबंद व आसपास की निचली बस्तियों में रहने वाले 275 लोग मतांतरित हो गए थे। समझाइश के बाद सभी लोगों की घर वापसी कराई गई है।

जनसंख्या नियोजन और नियंत्रण

जानी-मानी अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था प्राइस वाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के अनुसार 2035 तक दुनिया के एक तिहाई रोजगार आटोमेशन, एआइ और नई तकनीक की भेंट चढ़ जाएंगे। इनमें सर्वाधिक ऐसी नौकरियां होंगी जिन्हें अकुशल या अर्धकुशल लोग करते हैं। नौकरियों पर खतरे के इस ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। हम भविष्य के उस चरम की कल्पना कर रहे हैं जब लोगों की नौकरियां व्यापक पैमाने पर खत्म होने लगेंगी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए दुनिया के साथ यहां भी आटोमेशन को प्रोत्साहन देना ही होगा। लिहाजा नौकरियां यहां भी कम होंगी। देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा भारतवंशियों द्वारा भेजे जाने वाले धन का होता है। इस पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। खैर..स्याह कह लीजिए या सुनहरी, लेकिन भविष्य की जब ये तस्वीर अभी से दिखाई देने लगी है तो देश के कई राज्यों में दो बच्चा नीति को लेकर उठाए जा रहे कदमों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वह बेमानी सा लगने लगता है। दो बच्चा नीति पर जनसांख्यिकीविद बंटे हुए हैं। कुछ इसे अच्छा और देशहित में बताते हैं तो कुछ इसे वक्त से पहले का कदम बताने लगते हैं। कुछ लोग इसे कानून बनाकर लागू न करने की जगह लोगों की चेतना पर छोड़ देने की भी बात करते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने वाले भी पीछे नहीं। वे इससे पैदा हो रहे सामाजिक विद्रूप की तस्वीर पेश करते हैं कि एक जागरूक तबका तो स्वचेतना से दो बच्चा नीति का पालन करता है लेकिन एक खास मत के लोग इससे बेपरवाह हैं, जिससे कई क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन पैदा हो चुका है। तमाम तर्कों और नजरिये को अगर देखें तो लगता है कि जनसंख्या का नियंत्रण और नियोजन दोनों अपरिहार्य हो चला है। जिस आबादी के लिए हमारे पास भौतिक और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हों, हमें वहीं संख्या नियत करनी चाहिए और वर्तमान आबादी का नियोजन यानी उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल मुहैया कराकर राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका तय किए जाने की जरूरत है। ऐसे में देश की जनसंख्या के नियंत्रण और नियोजन की जरूरत की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।



इलस्ट्रेशन अवधेश

आटोमेशन की आहट


प्रियंका दीक्षित
असिस्टेंटप्रोफेसर, टाटाइंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुंबई

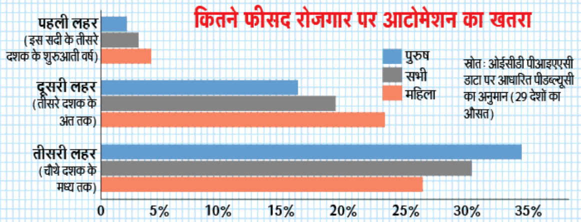
टेक्नोलाजी और आटोमेशन ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इतनी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करना सरल नहीं है। ऐसे में आबादी पर नियंत्रण जरूरी कदम है। यह नियंत्रण ही बेहतर प्रबंधन की कुंजी बन सकता है।

अभी भारत की जनसंख्या 0.99 फीसद की दर से बढ़ रही है, जबकि चीन की जनसंख्या वृद्धि दर केवल 0.39 फीसद है। हाल में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक्सपर्ट ग्रुप और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवक्ताओं ने 'टू चाइल्ड पालिसी' के संदर्भ में अपना मत रखा। जाहिर है, कुछ मत समर्थन में थे तो कुछ विरोध में। भारत की स्थिति का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि समय के साथ-साथ हम सबने आधुनिकता, आटोमेशन और तकनीकीकरण का समावेश हर क्षेत्र में देखा है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षण संस्थान और निर्माण विभाग हो। तकनीकीकरण और आधुनिक मशीनों के आने से हर क्षेत्र में श्रमशक्ति की जरूरत कम हो रही है। उदाहरण के लिए जहां कई मजदूर मिलकर खेत की कटाई, अनाजों की सफाई आदि करते थे, वह आज आधुनिक मशीनों से कम से कम लोगों के साथ संभव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मियों एवं सपोर्ट स्टाफ के स्थान पर रोबोटिक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है।

आटोमेशन के सभी कार्य क्षेत्रों में प्रवेश करने से उत्पादन, गुणवत्ता, क्षमता में बढ़ोतरी एवं समय की बचत हो रही है। इसलिए टेक्नोलाजी और आटोमेशन को अपनाना जरूरी हो गया है। वहीं इसका सीधा दुष्प्रभाव मजदूरों की संख्या पर पड़ा है। इस बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण ने माइग्रेशन को बढ़ावा दिया है, जिसके फलस्वरूप हम तेजी से शहरीकरण होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। एक जिम्मेदार सरकार के लिए अपने देशवासियों को रोजगार दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान सरकार ने इसके लिए बहुत सी अहम योजनाएं और पालिसी अपनाई हैं। 'टू चाइल्ड पालिसी' भी ऐसा ही कदम है, जिस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित करके उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 के अनुसार जहां दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 है, वहीं उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों में टीएफआर 2.9 और 3.2 है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में टीएफआर में लगातार कमी हो रही है। परंतु अभी भी कुछ दंपती दो से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। विशेष तौर पर वे दंपती जिन्होंने सिर्फ लड़कियों को जन्म दिया है। पापुलेशन स्टडीज में प्रकाशित पेपर के अनुसार स्वास्थ्य और उपचार की मांग में अब लड़के-लड़की में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, परंतु 'पुत्र वरीयता' की जड़ें अभी भी गहरी पैठ बनाए हुए हैं। 27 साल पहले पीएनडीटी एक्ट लागू होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाई।

वर्तमान सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं, पर सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें और हर रोजगार में कुछ प्रतिशत लड़कियों के लिए आरक्षित रहें। आधुनिकता, आटोमेशन और उच्च प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करते हुए हम सरकारी योजनाओं और स्कीम में हिस्सा लें जिससे कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सके।

कितने फीसद रोजगार पर आटोमेशन का खतरा

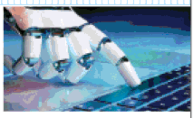


स्रोतः ओईसीडी पीआइएसी डाटा पर आधारित पीडब्ल्यूसी का अनुमान (29 देशों का औसत)

कहां-कहां बढ़े मशीनों के कदम

टेक्नोलाजी के उभार ने लगभग हर क्षेत्र में आटोमेशन को बढ़ावा दिया है। बहुत से काम जिनके लिए पहले अलग-अलग शिफ्ट में कई-कई लोगों की जरूरत होती थी, अब वहां एक मशीन दिन-रात उनका काम करती रह सकती है।

- **होम आटोमेशन** : साफ्टवेयर और टेक्नोलाजी की मदद से घर के कई उपकरणों पर एक कमांड के जरिये नियंत्रण करना संभव हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें बहुत मदद की है।
- **आफिस आटोमेशन** : विभिन्न आफिस में डाटा कलेक्शन से लेकर कई छोटे-बड़े काम आज मशीनों से होने लगे हैं। आज सैकड़ों लोगों का डाटा एक कमांड पर नियंत्रित किया जा सकता है।
- **कस्टमर केयर** : बैंकिंग, टेलीकाम से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां कस्टमर केयर सेवाओं में भी आटोमेशन का इस्तेमाल करने लगी हैं। कई सामान्य सवालों के जवाब अब आटोमेशन के माध्यम से दिए जाने लगे हैं। कस्टमर केयर अधिकारी से बात का विकल्प सबसे आखिरी में दिया जाने लगा है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आटोमेशन ने कई लोगों की जगह ले ली है।



- **कई अन्य क्षेत्रों में भी आटोमेशन**: चिकित्सा, परिवहन से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग एवं कंस्ट्रक्शन तक कई अन्य क्षेत्रों में भी मशीनों के प्रयोग ने इंसानों की जगह ली है।

पुराना है इतिहास

कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिने हैं। कुछ लोगों को समय के साथ रोजगार मिल भी जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, जिन्हें शायद वह रोजगार कभी नहीं मिल पाएगा, जिसमें वे काम कर रहे थे। इसकी वजह है आटोमेशन। वैसे तो दुनिया आटोमेशन की ओर बहुत समय से बढ़ रही है, लेकिन कोरोना काल में यह गति बढ़ गई है। कई जगहों पर उम्मीद से पहले मशीनों ने लोगों का काम संभाल लिया है।

16वीं सदी में शुरुआत



आटोमेशन का इतिहास पांच सदी पुराना है। 1589 में पहली बार विलियम ली नाम के पादरी ने लंबे मोजे (स्टाकिंग) को तैयार करने का मशीनी तरीका ईजाद किया था। हालांकि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनकी इस ईजाद को पेटेंट देने के इन्कार कर दिया था। उनका मानना था कि इससे मोजे बनाने वाले पारंपरिक कारीगरों के हाथ से रोजगार छिन जाएगा। विलियम ली की यह मशीन बहुत प्रभावी तो नहीं रही, लेकिन समय के साथ कई टेक्सटाइल मशीनों के बनने की राह जरूरी खुली।

19वीं सदी में टेक्सटाइल की दुनिया में आईं मशीनें

विलियम ली के तीन सदी बाद 19वीं सदी में टेक्सटाइल की दुनिया में मशीनों की दखल बढ़ी। औद्योगिक क्रांति के बाद



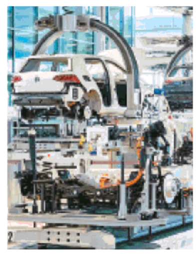
ग्रामीण इलाकों से लोग तेजी से बढ़ते शहरों की ओर पहुंचने लगे थे। भाप से चलने वाली मशीनों से हाथ के मुकाबले उत्पादन कई गुना तेजी से होता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी मशीनीकरण से चुनौती आई। बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा अनाज की जरूरत थी। इसलिए खेती में बीज डालने से लेकर फसल कटाई तक मशीनों का उपयोग बढ़ा।



छिड़ गए थे दंगे : मशीनीकरण को लेकर कामकाजी आबादी की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक नहीं थी। ब्रिटेन में बढ़ते आटोमेशन के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। लोगों ने दंगे किए, मशीनें तोड़ीं और कई उद्योग जला दिए।

कार के पहियों पर दौड़ा आटोमेशन

20वीं सदी के आखिर तक कारों के निर्माण में रोबोट का इस्तेमाल होने लगा था। शुरुआत में कुछ सामान्य और बार-बार किए जाने वाले काम के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। इनसे गुणवत्ता भी सुधरी और उत्पादन की गति भी बढ़ी। 1979 में फिएट ने बहुचर्चित विज्ञापन जारी किया था, जिसकी टैगलाइन थी 'हैंड बिल्ट बाई रोबोट्स' (रोबोट के हाथों तैयार)। कार निर्माण में रोबोट ने सबसे पहले असेंबली लाइन के काम जैसे वेल्डिंग और स्प्रे पेंटिंग में इंसानों की जगह ली थी। टेक्नोलाजी बढ़ने के साथ-साथ रोबोट का इस्तेमाल कई जटिल प्रक्रियाओं में भी होने लगा है।



मशीनों के साथ आगे बढ़ेगा भविष्य

वर्ल्ड इकोनामिक फोरम के क्लास श्वाब का कहना है, 'कोरोना महामारी ने हमें तेजी से एक और औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ा दिया है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल, फिजिकल और बायोलाजिकल क्षेत्र में नई टेक्नोलाजी मनुष्यों को केंद्र में रखकर आगे बढ़े। टेक्नोलाजी से संपूर्ण समाज का भला हो और सभी तक पहुंच सुनिश्चित हो।'

युवा आबादी का लिया जाए लाभ


पूनम मुतरेजा
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली

देश की विशाल आबादी लंबे समय से सवालों के घेरे में है। कई लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी कदम जरूरी मानते हैं। फिलहाल नियंत्रण जितना ही जरूरी है जनसंख्या का नियोजन। हमारी बड़ी आबादी युवा है। दुनियाभर में आटोमेशन के रूप में सामने आ रही चुनौती के बीच युवाओं को विकास का वाहक बनाने की जरूरत है।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत की आबादी में चौथाई हिस्सा 10 से 19 साल की उम्र के लोगों का है। यह बड़ी युवा आबादी आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम है, बशर्ते नीतियों में इस पर ध्यान दिया जाए। आबादी की बेहतरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर किया गया खर्च देश को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। जिस तरह से दुनिया आटोमेशन की ओर बढ़ रही है, उसे देखते हुए इस दिशा में कदम उठाना और भी जरूरी हो गया है। विज्ञान पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, किशोरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर खर्च बढ़ाकर तीन स्तर पर लाभ लिया जा सकता है। पहला लाभ तत्काल मिलेगा, दूसरा लाभ भविष्य में स्वस्थ वयस्क आबादी के रूप में और तीसरा लाभ स्वस्थ अगली पीढ़ी के रूप में मिलेगा। इसी तरह शिक्षा पर किया गया खर्च भी कई गुना होकर समाज को लाभ पहुंचाता है। मौजूदा हालात में जनसंख्या नियंत्रण जितना ही जरूरी जनसंख्या नियोजन है। वैसे भी आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत में आबादी बढ़ने की दर पहले के अनुमान के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हुई है। ऐसे में हमारे पास अपनी जनसांख्यिकी का लाभ लेने का समय कम होता जा रहा है। नीतियों को जल्द से जल्द इस दिशा में मोड़ना होगा, ताकि अपनी युवा आबादी का भरपूर लाभ भारत को मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी आबादी का सही नियोजन करें।

कोरोना के कारण पिछले 18 महीने में करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं। स्कूल-कालेजों के बंद रहने से बच्चों के जीवन और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना काल में डिजिटल डिवाइस तक पहुंच नहीं होने के कारण कई बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। गैर लाभकारी संगठन प्रथम की ओर से जारी एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) वेव-1 में सामने आया कि सरकारी स्कूलों के करीब 43.5 फीसद और निजी स्कूलों के करीब 26 फीसद बच्चों की पहुंच स्मार्टफोन तक नहीं है। नौंवी या इससे ऊपर की कक्षा में सरकारी स्कूलों के करीब 35 फीसद और निजी स्कूलों के 43 फीसद छात्रों को ही वाट्सएप, फोन काल, वीडियो या आनलाइन क्लास के माध्यम से लर्निंग मैटेरियल मिल पाया। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। जहां एक ओर दुनिया तेजी से टेक्नोलाजी और आटोमेशन की ओर बढ़ रही, तो दूसरी ओर लाखों बच्चों का पढ़ाई से दूर रहना चुनौती है।

पिछले साल आई नई शिक्षा नीति में वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पर जोर दिया गया है। कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग को मौजूदा और भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। इन कार्यक्रमों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि युवा भारत को सक्षम बनाया जा सके। युवाओं को जो ज्ञान दिया जाए, वह सामयिक हो और उन्हें ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में टेक्नोलाजी क्रांति को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाए। डिजिटल इंडिया जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के जरिये सरकार क्षमता निर्माण कर सकती है और युवा आबादी को लक्षित करते हुए विशेष पहल कर सकती है।

इस दिशा में शिक्षा बजट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में शिक्षा बजट 93,224 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल 99,300 करोड़ रुपये था। ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रविधान नहीं किया गया है। निसंदेह यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन के मुताबिक, भारत में 18 से 24 साल की 48 फीसद लड़कियां रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़ी नहीं हैं। सामाजिक प्रथाएं इस दिशा में बाधक बनती हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कोरोना काल में करीब एक करोड़ लड़कियों की पढ़ाई बाधित होने का अनुमान है।

जनसंख्या नियोजन के लिहाज से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम जैसी योजनाएं अच्छा प्रयास हैं। व्यवस्थागत खामियों को भी दूर करने की जरूरत है। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर के बीच संबंध स्थापित करना होगा, ताकि रोजगार कर रहे लोगों का प्रतिशत बढ़े। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास करने की जरूरत है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि युवाओं को आत्मविश्वास और कौशल से परिपूर्ण करने के बहुत से लाभ हैं। साथ ही इसमें चूकने से भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

जनमत

हां 5% नहीं 95%

क्या भविष्य में मशीनों द्वारा नौकरियों को छीने जाने वाली तस्वीर देखने के बाद आपको दो बच्चा नीति का विरोध जायज लगता है?

हां 97% नहीं 03%

क्या देश के सामाजिक ताने-बाने को संतुलित रखने के लिए दो बच्चा नीति वाला कानूनी और बाध्यकारी प्रविधान अब जरूरी है?

आपकी आवाज

किसी देश के विकास के लिए जरूरी है कि उसकी जनसंख्या नियंत्रण में रहे। मशीनीकरण ने बड़ी आबादी के समक्ष संकट को और बढ़ा दिया है। पहले जिस काम को 10 व्यक्ति करते थे, आज उसे एक मशीन कर लेती है। मशीनों ने रोजगार के अवसर सीमित कर दिए हैं। ऐसे में दो बच्चे की नीति का विरोध सही नहीं है।
विजय कुमार धानिया

किसी भी सूरत में जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करना उचित नहीं कहा जा सकता है। हमारी आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। जनसंख्या के साथ किसी देश के संसाधन नहीं बढ़ जाते हैं। बात रोजगार की हो या स्वास्थ्य की, बड़ी आबादी के कारण हर मोर्चे पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। मशीनीकरण से संकट और बढ़ रहा है।
शिखा शुक्ला

देश में सामाजिक ताने-बाने के संतुलन के लिए अब जरूरी है कि दो बच्चा नीति वाला कानूनी प्रविधान किया जाए। इसी से अभीष्ट सिद्ध होगा और सामाजिक समरसता आएगी। वर्तमान समय में नीति लाने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की जरूरत है।
गौरीशंकर अंतज

सामाजिक असंतुलन का नया विद्रूप


हरेन्द्र प्रताप, पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद

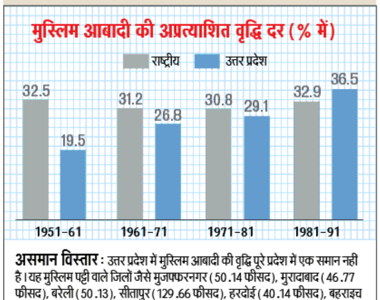
देश में मुस्लिम तबके की आबादी तेजी से बढ़ी है जबकि कई क्षेत्रों में पहले से मौजूद दूसरे मतावलंबियों की आबादी घटती गई। ज्यादा जागरूक होने के चलते अन्य मतों के लोग स्वतः प्रेरित दो बच्चा नीति का पालन करते रहे, जबकि मुस्लिम घुसपैठिए अपनी आबादी तेजी से बढ़ाते रहे।

देश मुस्लिम षड्यंत्रकारियों द्वारा उत्तर भारत में एक मुस्लिम पट्टी/गलियारा तैयार करने की योजना है ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को आपस में जोड़ा जा सके। यह गलियारा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान से मिलेगा। इस गलियारे में मुस्लिम आबादी बढ़ाने हेतु घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। बांग्लादेश से असम में आए मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ वहां चले जन आंदोलन के बाद इस्लामिक षड्यंत्रकारियों ने उन्हें बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भेजना शुरू किया। बंगाल में शासकीय एवं भाषायी अनुकूलता के कारण उनका विरोध न होना तो समझ में आता है, पर उत्तर प्रदेश में इस षड्यंत्र की अनदेखी क्यों हुई, यह समझ से परे है।

कुछ वर्ष पहले जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर कैराना से हिंदुओं के पलायन की बात उठी तो वोट के सौदागरों ने उसका खंडन किया। सच्चाई यह है कि विगत जनगणना में कैराना में हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय से आधा यानी 9.19 प्रतिशत तथा मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हिंदू से तीन गुना यानी 29.81 प्रतिशत थी। एक अनुमान के मुताबिक 2001-2011 के बीच बंगाल से करीब 35 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ है। ओवैसी के अपने शहर हैदराबाद की स्थिति भी कश्मीर घाटी से कम नहीं है। 2001 में हैदराबाद की हिंदू जनसंख्या 21,21,963 थी जो 2011 में घटकर 20,46,051 रह गई। ओवैसी पूरे देश को हैदराबाद बनाने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। बिहार के सीमावर्ती जिले में जैसे ही इन्हें राजनीतिक सफलता मिली, वैसे ही वहां भी कश्मीर घाटी को दोहराने की शुरुआत हो गई। पूर्णिया जिला की बायसी विधानसभा मुस्लिम बहुल है जहां से इस बार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसी वर्ष मई में इसी बायसी विधानसभा में दलितों की बस्ती को मुसलमानों के एक समूह ने आकर जला दिया।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घुसपैठ और हिंदुओं के पलायन के बाद अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के षड्यंत्र का भी फर्दाफाश हो गया है। इसके तार पाकिस्तान के साथ ही अन्य मुस्लिम देशों से भी जुड़ रहे हैं। इस्लामिक ताकतें घुसपैठ और हिंदू पलायन के साथ प्रस्तावित गलियारे में आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रही हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सक्रिय है। जून 2000 में आई एक रिपोर्ट ने भारत-नेपाल सीमा पर तेजी से बन रहे मदरसों और मस्जिदों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। ये मदरसे और मस्जिदें ऐसी जगहों पर बनाई जा रही हैं जहां से भारत की सामरिक तैयारियों पर न केवल नजर रखी जा सके बल्कि अपने आकाओं के इशारे पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में भी डाला जा सके।

मुस्लिम आबादी की अप्रत्याशित वृद्धि दर (% में)



असमान विस्तार : उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि पूरे प्रदेश में एक समान नही है। यह मुस्लिम पट्टी वाले जिलों जैसे मुजफ्फरनगर (50.14 फीसद), मुरादाबाद (46.77 फीसद), बरेली (50.13), सीतापुर (129.66 फीसद), हरदोई (40.14 फीसद), बहराइच (49.17 फीसद) और गोंडा (42.20 फीसद) है। हरियाणा में भी मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में 1981-91 में 45.88 फीसद के मुकाबले 1991-2001 में 60.11 फीसद दर्ज की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 जुलाई, 2021

दैनिक जागरण

प्रयास ही पुरस्कार का आधार होते हैं

हंगामा न हो

संसद के मानसून सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से विपक्ष से यह जो अपील की गई कि सदन में सार्थक और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा होनी चाहिए, वह कितना असर करती है, इसका पता पहले दिन ही चल जाएगा। आम तौर पर संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत हंगामे से ही होती है। ऐसा इसके बावजूद होता है कि सरकार सभी मसलों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार होती है। सरकार की तैयारी के बाद भी विपक्ष कई बार अपनी ओर से उठाए गए मुद्दों पर बहस के लिए अड़ जाता है और कभी-कभी तो इस पर तकरार हो जाती है कि बहस किस नियम के तहत हो? ऐसा लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी। संसद के ऐसे सत्रों का स्मरण करना कठिन है जब संसदीय कार्यवाही बाधित न हुई हो। वास्तव में अब संसदीय कार्यवाही धीर-गंभीर चर्चा के लिए बहुत कम जानी जाती है। यदि संसद को अपनी उपयोगिता और महत्ता कायम रखनी है तो यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वहां पर राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर सार्थक चर्चा हो। यह चर्चा ऐसी होनी चाहिए, जिससे देश की जनता को कुछ दिशा मिले। संसद में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सार्थक चर्चा के लिए दोनों ही पक्षों को योगदान देना होगा। संसद सत्र के पहले सर्वदलीय बैठकों में इसके लिए हामी तो खूब भरी जाती है, लेकिन अक्सर नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही अधिक रहता है।

विपक्ष संसद में किन्ही भी मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस बार जिन मसलों पर चर्चा होना आवश्यक दिख रहा है, उनमें कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, कोविड से हुई मौतें, स्वास्थ्य ढांचे की हालत, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और किसानों की समस्याएं प्रमुख हैं। इसी के साथ देश की आर्थिक स्थिति और अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर भी चर्चा आवश्यक जान पड़ रही है। जिस एक और गंभीर मसले पर चर्चा होनी चाहिए, वह है बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा। इस हिंसा ने बंगाल के माथे पर कलंक लगाया है। यदि विपक्ष हंगामा करने को अपना मकसद नहीं बनाता और सत्तापक्ष उसकी ओर से उठाए गए मुद्दों को सुनने के लिए तत्पर रहता है तो संसद का मानसून सत्र एक नजीर बन सकता है। संसद में केवल ज्वलंत मसलों पर उपयोगी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायी कामकाज भी सुचारु रुप से होना चाहिए। विपक्ष अपने मुद्दों को उठाने के लिए सजग रहने के साथ यह भी ध्यान रखे तो बेहतर कि संसद के इस सत्र में करीब 30 विधेयक पेश होने हैं और इनमें से लगभग आधा दर्जन अध्यादेश के रूप में हैं।

नक्सलियों का सफाया

लंबे अंतराल के बाद झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर दो दिनों के भीतर दो बड़े उग्रवादियों को मार गिराया। इससे पुलिस के साथ आम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है। नक्सली झारखंड के लिए पिछले कई दशकों से बड़ी समस्या रहे हैं। हाल के वर्षों में इन्हें मुख्यधारा में लाने के प्रयास भी होते रहे। इस बीच कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो कई मार गिराए गए। हाल के वर्षों में प्रदेश में नक्सली कमजोर तो पड़े, लेकिन समय-समय पर सिर उठाकर वह सुरक्षाबलों को निशाना भी बनाते रहे। वहीं दहशत फैलाकर वह लेवी भी वसूलते रहे। पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान निरंतर बनाए रखना चाहिए। झारखंड में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच अब तक सैकड़ों मुठभेड़ हो चुके हैं। पूर्व में कई बड़े नक्सली भी मारे गए, लेकिन इस समस्या का अंत नहीं हो पाया। सुदूर इलाकों में विकास योजनाओं को तेज गति देकर ग्रामीणों में और भी भरोसा जगाया जा सकता है, ताकि लोग नक्सलियों के बहकावे में न आएं। नक्सलियों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जो इसके बावजूद हिंसा का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, उनके खिलाफ सख्ती आवश्यक है। उन्हें संदेश भी दिया जा रहा है कि यदि विकास में बाधक बने तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। पिछले दो दिनों में पुलिस ने जो किया, वह यही स्पष्ट संकेत दे रहा है। झारखंड के सुदूर इलाकों में स्थित पर्यटन स्थलों पर भी नक्सलियों के डर से लोग जाना नहीं चाहते। इससे पर्यटन उद्योग प्रभावित है। वहीं विकास कार्य भी बाधित हैं। नक्सली समस्या का समाधान होने से इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और झारखंड विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभर सकेगा। नक्सलियों के अर्थतंत्र पर प्रहार करना भी आवश्यक है। हाल के वर्षों में संयुक्त प्रयास से आर्थिक तंत्र पर चोट किया गया है। इससे नक्सलियों को झटका लगा है। अब झारखंड की कमान नए डीजीपी के हाथ है। ऐसे में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई लोगों में भरोसा जगा रही है कि राज्य से एक दिन नक्सलियों का सफाया होगा। जहां पहले से दहशत थी, वहां शांति बहाल हो सकेगी।

नक्सली समस्या का समाधान होने से राज्य का राजस्व बढ़ेगा और झारखंड विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभर सकेगा

कानून की आवश्यकता पर भी हो विचार



हृदयनारायण दीक्षित

राजद्रोह कानून का दुरुपयोग बेशक गंभीर बात है, लेकिन उसकी जरूरत और उपयोगिता भी विचारणीय है



अवधेश राजपूत

भारतीय राष्ट्र राज्य संप्रभु सत्ता है। व्यक्ति की तरह राष्ट्र राज्य की भी अस्मिता है। राष्ट्र को भी आत्मरक्षा के अधिकार हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा-121, 121ए, 122, 123, 124 व 124ए में राजद्रोह से निपटने के प्रविधान हैं। इनमें से 124ए के दुरुपयोग और खात्मे पर बहस जारी है। इस कानून में उल्लेख है, 'जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या उसकी कोशिश करेगा। अप्रीति का प्रसार करेगा, प्रयत्न करेगा वह तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।' सर्वोच्च न्यायपीठ ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 'सरकार ने कई पुराने कानून रद किए हैं। गांधी और तिलक के विरुद्ध भी इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। क्या स्वतंत्रता के बाद भी इस कानून की जरूरत है?' कानून का दुरुपयोग बेशक गंभीर बात है, लेकिन कानून की आवश्यकता भी विचारणीय है। आवश्यकता से ही कानून का जन्म होता है। कानूनों में संशोधन और निरसन भी राष्ट्र की आवश्यकता के कारण ही होते हैं। कानून का मसौदा विधेयक पेश करते समय प्रस्तावित विधि के उद्देश्य और कारण बताए जाते हैं।

राजद्रोह कानून के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप दुरुपयोग का है। इसके लिए कानून का उपयोग करने वाला तंत्र जिम्मेदार है, कानून नहीं। अवैध हथियार रखना अपराध है। इसके लिए शस्त्र अधिनियम है। यह कानून समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन पुलिस इसी कानून में निर्दोषों को भी जेल भेजती है। क्या इसी आधार पर कानून समाप्त करना सही हो सकता है? यहां तमाम कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन मात्र दुरुपयोग के आधार पर ही कानून समाप्ति का कोई औचित्य नहीं है। दुरुपयोग रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए कानून प्रवर्तित करने वाले तंत्र के पेच कसने की जरूरत है। राजद्रोह संबंधी कानून के विरुद्ध दूसरा मुख्य आरोप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होना है। विचार अभिव्यक्ति संविधान का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष और असीम नहीं है। इससे जुड़े अनुच्छेद 19 में विचार स्वातंत्र्य पर 'भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और न्यायालय अवमान आदि के बंधन' हैं। यहां विचार अभिव्यक्ति के बहाने राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता से खिलवाड़ की छूट नहीं है। ऐसा खिलवाड़ देशद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता?

राजद्रोह कानून की संवैधानिकता का परीक्षण उचित है। वर्ष 1962 में सर्वोच्च न्यायपीठ ने केदारनाथ मामले में 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण किया था और इसे संवैधानिक घोषित किया था। यह भी कहा था कि 'नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है बशर्ते वे हिंसक विचार से दूर रहें।' भारत में सरकारों की आलोचना होती है। असहमति के अवसर हैं। वैचारिक टकराव भी हैं। मूलभूत प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर भी आक्रमण करना सिर्फ सरकार की ही आलोचना है? भारतीय देश से भावात्मक लगाव रखते हैं। देश की धरती को भारत माता कहते हैं। वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रगीत है। पं. नेहरू ने भी 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में देश की धरती और लोगों को भारत माता बताया है। भिन्न-भिन्न समूहों द्वारा भावनाएं आहत होने की चर्चा बहुधा चलती है। राष्ट्रीय अखंडता का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकता? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजद्रोह की चर्चा इन शब्दों में की है, 'यदि साम आदि उपायों से राजद्रोहियों को शांत न किया जा सके तो दंड का प्रयोग होना चाहिए।'

राजद्रोह राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती है। भारत में राजद्रोह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। कभी करनी द्वारा और बहुधा कथनी द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नारेबाजी हुई, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे।' इस नारेबाजी को राजद्रोह नहीं तो क्या सुभाषित की श्रेणी में रखेंगे? दूसरी नारेबाजी और भी आग लगाऊ है, 'अफजल हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा हैं।' यह दोष सिद्ध भारत विरोधी राजद्रोही आतंकी का महिमामंडन है। क्या यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खतरनाक दुरुपयोग नहीं है? इसे राजद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता? पाकिस्तानी झंडे लहराना राष्ट्रीय अखंडता व संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह सरासर राजद्रोह है। माओवादी हिंसा राष्ट्र राज्य से युद्ध है। ऐसी घटनाएं विचार और मंसूबे देशद्रोह हैं। ये राजद्रोह की ही श्रेणी में आती हैं। आइपीसी की धारा 124ए में इनका विचारण संभव है। राष्ट्र राज्य की अस्मिता का विधिक संरक्षण जरूरी है। भारत में विधि का शासन है। यहां हर समस्या का समाधान विधि द्वारा ही होता है।

सक्रिय राष्ट्र विरोधी शक्तियों से निपटने के लिए कानून जरूरी हैं। ये ताकतें किसी न किसी रूप में अपने मंसूबे पूरे करने में लगी हैं। आतंकियों की हरसंभव सहायता यही ताकतें करती हैं। राष्ट्र की आंतरिक रक्षा के लिए 124ए की अपनी उपयोगिता है। इसके दुरुपयोग की चर्चा नई नहीं है। दुरुपयोग रोकने के लिए इसी कानून में कतिपय संशोधन संभव हैं। विधि प्रवर्तक तंत्र को भी दुरुस्त करना होगा। इस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय की यह बात सही है कि इस कानून में जवाबदेही नहीं है। अदालत ने इस कानूनी प्रविधान की संवैधानिकता जांचने का निश्चय किया है। यह अच्छी बात है, पर संवैधानिकता के साथ इसकी उपयोगिता का निरीक्षण भी जरूरी है। दुनिया के सभी कानूनों का उद्देश्य उपयोगिता ही होता है। उपयोगिता समाप्ति के बाद कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब उसकी समाप्ति ही उचित है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा है कि 'राजद्रोह कानून पर विचार अभिव्यक्ति के लिटमस टेस्ट से परीक्षण का समय आ गया है।' अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया है कि दुरुपयोग रोकने के लिए, 'कुछ मार्गदर्शी रक्षोपाय जोड़कर कानून का सही लक्ष्य पाया जा सकता है।' उनके अनुसार इस कानून का सुनिश्चित उद्देश्य व प्रयोजन है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। यह खूबसूरत मौलिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता अखंडता के तोड़कों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का कानून भी जरूरी है। राजद्रोह असाधारण प्रकृति का अपराध है। इसलिए कानून की उपयोगिता है। इस दृष्टि से वेणुगोपाल के सुझाव उपयोगी हैं। मूल समस्या कानून के दुरुपयोग की है, कानून समाप्त करने की नहीं है। माननीय न्यायालय ने समग्रता में सुनवाई व विचारण की बात कही है। विश्वास है कि समग्रता में विचारण का फल राष्ट्र हितैषी होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

इतिहास को दुरुस्त करने का अवसर



कृपाशंकर चौबे

इतिहास को जब तक सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वह प्रेरणादायी नहीं हो सकता

शिक्षा से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को दुरुस्त करने के लिए देशभर के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे हैं। यह पहल तार्किक ही है, क्योंकि अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय राजाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी और हार गए, किंतु उन्होंने जो युद्ध जीते, उसका वृत्तांत नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए आठवीं शताब्दी में 36 वर्षों तक युद्ध कर अपने राज्य का विस्तार करते रहे कश्मीर के कर्कोटक नागवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में स्कूली इतिहास की किताबें खामोश हैं। उन्होंने अरब के मुसलमान आक्रांताओं तथा तिब्बती सेनाओं को पीछे धकेला था। उनका राज्य पूरब में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर बनवाया था। ग्यारहवीं शताब्दी में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित करने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव के बारे में भी स्कूली इतिहास की किताबों में सुसंगत विवरण नहीं मिलता। इसी तरह 1741 में डचों को हराने वाले राजा मार्तंड वर्मा के बारे में इतिहास की किताबें प्रकाश नहीं डालतीं। चोल, चालुक्य, देवबर्मन, अहोम राजाओं के बारे में भी इतिहास की किताबें लगभग मौन हैं। दक्षिण भारत से लेकर ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर के अनेक प्रतापी राजाओं ने दो-ढाई सौ वर्षों तक शासन किया, पर उनके बारे में स्कूली इतिहास की किताबों में यथोचित विवरण नहीं मिलता। स्कूलों में भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह मुख्यतः दिल्ली का इतिहास है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे समय इतिहास के एकांगी पक्ष को दूर करने का सुअवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

किसी भी देश का इतिहास कितना ही गौरवपूर्ण क्यों न हो, जब तक उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वह प्रेरणादायी नहीं हो सकता। बहुत कम पुस्तकें हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सके। इस दृष्टि से काशीप्रसाद जायसवाल की किताब 'हिंदू राज्य तंत्र' और गोविंद सखाराम सरदेसाई द्वारा 12 खंडों में लिखी गई 'भारत का इतिहास' को मानक माना जा सकता है। हिंदू राज्य तंत्र पुस्तक दो खंडों में विभक्त है। पहले खंड में आरंभिक काल, महाभारत काल के



केदारनाथ स्थित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। आदि शंकर को इतिहास में भी यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए। फाइल

राजनीतिक ग्रंथ, चौथी एवं पांचवीं शताब्दी के ग्रंथों, हिंदू धर्मशास्त्रकारों के चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक के ग्रंथों, छठी एवं सातवीं शताब्दी के ग्रंथों और आरंभिक मध्य युग के ग्रंथों, नीति एवं धर्म संबंधी ग्रंथों का विवेचन किया गया है। उसके बाद सभा-समितियों के कार्य का विवरण देते हुए हिंदू प्रजातंत्रों के आरंभ का इतिहास बताया गया है। बौद्ध संघ के प्रजातंत्र से लेकर हिंदू प्रजातंत्र का विवरण दिया गया है। मौर्य साम्राज्य, वैदिक काल, हिंदू एकराजत्व का विवरण भी विस्तार से दिया गया है। जायसवाल ने भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखा। वही काम गोविंद सखाराम सरदेसाई ने किया। उन्होंने 1000 से 1857 तक का 'भारत का इतिहास' बारह खंडों में लिखकर मुसलमान, मराठा और अंग्रेजों के इतिहास का व्यापक, सही और सुसंगत विवरण दिया।

इतिहास में केवल प्रामाणिक तथ्य दिए जाते हैं। पात्र, परिस्थितियां और घटनाएं इतिहाससम्मत होती हैं और इतिहास लिखने वाले के पास उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री होती है, किंतु समस्या तब होती है जब किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य न हो। जैसे 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में इतिहासकारों के चार मत हैं। एक मत उन अंग्रेजपरस्त अध्येताओं का है कि 1857 की जनक्रांति गदर-विफल बगावत थी। दूसरा मत उन अध्येताओं का है कि वह जनक्रांति भारतीय सामंतों के स्वार्थ की लड़ाई थी। तीसरे मत में कुछ अध्येताओं ने उस क्रांति में आदिवासियों, दलितों एवं अन्य छोटी जातियों के अन्याय विरोधी संघर्ष की झलक देखी थी तो चौथे मत के इतिहासकारों की राय में 1857 का संग्राम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के उत्कट बलिदानों से भरा एक सुनियोजित महासंग्राम था। राष्ट्रीय चेतना जगाने और अंग्रेजी राज्य से मुक्ति का वह पहला संगठित आंदोलन देश की मर्यादा और आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं और संग्रहालयों में उसके इतने प्रमाण हैं कि कोई उससे किनारा नहीं कर सकता। चौथा मत इसलिए सर्वाधिक मान्य हुआ, क्योंकि वह इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखा गया।

इसके अलावा उन सभी गैर-राजनीतिक व्यक्तियों का इतिहास भी पढ़ाया जाना चाहिए, जिनका समाज पर असर या जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा हो। जैसे कबीर का जो प्रभाव समाज पर रहा है, उसे केवल साहित्य नहीं इतिहास में भी शामिल करना चाहिए। उसी तरह इतिहास के विद्यार्थियों को शंकराचार्य के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह उन्होंने पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। चारों दिशाओं में स्थापित होने वाले ये मठ भारत की एकता का परिचय देने वाले चिन्ह हैं। इसी तरह यह भी बताया जाए कि किस तरह स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को वेदांत और योग से परिचित कराते हुए यह बोध कराया था कि वेदांत में सभी धर्मों की एकात्मकता व्यक्त होती है। इसी भांति इतिहास के विद्यार्थियों को यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में किस तरह सखाराम गणेश देउस्कर की किताब 'देशेर कथा' का राष्ट्रीय जीवन में कितना व्यापक प्रभाव पड़ा।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

एकाग्रता

वास्तव में ध्यान मन की लहरों को शांत करना है। अर्थात मन को विचारों से खाली करना है और यह ध्यान मन की एकाग्रता से प्रारंभ होता है। प्रायः हम अपने कार्यों के प्रति एकाग्र नहीं होते हैं। हम स्नान कर रहे होते हैं तो भोजन या फिर अन्य विषय के बारे में सोचते हैं। जब भोजन कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर अन्य दूसरे विचार आते रहते हैं। कहने का मतलब है कि हम एक कार्य कर रहे होते हैं, परंतु सोचते हैं अन्य कार्यों के प्रति। इससे मन की एकाग्रता क्षीण होती है। कार्य सिद्धि या लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम जिस कार्य को करें हर पल उसी के विषय में सोचें। धीरे-धीरे हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर हम बड़ी आसानी से अपने आत्मा के भीतर प्रवेश कर सकेंगे।

सुखपूर्वक हम किसी भी आसन में बैठकर किसी भी चीज या बिंदु पर ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान करते समय हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। उन विचारों को हमें दबाना या रोकना नहीं है, बस साक्षी भाव से उन विचारों को देखना भर है। इन्हीं विचारों तथा इच्छाओं को द्रष्टाभाव से देखने का चमत्कार ही ध्यान है। हम यह महसूस करें कि ये विचार मन के अंदर नहीं, बल्कि बाहर ही गुजर रहे हैं। हम यह भी महसूस करें कि इन विचारों की स्मृतियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से धीरे-धीरे हम निर्विचार होते जाएंगे।

इस प्रकार ध्येय वस्तु का ध्यान करते-करते मन उसमें ही विलीन हो जाता है। इससे साधक हर पल ध्यानमय रहता है। यह अमन की अवस्था ही ध्यान है। ऐसा करने पर साधक अपने आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता है। इससे साधक को महसूस होने लगता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं। ऐसा होने पर साधक के मन से कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। इससे उसके अंदर अहम् का भाव नहीं रह जाता। अहम् से मुक्ति जीवन को सार्थक बनाने की राह खोल देती है।

अवधविहारी शुक्ल

महंगाई पर अंकुश जरूरी

डॉ. महेश परिमल

महंगाई बढ़ाने वाले कारकों की तलाश कर उस पर अंकुश लगाना आज की पहली आवश्यकता है

कहा जाता है कि देश के 20 प्रतिशत गरीबों के लिए सरकार है, 20 प्रतिशत अमीरों को महंगाई से कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बचे 60 प्रतिशत मध्यमवर्गीय लोग। यही वर्ग सबसे अधिक टैक्स सरकार को देता है। आज महंगाई से यही वर्ग सबसे अधिक त्रस्त है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसे वे अपने लिए राहत मानें। जब से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं, तब से कृषि उत्पादों पर उसका असर हुआ है। पूरे देश में सड़क मार्ग से माल की ढुलाई होती है, इससे जुड़े सभी संस्थानों ने अपने बाजार भाव बढ़ा दिए हैं। यही हाल दूसरे उपभोक्ता वस्तुओं का भी है। इसके अलावा कई ऐसे भी क्षेत्र हैं, जो कीमतों में वृद्धि की राह देखते रहते हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उससे संबंधित कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर यदि इनकी कीमतों में कमी आती है तो बढ़े हुए दाम कभी कम नहीं होते। ऐसा बाजार में बार-बार देखा गया है। इस परिस्थिति का लाभ व्यापारी वर्ग उठाता है। सरकार इसे अच्छी तरह से समझती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। चारों तरफ कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। कई कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के पैकेट का आकार छोटा कर दी हैं। जो अब तक 500 ग्राम माल डालते थे, वे अब 400 ग्राम का पैकेट बनाने लगे हैं।

हाल में अमूल ने प्रति लीटर दो रुपये दूध की कीमत बढ़ा दी। इसके कारण अब दूसरे उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, यह तय है। इसी तरह टीवी के दाम बढ़े, क्योंकि इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दाम बढ़े। महंगाई की इस आग में स्मार्ट मोबाइल फोन के साथ-साथ कई इलेक्ट्रानिक्स सामान भी चपेट में आए हैं। कोई भी व्यापारी यह नहीं चाहता कि उसके व्यापार में उसे किसी भी तरह का घाटा हो। अपने लाभ के लिए कई बार वह प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम कर देता है या फिर वजन।

कुछ लोग कहते हैं कि आज महंगाई कहीं नहीं है, क्योंकि जुलाई महीने में कार कंपनियों ने कुल 20 नए माडल लांच किए हैं, जिसे खरीदने के लिए लोग हाय-तौबा मचा रहे हैं। यह एक गलत सोच है, क्योंकि इन्हें यह नहीं मालूम कि कार के नए माडल देश के केवल दो प्रतिशत लोगों के लिए ही हैं। बाकी 98 प्रतिशत लोग आज भी महंगाई के बोझ से दबे हुए हैं। केंद्र सरकार को इस दिशा में कुछ सख्त कदम उठाने ही होंगे। महंगाई बढ़ाने वाले कारकों की तलाश कर उस पर अंकुश लगाना आज की पहली जरूरत है। वैसे भी महंगाई के बारे में कहा गया है कि इसका कीड़ा सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप तक ही जीवित रहता है। पिज्जा हट, शापिंग माल, आइस्क्रीम पार्लर, पीवीआर सिनेमा में घुसते ही मर जाता है। उसके बाद शराब दुकानों में पहुंचकर आत्महत्या ही कर लेता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जनसंख्या वृद्धि सबके लिए हानिकारक

'बढ़ती जनसंख्या से मुंह मोड़ने की कोशिश' शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों का विरोध करने वालों को यह समझाने की कोशिश की है कि जनसंख्या वृद्धि देश की बहुत सी समस्याओं की जड़ है। लिहाजा इसके नियंत्रण के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रयास का किसी भी धर्म के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की मानें तो अगले 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दो अरब तक बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर एक बन सकता है। कुछ समय पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एक जनवरी, 2019 को दुनिया में लगभग तीन लाख 95 हजार बच्चों ने जन्म लिया। इस दिन भारत में सबसे ज्यादा 69,944 बच्चे पैदा हुए। यह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे में समय के साथ-साथ सरकारों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त नीति बनाई जाए। अगर भारत ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए अभी से उपाय नहीं किए तो फिर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई आदि समस्याएं बेकाबू हो जाएंगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चिंता का विषय

'बढ़ती जनसंख्या से मुंह मोड़ने की कोशिश' में संजय गुप्त ने जनसंख्या वृद्धि को चिंता का विषय बताते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य को आबादी नियंत्रण के विषय पर सोचना चाहिए। कोरोनाकाल में अस्पताल, डाक्टर, आक्सीजन, दवाइयों की कमी और शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार न हो पाने के बावजूद यदि अब भी हमारी आंखें नहीं खुलीं तो कब खुलेंगी? किसी भी देश की तरक्की स्वस्थ जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिसका भरण पोषण आसानी से हो सके। देश में नालों के किनारे झोपड़ियां बनाकर नारकीय जीवन जीने के लिए इंसान मजबूर है। भारतीय रोजी रोटी और अच्छे जीवन की आस में विदेश कमाने जाते हैं। वहां किन कष्टों से गुजरते हैं, वही जानते हैं। अब तो विदेश में भी रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतें कम होने से तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है। प्राइवेट नौकरियों में अनिश्चितता बनी रहती है। धरती जनसंख्या के हिसाब से खींचकर बड़ी, छोटी या चपटी नहीं होती है। राजनीतिक दल चुनाव के अवसर पर बड़े-बड़े वादे कर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार महिलाओं की समझ में आसानी से आ जाता है। जरूरत है महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की। टेक्नोलाजी का जमाना है। जितना विकास होगा, रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे, तब क्या होगा?

डा. शोभा भारद्वाज, दिल्ली

पाकिस्तान को भी रास्ते पर लाना होगा

'तालिबान के शिकंजे में अफगानिस्तान' नामक आलेख में विवेक काटजू ने अफगानिस्तान की वर्तमान विकराल परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। वहां के लगभग 40 वर्षों के घटनाक्रम को सूत्रबद्ध किया जाए तो समस्या किसी सुलह सफाई के रास्ते की नहीं है। वहां केवल एक ही धार्मिक एजेंडा या व्यवस्था को स्थापित करने का संघर्ष कई दशकों से चलता आ रहा है। इस संघर्ष को लगभग 20 साल तक रूस झेलकर चला गया। उसके बाद अमेरिका द्वारा स्वयं पैदा किए गए इस जिन्न को 20 साल तक काबू कर पाने असमर्थ रहकर अपने आपको वहां से उठाकर ले गया। तालिबानी संघर्ष किसी लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का मंतव्य नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से धार्मिक शरिया कानूनों के तहत एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है। आज तालिबानियों के साथ पाकिस्तान के कुछ या अधिक निहित स्वार्थ हैं। परंतु यह पाकिस्तान को आभास होना चाहिए तालिबानियों का अगला सुगम लक्ष्य वही होगा। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान उनका साथ देने के बजाय अभी से चेत जाए।

डीडी सिंघल, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

39 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर और महज 22 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा मौजूद है देश में, यूडीआइएसई की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्रों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

आजकल

स्कूली शिक्षा में समग्र सुधार की बने रूपरेखा

कोरोना महामारी के दौरान देशभर में स्कूली शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि आनलाइन माध्यम से स्कूली कक्षाओं का संचालन अवश्य जारी रखा गया है, लेकिन महामारी जनित कारणों से आनलाइन कक्षाओं के अभी जारी रहने के दौर में इस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। हाल में जारी एक संबंधित रिपोर्ट में भी आनलाइन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विविध पहलुओं के विश्लेषण पर जोर दिया गया है। लिहाजा इस दिशा में समग्र सुधार की ओर समुचित कदम उठाया जाना जरूरी है



अमरजीत कुमार
शोधार्थी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

कोरोना काल में देश में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सरकार द्वारा कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। वहीं पिछले दिनों एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडीआइएसई प्लस द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी रिपोर्ट कई मायनों में अहम है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की शुरूआत 2012-13 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (तब मानव संसाधन मंत्रालय) द्वारा की गई थी। मंत्रालय ने इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए एकीकृत प्रणाली का गठन किया था। भारत में विद्यालयी शिक्षा पर यह मुख्य सार्वजनिक डाटाबेस है, जिसमें 15 लाख से अधिक विद्यालय शामिल हैं। वहीं इसमें 97 लाख शिक्षक और प्री-प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्तर तक 26.5 करोड़ बच्चे हैं।

यूडीआइएसई प्लस की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के आधार पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न पहलुओं का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर 3.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 44.3 फीसद सरकारी विद्यालयों में हैं और करीब 20 फीसद सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हैं, जबकि लगभग 35 प्रतिशत छात्र निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यानी विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। एलिमेंटरी और अपर प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में सकल प्रवेश दर (जीईआर) क्रमशः 1.7 फीसद और दो फीसद वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि हायर सेकेंडरी स्तर पर वृद्धि दर 1.3 फीसद रही। इस दौरान शिक्षक छात्र अनुपात में भी सुधार हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षकों की संख्या में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 2.7 फीसद की वृद्धि हुई। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019-20 में 96.87 लाख शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे थे, जो 2018-19 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 2.57 लाख अधिक है।

उपरोक्त संदर्भों में यूडीआइएसई की रिपोर्ट सकारात्मक संकेत देती है। जबकि कुछ पक्ष अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। पूर्व के अध्ययनों के अनुसार विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि के साथ पाठ्यक्रम सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना चुनौतीपूर्ण है, जिसके कई सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। दूसरी तरफ कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था के लिए तय की जा रही आगामी नीतियों में यूडीआइएसई प्लस रिपोर्ट को आधार बनाना महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 30 फीसद छात्र सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर पर दाखिला नहीं लेते हैं और बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। जबकि माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर 17 फीसद से अधिक है। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर यह क्रमशः 1.8 और 1.5 फीसद है।

महामारी के बाद से व्यापक बदलाव : भारत में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वर्तमान में अनेक कदम उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है। दूसरी तरफ यूडीआइएसई प्लस की रिपोर्ट में कोरोना महामारी के पूर्व की स्थिति से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, इसके सभी आयामों पर चर्चा की जानी चाहिए।

कोरोना महामारी के दौरान आनलाइन माध्यम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। ऐसे में आनलाइन शिक्षा व्यवस्था लागू करने में तकनीकी पूर्व आवश्यकताएं और आधारभूत संरचना पर कार्य किया जाना अहम होगा। संबंधित रिपोर्ट के अनुसार देश के सिर्फ 39 फीसद स्कूलों में कंप्यूटर और सिर्फ 22 फीसद स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन था। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी रही। हाल ही में इस संबंध में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा है। यही कारण है कि कोरोना के कारण शिक्षा में उत्पन्न व्यवधान की स्थिति में भारत का स्थान दक्षिण एशिया में दूसरे सबसे खराब देशों में रहा। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को आनलाइन शिक्षा व्यवस्था के माध्यम को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

भारतनेट परियोजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को यह कहा था कि आगामी एक हजार दिनों में देश के सभी गांवों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार का लक्ष्य रखा है। वहीं पिछले दिनों सरकार ने 'भारतनेट परियोजना' के माध्यम से ब्राडबैंड विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने में काफी मदद मिलेगी। जरूरत है कि योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए, क्योंकि अक्टूबर 2011 में प्रारंभ भारतनेट परियोजना को पूरा करने की तय समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान महामारी काल में आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आनलाइन शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण : यूडीआइएसई प्लस की रिपोर्ट ने नई शिक्षा नीति और आनलाइन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित पक्षों को विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का समान उपयोग सुनिश्चित करना, विषय के अंतर्गत महामारी के दौर में आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लागू करना एक आवश्यक कदम माना है। साथ ही इसके कई आयामों पर चर्चा भी की गई है। नई शिक्षा नीति में साहित्य, वोकेशनल विषय, ओपन डिस्टेंस लर्निंग आदि में आनलाइन माध्यमों को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि 'स्वयं' और 'दीक्षा' जैसे आनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग कर शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य किया जाना है। उपरोक्त आधार पर यह महत्वपूर्ण है कि आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित सभी जरूरतों पर एक प्रभावी रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है।



महामारी के बाद स्कूली शिक्षा व्यवस्था में पैदा हुई चुनौतियों से समग्रता से निपटने की आवश्यकता है। फाइल

शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना का विकास

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई चार अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रविधान किया गया है। वहीं एक अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया।

कोरोना महामारी ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को काफी प्रभावित किया है, जबकि यूडीआइएसई प्लस की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई कमियों को दुरुस्त करने की जरुरत है। कोरोना महामारी के दौरान छात्रों के लिए आनलाइन माध्यम ही बेहतर विकल्प था। ऐसे में ग्रामीण और शहरी छात्रों में आनलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा में काफी असमानता थी, जबकि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों की स्थिति कमोबेश यही रही। इस संबंध में 34,000 से अधिक भारतीय छात्रों पर किए गए एनसीईआरटी के एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अगस्त 2020 में जारी किया गया जिसके तहत लगभग 27 फीसद स्कूली छात्रों के पास आनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन, लैपटाप या कंप्यूटर तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा सेटेलाइट टीवी क्लासरूम स्थापित करने के लिए इसरो ने अपनी सहमति दे दी है, ताकि महामारी के दौरान विद्यालय बंद होने की स्थिति में उन हजारों छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जा सके जिनकी पहुंच आनलाइन कक्षाओं तक नहीं है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में टीवी तक बच्चों की पहुंच आसान है, वहीं सेटेलाइट टीवी के माध्यम से छात्र निशुल्क आनलाइन क्लास की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े पिछले कुछ रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि विगत दशकों में निजी विद्यालयों के खुलने में और उनमें नामांकन दर में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निजी विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों के सामने एक विकल्प देता है, लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था में असमानता का भी कारण बना है। सरकार के सामने यह चुनौती है कि सरकारी विद्यालयों में भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। विगत दो वर्षों से वैश्विक कोरोना महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था एक चुनौती के दौर से गुजर रही है। जबकि यूडीआइएसई प्लस की रिपोर्ट से स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम पक्ष उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसके विभिन्न पक्षों से जुड़े कई आयामों पर कार्य करने की जरूरत है। गौरतलब है कि प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी, किंतु केंद्र और राज्यों का महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे में केंद्र और राज्यों को एक साझा और प्रभावी रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है।

ऐसे समय में जब देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसके तहत शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया जाना है। ऐसे में नई शिक्षा नीति में महामारी की दशा में वैकल्पिक माध्यमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। अतः विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इसे अवसर के तौर पर लेना चाहिए और एक तय समय सीमा में शिक्षा से जुड़ी नई पाठ्यक्रम व्यवस्था के साथ आधारभूत संरचना के विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए।

खरी-खरी

मेरा लेखन और उनका बिजनेस

राकेश सोहम

प्रातः भ्रमण के दौरान वे लगभग रोज मिलते हैं। सुबह के हलके उजाले में भी उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। बदन पर झक सफेद ब्रांडेड टीशर्ट, डार्क ब्राउन ट्रैक पायजामा और पैरों में महंगे ट्रैकिंग जूते। इन सबके कारण चेहरे पर रईसी दमक। आंखों पर हल्का रंगीन चश्मा और कानों में ठुंसे हुए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की कार्ड झूलती हुई लोअर की पीछे वाली जेब से बाहर झांकते हुए मोबाइल में फंसी रहती है। एक हाथ में काले और चौड़े पट्टे वाली स्मार्ट वाच और दूसरे हाथ में विदेशी कुत्ते की चेन।

प्रतिदिन प्रातः भ्रमण के दौरान उनसे सामना हो जाता है। एक दिन मैंने ही पहल करते हुए नमस्कार कर दिया। वे रुक गए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा। हालांकि मुझे पहचानना कठिन नहीं था। मैं नित्य उसी काली टीशर्ट, जो जगह-जगह से घिसकर भूरी हो चुकी है, और हरे पेंट में निकलता हूं। सफाई पसंद हूं इसलिए रोज धो लेता हूं। लोगों की जेब धो देना सीखता तो शायद मैं भी रोज नया सूट पहनता।

उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं?

मैं झेंपा और बोला, सेवानिवृत्त हूं और लेखक भी हूं। मेरी मति मारी गई थी इसलिए मैंने भी पूछा लिया, और आप क्या करते हैं? वह पुरानी फिल्मों के खलनायक की स्टाइल में खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, बिजनेस... अपना लाखों का धंधा है।

मैंने आत्मविश्वास जुटाकर कहा, कभी समय मिले तो पढ़िएगा हमारी किताब। वे फिर विलेन स्टाइल में बोले, टाइम कहां है? बस ये टामी को टहलाने निकलना पड़ता है। बस यही एक्स्ट्रा समय है जीवन में। वे कहना चाह रहे थे कि टामी मुझसे भी अधिक भाग्यवान है, जिसे वे समय दे देते हैं।

मैंने हिम्मत करते हुए कहा, अखबार तो पढ़ते होंगे। उसमें पढ़िएगा, मेरी रचनाएं छपती हैं।

अबकी वे अमरीश पुरी हो गए। बोले, खाली कारोबार का पन्ना ही पढ़ पाता हूं। ये व्यंग्य, कहानी कविताएं तो 12वीं के बाद से अब तक नहीं पढ़ी। और फिर इनको पढ़कर मिलता भी क्या है?

उनकी बात सुन मैंने मन में कहा, ये कहानी, कविताएं, व्यंग्य न होते, तो यह देश कबका सीरिया बन गया होता।

ट्वीट-ट्वीट

ईद के लिए केरल सरकार ने जो तीन दिन की छूट दी है, उसे तुरंत रद किया जाना चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट सख्ती करे। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी केरल से ही आ रहे हैं, तिस पर ऐसी ढिलाई और बर्बादी लाएगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा बंद करके ठीक किया गया, अब केरल भी संयम का परिचय दे।

सौरव शर्मा@journosaurav

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। दरअसल उनका प्रचार तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था और 26 जनवरी को तो उन्होंने रोड शो भी कर दिया था।

राजशेखर झा@rajshekharTOI



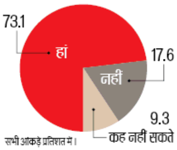
शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। परिपक्व नेता ऐसे ही करते हैं। वे मोदी की राजनीतिक रूप से आलोचना करने के बावजूद संवाद की कड़ियां जोड़े रखते हैं। नवीन पटनायक, जगन रेड्डी से लेकर एमके स्टालिन तक यही करते हैं। वहीं कुछ नेता राजनीतिक विरोध को निजी दुश्मनी और घृणा के स्तर तक ले जाते हैं। संदीप घोष@SandipGhose

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की इन दिनों पार्टी में गजब दहशत है। जिस मुख्यमंत्री को वह बुला लेते हैं, उसे हुक्का पानी बंद होने का डर सताने लगता है। सिलसिला देख लीजिए। पहले असम से सोनोवाल को बुलाया और फिर त्रिवेंद्र रावत को, दोनों की कुर्सी गई। हाल ही में उन्होंने येदियुरप्पा को भी बुलाया। विकास भदौरिया@vikasbha

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कांग्रेस नेतृत्व पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफदारी और अमरिंदर सिंह की अनदेखी कर रहा है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को एक अक्टूबर से खोलने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

राणा जी कहने लगे अपनी इज्जत गोड़,
वह योगी की जीत पर देंगे यूपी छोड़।
देंगे यूपी छोड़ दर्ज कर लो यह भाई,
जिससे उनको जाय समय पर याद दिलाई।
हैं शायर पर आप सियासी धारें बाना,
खुद अपना सम्मान खो रहे शायर राणा!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्कृति और संस्कार की सरकारी सीख



राजू मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

योगी सरकार प्रदेश में पुराने से कुछ नया खोजकर लाने के लिए चर्चा में रहती है। चाहे विधर्मियों द्वारा हिंदू संस्कृति से जुड़े शहरों/ जिलों के बदले गए नामों को निरस्त कर पुनः सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नाम रखने की परंपरा हो या दीपदान या प्रज्ज्वलन जैसी समाप्त हो चुकी परंपराओं को पुनर्जीवित करने की बात हो। इसके लिए वह अक्सर विवादों और विपक्षी आलोचना के दायरे में आ जाती है।

वैसे अच्छी बात यह भी है कि इस आलोचना पर विराम लगाने के लिए एक बड़ा समर्थक वर्ग भी सामने आ जाता है। इस बार भी प्रदेश में संस्कृति और संस्कार का बोध कराने वाले ऐसे ही दो प्रयोग हुए हैं। पहला प्रयोग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो दूसरा सचिवालय में हुआ है।

उत्तर प्रदेश डायरी

संस्कृति के अहसास से जुड़ा बनारस रेलवे स्टेशन : वाराणसी या काशी ही नहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी का एक नाम बनारस भी है। बड़ा प्रचलित नाम है और बोलचाल में आज भी यही प्रचलित भी है। बनारस भी काशी का ही पर्याय है। संस्कृत वांग्मय और केनोपनिषद में रस और बन की उपलब्ध व्याख्या ही बनारस की उत्पत्ति का मूल है। केनोपनिषद में बन का अर्थ उपासना योग्य से लिया गया है और संस्कृत वांग्मय के सूक्ति रसों का अर्थ ब्रह्म से लिया जाता है। रस का अर्थ आनंद से भी लिया जाता है। यानी रस का आशय ब्रह्म और आनंद से है। आनंद की प्राप्ति शिक्षा से होती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम आबाद नगरी काशी धर्म और शिक्षा के साथ ही संस्कृत की भी जननी मानी जाती है। इसीलिए इसके बनारस नाम को पुनर्जीवित करने या नए गौरवपूर्ण अहसास से जोड़ने के लिए रेलवे ने पहल की है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन में नए बोर्ड लगाए जा चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर लगाए गए इन बोर्डों पर संस्कृत में बनारसः लिखा गया है। प्लेटफार्मों पर बनारसः के बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी राज्यों से ही नहीं विदेश के भक्त भी यहां आकर रमे रहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हजारों विदेशी भक्त प्रतिदिन काशी में रमे रहते हैं। घाटों पर इनका विचरण कौतूहल पैदा करता है। अब यहां आने वाले यात्रियों का जब शिव की नगरी के एक नए गौरव से परिचय होता है तो वह नई अनुभूति लेकर जा रहे हैं।



लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस हो गया है। स्टेशन पर लगे बोर्ड पर चार भाषाओं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में इसका नाम लिखा गया है। श्रवण भारद्वाज

गरिमा के अनुरूप पोशाक : शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर ड्रेस कोड लागू करने की अलग-अलग मंशा से पहले भी पहल हुई हैं, लेकिन यह कहकर तुरंत एक वर्ग आपत्ति शुरू कर देता है कि पहनने-ओढ़ने के चयन में आजादी होनी चाहिए। कभी कभी यह आपत्ति या आलोचना इतनी मुखर हो जाती है कि कोई भी आदेश या तो पूरी तरह वापस ले लिया जाता है या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसी ही खुसफुसाहट इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों में है। कारण है, एक आदेश जिसमें कहा गया है कि सचिवालय के कर्मचारी अब जींस-टीशर्ट में कार्यालय नहीं आएंगे। इसके स्थान पर गरिमापूर्ण पोशाक में ही कार्यालय आएंगे। इसी बात पर खुसफुसाहटें शुरू हुई हैं। हालांकि इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित का तर्क काबिले गौर है। विधानसभा के सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म मिलती है या यूं कहें यूनिफार्म का भत्ता मिलता है। जोर न देने से कर्मचारियों ने यूनिफार्म पहनने की आदत ही नहीं डाली और भूल गए। अब जब संज्ञान लिया गया है तो फौरी दिक्कत होना स्वाभाविक है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों को उन्हें दी गई यूनिफार्म ही पहन कर कार्यालय आना चाहिए।

यूं सरकारी सेवा के लोगों को अपने सेवायोजन पर हमेशा गौरव का अहसास होता है। पुलिस के लिए खाकी वर्दी नियत है। सेना के लिए भी अपनी वर्दी शान की बात है। ये यूनिफार्म तय करने के पीछे मंशा यह रही है कि वे इसे पहनकर गौरव की अनुभूति के साथ ही अपने कर्तव्यों का अहसास कर सकें। सचिवालय सेवा के बहुत से कर्मचारी/ अधिकारी गर्व से अपने वाहनों के पीछे सचिवालय का लोगो लगाकर घूमते-फिरते हैं। फिर यदि उनसे अपनी निधारित यूनिफार्म पहनने की अपेक्षा की जा रही है तो इस स्वस्थ नजरिये से ही देखा जाना चाहिए।

मंथन

मातृभाषा बनाम अंग्रेजी की मिल्कियत

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को उनके कुछ पुराने ट्वीट के संबंध में इंटरनेट मीडिया पर उनकी अंग्रेजी का मजाक बनाया गया जो निश्चित रूप से दुखद है। इसके तमाम पहलुओं पर गौर करना जरूरी है



डा. खुशबू गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, किसी भी विषय का ज्ञान, उसकी योग्यता और अपनी समझ को अभिव्यक्त करता है। यह योग्य, विकसित और बौद्धिक कहलाने, समृद्धशाली, अभिजात होने का मानदंड नहीं है, बल्कि भाषा व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा उसके अतीत की संपदा है जो उसे श्रेष्ठ बनाती है। भाषा न केवल संस्कृति, ज्ञान, परंपरा का संवहन करती है, बल्कि विकास की प्रक्रिया में सहयोग भी करती है।

इसी संदर्भ में यदि भाषा व्यक्ति की बौद्धिकता और उसकी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए तो बहुत चिंताजनक और दुखद है। बीते दिनों नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा कर नए चेहरों को शामिल किया गया, वहीं सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखते हुए अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे डाक्टर, इंजीनियर, कानून और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले सदस्यों को वरीयता दी गई। गौरतलब है कि इन सभी नए सदस्यों में भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के कुछ पुराने ट्वीट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर उनकी अंग्रेजी का बहुत मजाक बनाया गया जो दुखद है। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जहां विविध भाषा, वेश-भूषा, संस्कृति, धर्म को समाहित किए हुए है। विविधता में एकता, इसकी मूल विशेषता के रूप में परिलक्षित होता है।

वहां इस घटना से स्पष्ट रूप से यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, आप किसी विषय के बारे में कितनी ज्यादा समझ क्यों न विकसित कर लिए हों, यदि आप उसकी अभिव्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी भाषा के कारण नहीं कर सकते तो वह सब कुछ शून्य है। आपका बौद्धिक होना निरर्थक है? आपकी योग्यता पर सवाल उठने चाहिए? और हां, ऐसा इसलिए घटित होता रहता है, क्योंकि सिर्फ इस देश में कुछ अंग्रेजों के गुलामों द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाता रहा है कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप व्यर्थ हैं। ऐसे तमाम तथाकथित अंग्रेजों से सिर्फ एक बार पूछिये कि आप हिंदी भाषा में अपने बौद्धिक विचारों को अभिव्यक्त करें तो शायद ही लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। अपवाद बहुत से होंगे जो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में कुछ ऐसे राजनेता हमारे देश में रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में असहज रहे हैं। ऐसे भी राजनेता रहें हैं सदन में जिनकी लोक भाषा को सुनकर वही तथाकथित अंग्रेज वाहवाही भी करते रहे हैं।

विगत कई वर्षों से जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य बढ़ा है, यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस किसी भी राष्ट्र में अपनी मातृभाषा का मजाक बनाया जाता है उसकी उपेक्षा व सम्मान नहीं किया जाता, वह राष्ट्र उन्नति के पथ पर बढ़ने के बजाय पतन की तरफ बढ़ता है, जहां न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बाधित होता है, बल्कि उस राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा उसका गौरवपूर्ण अतीत संकट में होता है। जिस प्रकार से हम अंग्रेजियत की तरफ बढ़ रहे हैं नई पीढ़ी के ऊपर अंग्रेजी को थोप रहे हैं, अपने आपको अभिजात बनाने की होड़ में हैं, दिखावे कर रहे हैं, हिंदी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं निश्चय ही हमारी मातृभाषा के लिए गंभीर संकट है।

इसी संदर्भ में बता दें कि खास कर शिक्षा जगत के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य बढ़ा है वह हम सभी के लिए बहुत चिंताजनक है। विचारणीय इसलिए है कि बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जो केवल अंग्रेजी भाषा की वजह से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपनी योग्यता प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो पाते ऐसे छात्रों का भविष्य क्या होगा? ऐसे छात्र यदि किसी तरह अपनी शिक्षा पूर्ण भी कर लेंगे तो क्या उनका शैक्षणिक कार्य गुणवत्तापूर्ण होगा?

देश के कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। जहां ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों का प्रवेश होता है जिन्होंने हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा में अध्यन करके उन संस्थानों में दाखिले प्राप्त किए होते हैं। लेकिन महज अंग्रेजी भाषा की समझ न होने के कारण उनकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता रहा है, आखिर क्यों? वो ऐसे प्रतिभासंपन्न छात्र होते हैं जिन्हें उनकी मातृभाषा में यदि अध्ययन करने दिया जाए तो न केवल देश में, बल्कि विश्व में अपनी अलग एक पहचान बनाने में सक्षम हो सकेंगे।

आज इजराइल, जापान और चीन जैसे विश्व में कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही कार्य करते हैं। यही वजह है कि ऐसे देश अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी भाषा को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं व विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा का कोई विरोध नहीं कर रहा है बस समझने की बात इतनी है कि भाषा को भाषा की तरह रहने दिया जाना चाहिए। किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। अध्यापन का कार्य यदि मातृभाषा में ही हो तो हमारे देश के विकास में देश की नई पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ योगदान प्राप्त हो सकेगा। भारतवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर विश्व पटल पर अपना दमखम दिखा सकता है।



मजबूत तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखते मनसुख मंडाविया। फाइल

राष्ट्रीय संस्करण

बिजनेस

सोमवार 19 जुलाई, 2021 दैनिक जागरण

www.jagran.com

भारतीय कंपनियों का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश जून में दोगुना हुआ

मुंबई: भारतीय कंपनियों का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश इस साल जून में बढ़कर 2.80 अरब डालर (20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा) हो गया। यह पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। एक साल पहले इस दौरान यह आंकड़ा 1.39 अरब डालर (10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा) था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जून 2021 में कुल विदेशी निवेश में से 1.17 अरब डॉलर गारंटी, 1.21 अरब डालर कर्ज और 42.68 करोड़ डालर शेयर-पूंजी के रूप में रहा। (प्रेट्र)

महामारी से जुड़ी अड़चनों के बाद अब मांग में 'वी' आकार का सुधार देखने को मिल रहा है। टीकाकरण अभियान के बीच धारणा सकारात्मक हुई है।

– शरद अग्रवाल, हेड, लैम्बोर्गिनी इंडिया



एक नजर में

सीआइआइ ने दिया महामारी पूल बनाने का सुझाव

नई दिल्ली: सीआइआइ ने भविष्य में कोरोना जैसी किसी भी स्थिति से निपटने को सरकार के शुरुआती वित्त समर्थन से महामारी पूल के गठन की वकालत की है। परिसंघ ने कहा, इस समय लोगों और कंपनियों के मन में कोरोना से जुड़े जोखिम सबसे ऊपर हैं। ऐसे में महामारी पूल में उनकी ओर से उचित भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। (प्रेट्र)

12.5 अरब डालर को पार कर जाएगा ओटीटी बाजार

नई दिल्ली: भारत का वीडियो ओटीटी (ओवर द टाप) बाजार वर्ष 2030 तक 12.5 अरब डालर को पार कर जाएगा। यह वर्तमान में डेढ़ अरब डालर है। सलाहकार कंपनी आरबीसीए की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने व डिजिटल संपर्क में वृद्धि से ओटीटी बाजार को मजबूती मिलेगी। ओटीटी बाजार में अब वृद्धि टियर दो, तीन और चार शहरों समेत भारतीय भाषा बोलने वाली आबादी में देखने को मिलेगी। वहीं आडियो ओटीटी की बात करें तो अभी इसका बाजार 0.6 अरब डालर है। (प्रेट्र)

कम हुआ बीएसएनएल का घाटा

नई दिल्ली: 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल का घाटा कम होकर 7441.11 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,499.58 करोड़ के स्तर पर था। 78,569 कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के चलते यह घाटा कम हुआ है। (प्रेट्र)

कोकिंग कोल पर सरकार का फैसला दूरदर्शी

मुंबई : रूस से आयात होने वाला कोकिंग कोल भारत की 50 फीसद जरूरत को पूरा कर सकता है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा ने कहा, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो फैसला किया गया है, वह बहुत ही दूरदर्शी है। इससे आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका जैसे दूर स्थित देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। (प्रेट्र)

क्रिप्टो में निवेशकों का बढ़ा रुझान

एक साल में निवेश में 600% की बढ़ोतरी, कानून को लेकर सरकार दुविधा में

राजीव कुमार • नई दिल्ली

पिछले साल अप्रैल में एक क्रिप्टोकरेंसी की कीमत 12,000 रुपये थी जो अभी 25,000 रुपये के स्तर पर है। एक साल में इस प्रकार के रिटर्न को देखते हुए ही भारतीय निवेशकों का रुझान क्रिप्टोकरेंसी को लेकर साफ देखा जा सकता है। पिछले एक साल में क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली भारतीय निवेश में 612% की वृद्धि हुई है। ब्लाकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनएनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल क्रिप्टो बाजार में भारतीयों का निवेश 92.30 करोड़ डालर का था जो एक साल में बढ़कर 6.6 अरब डालर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक डेढ़ करोड़ भारतीय क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं।

अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या 2.3 करोड़ है तो ब्रिटेन में सिर्फ 23 लाख लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार का रुख अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पिछले दो साल से सरकार के अंदर क्रिप्टोकरेंसी को लेकर उहापोह की स्थिति है। पहले सरकार क्रिप्टो को प्रतिबंधित के लिए बिल लाना चाहती थी, अब क्रिप्टो को नियंत्रित करने की बात चल रही है। तीन साल पहले आरबीआइ ने बैंकों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर रोक लगाई थी। हालांकि इससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था। 19 जून से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में भी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित बिल लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक कार्यक्रम में इसका संकेत दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

क्या है क्रिप्टोकरेंसी

यह एक तरह की डिजिटल करेंसी है। दुनिया में सैकड़ों तरह की क्रिप्टोकरेंसी हैं। भारत में मुख्य रूप से 10 प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार होता है। इसमें बिटकाइन, एथेरियम, डोजे, पोल्काडाट, बिनानसे व ट्रोन नामक क्रिप्टोकरेंसी अधिक प्रचलित हैं। क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त क्रिप्टो एक्सचेंज पर होती है। भारत में क्रिप्टो कारोबार संचालित करने के लिए छह प्रमुख एक्सचेंज हैं। इनमें वजीरएक्स, कायनडीसीएक्स, कायनस्वीच कुबेर, यूनोकायन, जेबपे और बाइयूकायन शामिल हैं। क्रिप्टो की खरीदारी के लिए एक्सचेंज पर जाकर आनलाइन एकाउंट खुलवाना होता है, जिसके लिए मात्र 100-200 रुपये का शुल्क लगता है।



क्या हैं जोखिम

दूसरे देशों की कई कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अन्य करेंसी की तरह क्रिप्टोकरेंसी कोई वैधानिक करेंसी नहीं है। कोई सरकार इसकी गारंटी नहीं लेती है।

फिर भी है आकर्षण

निवेश विशेषज्ञों के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से डिजिटल रूप में है इसलिए नौजवानों को आकर्षित करती है। सोने और प्रापर्टी में निवेश करने के बाद उसकी असलियत को लेकर दुविधा बनी रहती है। ज्वैलर्स नकली सोना भी दे सकता है। क्रिप्टो की असलियत जांचने की जरूरत नहीं है। काफी कम समय में मोटे रिटर्न की उम्मीद होती है। हालांकि विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी चिंता जता रहे हैं कि इस साल फरवरी में कुछ क्रिप्टो की कीमत 45,000 रुपये थी जो अभी 25,000 रुपये के स्तर पर है। ऐसे में 45,000 वाले क्रिप्टो को खरीदने वाले को फिलहाल घाटा ही है।

पुराने गहनों के खरीद व बिक्री मूल्य के अंतर पर देना होगा जीएसटी

नई दिल्ली, प्रेट्र: जौहरियों को पुराने सोने के आभूषणों को दोबारा बेचने पर होने वाले मुनाफे के लिए ही जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान करना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर), कर्नाटक ने यह व्यवस्था दी है। दरअसल, बेंगलुरु की आद्या गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने एएआर में आवेदन दायर कर यह जानकारी मांगी थी कि यदि कंपनी किसी व्यक्ति से पुराना सोने का आभूषण खरीदती है और बाद में बेचने के समय उस उत्पाद के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या जीएसटी का भुगतान खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर पर ही करना होगा।

एएआर की कर्नाटक पीठ ने फैसले में कहा है, जीएसटी सिर्फ बिक्री और खरीद मूल्य के अंतर पर ही देना होगा, क्योंकि आवेदक पुराने आभूषण के स्वरूप में बदलाव नहीं कर रहा है और सिर्फ उसे साफ और पालिश करके बेच रहा है। अभी जौहरी खरीदार से प्राप्त सकल बिक्री मूल्य के तीन फीसद के बराबर जीएसटी लेता है।

सरकार व श्रमिक यूनियन के बीच अब हर सप्ताह संवाद

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहले हफ्ते सभी यूनियनों से की मुलाकात, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति देने की कवायद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मैन्यूफैक्चरिंग को गति देने के लिए सरकार और श्रमिक यूनियनें अब लगातार संवाद करेंगी। इससे ना केवल कारोबार के अनुकूल औद्योगिक माहौल तैयार हो सकेगा, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में आने वाले सभी प्रकार के व्यवधान को दूर किया जा सकेगा। इस दिशा में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर शुक्रवार को श्रमिक यूनियन के साथ सीधा संवाद करने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार पिछले हफ्ते मंत्री ने हर यूनियन से मुलाकात व चर्चा पूरी कर ली। शुक्रवार से श्रमिक यूनियन संग संवाद करने का साप्ताहिक काम भी शुरू कर दिया गया है जो अब प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा। पिछले शुक्रवार को इंटक, सीटू, बीएमएस जैसे कई श्रमिक यूनियन संग श्रम मंत्री ने संवाद किया। उन्होंने बताया, श्रमिकों की समस्या के साथ औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी के लिए श्रमिक यूनियन के साथ संवाद कायम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। संवाद होने से श्रमिक यूनियन भी सरकार के नजरिये को पहले से जान रही होती है जिससे नीतिगत फैसले को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है।

श्रम मंत्रालय आने वाले महीनों में लेबर कोड (श्रम संहिता) से लेकर प्रवासी मजदूरों के पोर्टल एवं सेवा क्षेत्र के दिहाड़ी श्रमिकों की भलाई संबंधी कई फैसले लेने की तैयारी में है। श्रम संहिता को इस साल अप्रैल से ही लागू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वैसे ही, प्रवासी मजदूरों के पंजीयन के लिए पोर्टल शुरू करने की भी तैयारी फिर से जोर पकड़ने लगी है।

मंत्रालय सेवा क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की भलाई के लिए ठोस योजना बनाने पर भी गंभीर रूप से विचार कर रहा है।

आरबीआइ के पास बैड बैंक के लिए आवेदन करेगा आइबीए

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) जल्द ही रिजर्व बैंक के पास छह हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित पूंजी के साथ राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) या बैड बैंक (डूबी-संपत्तियों का बैंक) के गठन के लिए आवेदन करेगा। सूत्रों के मुताबिक आइबीए को इसके लिए लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी के पंजीकरण के बाद 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी डालने की प्रक्रिया दिशानिर्देश के तहत हो रही है। अगला कदम आडिट का होगा। उसके बाद आइबीए संपत्ति पुनर्गठन कंपनी के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन करेगा।

रिजर्व बैंक ने 2017 में पूंजी की अनिवार्यता को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया था। केंद्रीय बैंक का मानना है कि डूबे कर्ज को खरीदने के लिए कहीं अधिक राशि की जरूरत होती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शुरुआती पूंजी आठ बैंक डालेंगे। इन बैंकों ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है।

रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद एनएआरसीएल अपनी पूंजी का आधार बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये करेगी। रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद अन्य इक्विटी भागीदारों के भी इससे जुड़ने की संभावना है। आइबीए को बैड बैंक के गठन की जिम्मेदारी दी गई है। एनएआरसीएल का शुरुआती बोर्ड का गठन हो चुका है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के स्ट्रेस एसेट एक्सपर्ट पीएम नायर को प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। बोर्ड के अन्य निदेशकों में आइबीए के मुख्य कार्यपालक सुनील मेहता, एसबीआइ के उप प्रबंध निदेशक एस एस नायर और केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजित कृष्ण नायर शामिल हैं।

मुंबई से अहमदाबाद जाएगा एएएचएल का मुख्यालय

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वामित्व मिलने के कुछ ही दिन बाद अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने कंपनी के नेतृत्व में कुछ बड़े बदलाव करने का एलान किया है। इसके तहत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआइएएल) के सीईओ आरके जैन अब सीईओ एयरपोर्ट्स होंगे। इसके अलावा एएएचएल ने अपना मुख्यालय मुंबई से अहमदाबाद ले जाने का भी फैसला किया है।

समूह द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया, 'एयरपोर्ट सेक्टर में अदाणी समूह तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमें सभी के सहयोग के साथ तेजी से फैसले लेने में मदद करेगा।' कंपनी ने बताया कि जैन एमआइएएल से शुरू से जुड़े रहे हैं और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल करने में उनका बड़ा योगदान रहा है।

तिमाही नतीजों पर होगी बाजार की नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र: इस सप्ताह कंपनियों के पहली तिमाही नतीजे शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में उत्साह के अभाव से यहां उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बता दें कि बकरीद के चलते बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजित मिश्रा ने कहा, 'यह कम कारोबारी सत्रों वाला सप्ताह है। वैश्विक घटनाक्रम तथा तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। कोरोना से जुड़े घटनाक्रम तथा मानसून की प्रगति से भी बाजार का रुख तय होगा। उन्होंने कहा, इस सप्ताह रिलायंस, एसीसी, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक्नोलाजीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट तथा जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम आएंगे।



रिलायंस सहित कई बड़ी कंपनियों के इस सप्ताह आने हैं नतीजे • फाइल फोटो

एफपीआइ ने जुलाई में अब तक 4,515 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से 4,515 करोड़ रुपये निकाले हैं। इस दौरान भारतीय बाजार के प्रति एफपीआइ का रुख सतर्कता भरा रहा है। इस दौरान उन्होंने बांड बाजार में 3,033 करोड़ रुपये डाले भी हैं। इस तरह की उनकी शुद्ध निकासी 1,482 करोड़ रुपये रही। जून में एफपीआइ ने भारतीय बाजारों में 13,269 करोड़ डाले थे।

छह कंपनियों का मार्केट कैप 69,611 करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 69,611.59 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक, स्टेट बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक के पूंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई। टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल और बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन घटा है।

निवेशकों का सोने से मोह नहीं हुआ भंग

नई दिल्ली, प्रेट्र: निवेशकों ने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में जून, 2021 को समाप्त तिमाही में 1,328 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में निवेश का यह प्रवाह जारी रहेगा।

ओपेक ने पांच देशों में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी दी

दुबई, एपी: ओपेक और सहयोगी देशों ने उन पांच राष्ट्रों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिन पर पूर्व में इस संबंध में रोक लगाई गई थी। कुछ दिनों पहले यूएई ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद समूह की होने वाली बैठक को टाल दिया गया था।

रविवार को बयान में कहा गया कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) उत्पादन बढ़ाएंगे। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने कहा, जो चीज हमें एक मंच पर लाती है वह मीडिया की कल्पना से परे हैं। कई बिंदुओं पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम फिर भी एक हैं। उन्होंने इस बारे में बताने से इन्कार कर दिया कि उनके बीच आम सहमति कैसे बनी।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

54 लाख के नकली नोटों के साथ एक गिरफ्तार

भोपाल: मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने और बाजार में उन्हें खपाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। राजगढ़ जिले की पुलिस ने जीरापुर और आगर से पकड़े गए नकली नोट खपाने वाले आरोपितों की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से विजय सिंह नामक युवक को 54 लाख रुपये के नकली नोट और उन्हें छापने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। यह युवक एक करोड़ रुपये के नकली नोट छापने की तैयारी था। (नईदुनिया)

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 100 निवेशकों को करोड़ों का चूना

हिमाचल के 100 से अधिक लोगों के साथ साइबर ठगी की गई है। उन्हें पैसा 64 फीसद ब्याज के साथ लौटाने और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर दोगुने व तिगुने पैसे वापस देने का झांसा दिया गया। साइबर क्राइम एसपी संदीप धवल के अनुसार पूरा मामला दो से तीन करोड़ रुपये का निकला है। (जासं)

एआइएमआइएम का ट्विटर अकाउंट हैक, फिर बहाल

हैदराबाद: आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट रविवार को कुछ घंटों के लिए हैक हो गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बाद में अकाउंट बहाल हो गया। हैकरों ने पार्टी का प्रोफाइल नाम बदलकर 'एलन मस्क' कर दिया था और हैंडल के प्रोफाइल पिक्चर की जगह टेस्ला सीईओ की तस्वीर लगा दी। नौ दिन पहले भी पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। पार्टी ने बताया कि रविवार दोपहर एक बजे एआइएमआइएम ट्विटर अकाउंट हैक किया गया जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। (प्रेट्र)

29 साइबर मामलों के वांछित प्रमोद दिल्ली में पकड़ा गया

दुमका : 29 साइबर मामलों के वांछित दुमका के सरैयाहाट स्थित बंदरी निवासी शातिर साइबर अपराधी प्रमोद मंडल आखिरकार दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। (जासं)

क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा का हत्यारोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली

- पिछले साल वारदात कर हैदराबाद में छिपा था छैमार गिरोह का सदस्य, 10 दिन पहले बेटी के घर आया

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या का आरोपित छज्जू उर्फ बाबू खां बरेली में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। छैमार गिरोह का सदस्य छज्जू बेहद शातिर है। दिन में परिवार की महिलाओं से चादर व फूलों की फेरी के बहाने रेकी कराता, इसके बाद रात को वारदात कर देता था। अशोक कुमार के घर में भी इसी तरह डकैती डाली गई थी।

पिछले साल की थी वारदात : पिछले साल अगस्त में पंजाब के पठानकोट के थरियाल में रहने वाले अशोक कुमार के घर में छैमार गिरोह ने डाका डाला था। बेहद खतरनाक गिरोह घर में घुसते ही सदस्यों के सीधे सिर पर वार करता है। इसी तरह अशोक कुमार पर वारकर डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। 14 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिनमें 10 गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्हीं से पूछताछ के आधार पर बहेड़ी के पचपेड़ा गांव निवासी छैमार छज्जू के बारे में जानकारी मिली। उस तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस ने बरेली की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से संपर्क किया था।

बेटी के बुलाने पर आया था बहेड़ी : एसटीएफ प्रभारी अजय पाल सिंह ने बताया कि 10 दिन पहले छज्जू की बेटी रुखसार की ससुराल में शादी समारोह था। बेटी के कहने पर वह इसमें शामिल होने आया, तब से उसी के घर रह रहा था। शनिवार को सटीक जानकारी मिली तो पंजाब पुलिस को बताया। रविवार को उसे बेटी के घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे ले गई।

मदद के बहाने घर के अंदर तक घुस जाती थीं महिलाएं : छैमार गिरोह के अधिकतर सदस्य आपस में रिश्तेदार होते हैं। ये सड़क किनारे डेरा लगाकर अलग शहरों में कुछ दिन रुकते हैं। रेकी के बाद वारदात कर भाग जाते हैं। छज्जू ने स्वीकारा कि पिछले साल पठानकोट के शाहपुर काडी में डेरा लगाया था। रेकी के दौरान थरियाल में अशोक कुमार का मकान एकांत में बना दिखा। टोह लेने के लिए गिरोह की महिलाएं चादर व फूल बेचने के बहाने उनके घर के अंदर तक पहुंच गईं। वापस आकर घर के नक्शा, सदस्यों के बारे में बताया। इसके बाद डकैती डाली गई।

बेटे हैदराबाद में बेचते हैं फूल, वहीं छिपा रहा : छज्जू की सात बेटियां व चार बेटे हैं। दो बेटे बंटी व कौशर हैदराबाद के अलखनामा में चादर व फूल बेचते हैं। वारदात के बाद छज्जू वहीं चला गया था। एसटीएफ व पंजाब पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने वहां भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। इस बारे में भी पूछताछ की जा रही।

क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या में शामिल छज्जू छैमार की लोकेशन बहेड़ी के पचपेड़ा में मिली थी। उसकी बेटी के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस उसे अपने साथ ले गई है।

-अजयपाल सिंह, एसटीएफ प्रभारी, बरेली ईकाई।

तीन आरोपित फरार, गिरोह में महिलाएं भी

अब तक सावन उर्फ मैचिग निवासी औरैया (उप्र), शाहरुख खान उर्फ लुकमान, जबराना व मोहब्बत निवासी राजस्थान, रिहान उर्फ सोनू निवासी राजस्थान, असलम निवासी अमृतसर, तवजल व काजम निवासी सहारनपुर (उप्र), चाहत निवासी कानपुर (उप्र), साजन उर्फ आमिर निवासी सहारनपुर (उप्र) पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। अभी गोलू निवासी धलापड़ा गंगोह सहारनपुर (उप्र), रशीद निवासी प्लानी झुनझुनु राजस्थान व वाफिला निवासी सुल्तान भिंड मंडी भगवतावली अमृतसर फरार हैं। छज्जू छैमार करीब 15 साल पहले जंगल में वन्यजीवों का शिकार करता था जेल जा चुका है।

फर्जी बाबा की निशानदेही पर 72 लाख के जेवर बरामद

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश

ज्वेलर की पत्नी के उपचार के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी बाबा प्रियव्रत अनिमेष उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रोबिन खलीफा की निशानदेही पर पुलिस ने 72 लाख रुपये मूल्य के जेवर बरामद किए हैं। इससे पहले आरोपित की गिरफ्तारी वाले दिन नौ लाख रुपये के जेवर बरामद किए गए थे। पुलिस ने आरोपित का तीन दिन का रिमांड लिया था, जो रविवार को पूरा हो गया।

इसी 10 जुलाई को पंवार ज्वेलर्स के संचालक हितेंद्र सिंह पंवार ने कोतवाली में आजाद नगर पानीपत हरियाणा निवासी प्रियव्रत अनिमेश के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। वह यहां संत के भेष में लालतप्पड़ स्थित नेचर विला में किराये का फ्लैट लेकर रह रहा था। आरोप है कि उसने ज्वेलर्स की पत्नी का मानसिक इलाज करने का झांसा देकर वर्ष 2019 में जेवरात और नकदी ठगनी शुरू की, जो अब भी जारी थी। हालिया दिनों में स्टाक मिलान करने पर ज्वेलर्स को इसका पता चला। तब पत्नी ने सारी हकीकत बताई। आरोप है कि फर्जी बाबा ने ज्वेलर्स की पत्नी से रुद्राक्ष की माला, सोने का ब्रेसलेट, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, सोने की माला, सोने की चार अंगूठी, तुलसी की माला समेत लाखों रुपये के जेवर और 27 लाख नकदी ठगी।

पुलिस ने उसी दिन आरोपित को उसके लालतप्पड़ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। यहां से पुलिस को करीब नौ लाख रुपये के आभूषण मिले थे, इनमें से कुछ आभूषण आरोपित ने पहने हुए थे। तीन दिन पहले पुलिस ने अदालत से आरोपित का रिमांड हासिल किया था। पुलिस अधीक्षक देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपित को देहरादून, दिल्ली, पानीपत और करनाल स्थित ठिकानों पर लेकर गई। ठगे गए सभी जेवर बरामद कर लिए गए हैं।

सेल्फी लेने में शबरी जल प्रपात में डूबे चार दोस्त, तीन की मौत

संवाद सहयोगी, मानिकपुर (चित्रकूट)

- मोटरसाइकिल से आए थे पिकनिक मनाने, सेल्फी लेते समय हुआ हादसा

शबरी जल प्रपात के तेज बहाव में बहकर चार दोस्त 15 फीट गहरे कुंड में डूब गए। सेल्फी लेने के चक्कर में हुए हादसे में तीन की मौत हो गई और एक को सुरक्षित बचा लिया गया है। सभी पड़ोसी बांदा जिला के अतर्रा के रहने वाले थे।

अतर्रा के नरैनी रोड स्थित नगर पालिका के पास रहने वाले किराना व्यवसायी विद्यासागर साहू के 22 वर्षीय पुत्र पीयूष रविवार को अपने 12-13 साथियों के साथ वीकेंड पर पिकनिक मनाने के लिए सुबह करीब छह बजे निकले थे। पूर्वाह्न 11 बजे घूमते हुए शबरी जल प्रपात पहुंचे। वहां बाइक खड़ी कर सभी नहाने लगे। पीयूष अपने पड़ोसी 16 वर्षीय मोहित पुत्र देवेंद्र साहू, 17 वर्षीय साहिल पुत्र अशोक साहू और 25 वर्षीय आकाश पुत्र दिनेश साहू के साथ झरने के नीचे उतर गए। वहां स्नान के साथ वो सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान चारों एक साथ झरना पार करने लगे। तभी तेज बहाव में एक-एक कर बह गए। दोस्तों को पुकारा, लेकिन झरने से गिरते पानी के शोर में किसी ने सुना नहीं। बाद में उन्हें डूबते देख दोस्त बचाने दौड़े। मोहित, साहिल व आकाश को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पीयूष डूब चुका था। तीनों को अस्पताल भेजा गया। मोहित व साहिल को मध्य प्रदेश के मझगंवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में मृत घोषित कर दिया गया जबकि पीयूष का शव करीब तीन घंटे बाद कुंड से निकाला गया। आकाश का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मानिकपुर में चल रहा है। यह साल भर में दूसरी घटना है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण लोग अक्सर डूबने की घटनाएं होती हैं। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारीजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को नियमानुसार अनुमन्य राहत राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।

गैरकानूनी रूप से रुके नौ ईरानी गिरफ्तार, जाली आधार कार्ड बरामद

चेन्नई, प्रेट्र : नौ ईरानी नागरिकों को गैरकानूनी रूप से चेन्नई में रुकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से जाली आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा कि एक सोमालियाई नागरिक से लूटपाट के एक मामले में तीनों की भूमिका सामने आने के बाद इस मुद्दे का पता चला। चेन्नई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन महिलाएं शामिल हैं। सभी नौ लोग समुद्र के किनारे स्थित कस्बे कोवलम के एक रिसार्ट में ठहरे हुए थे। यह मामला तीन लोगों की जांच के क्रम में प्रकाश में आया।

सेंट्रल पुलिस का दावा है कि तीनों ने हाल ही में एक सोमालियाई नागरिक से नार्कोटिक पदार्थ की जांच के बहाने 3800 डालर (दो लाख 83 हजार रुपये से अधिक) लूट लिए। 61 वर्षीय सोमालियाई नागरिक आंख का इलाज कराने के लिए चेन्नई आया हुआ था। उसने थाउजैंड लाइट पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। टीम ने इस्तेमाल की गई कार का पता लगाया और आगे की जांच में नौ लोग पकड़े गए।

दुबई-कोलकाता की फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

दहशत

- जांच की गई तो संदेश झूठा निकला, पड़ताल शुरू
- फ्लाइट को चेक कर करीब तीन घंटे बाद किया रवाना

सैन्य संपर्क इकाई की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। हालांकि, जब जांच की गई तो यह संदेश झूठा निकला। दुबई-कोलकाता की उक्त फ्लाइट से सभी 145 यात्रियों को तत्काल बाहर निकालने के बाद विमान की सघन जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस अफवाह की वजह से फ्लाइट काफी देर बाद गंतव्य के लिए फिर से उड़ान भर सकी।

रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे सैन्य संपर्क इकाई (एमएलयू) ने कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों को सूचित किया कि विदेश से आने वाली या फिर यहां से चीन व दक्षिण पूर्व एशिया को जाने वाली किसी फ्लाइट में बम है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस फ्लाइट में बम है। इसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और सभी आवश्यक कार्रवाई शुरू हो गई। करीब 8:05 बजे दुबई से आ रही एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या ईके 570 कोलकाता लैंड कर गई। एमएलयू की ओर से सुबह 7:55 बजे कोलकाता एयरपोर्ट प्रबंधन को फिर से कॉल किया और धमकी फर्जी होने की बात कही गई, लेकिन तब बम निरोधी टीम रनवे पर पहुंच चुकी थी। बम की खबर आग की तरह सभी अधिकारियों के बीच फैल चुकी थी। उक्त विमान के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे अलग ले जाया गया और सभी यात्रियों को उतारकर जांच शुरू की गई। हालांकि कुछ नहीं मिला है। जांच के बाद विमान को सुबह 10.06 बजे चार यात्रियों के साथ उड़ान दुबई के लिए रवाना हो सकी। अब जांच की जा रही है कि सैन्य संपर्क इकाई को यह गलत सूचना किसने दी और क्यों दी।

घरों में पालतू पशु रखने पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा कोर्ट

कोच्चि, प्रेट्र : आवासीय सोसायटी व आरडब्ल्यूए की तरफ से घरों में पालतू पशु रखने पर लगाए गए प्रतिबंध का मामला केरल हाई कोर्ट पहुंच गया है।

पीपुल फार एनिमल्स (पीएफए) की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है, 'इस प्रकार के संगठन देश के कानून से इतर न तो कोई कानून बना सकते हैं न ही संशोधन कर सकते हैं।' याचिका में पीएफए ने कहा है कि उसे कई आवासीय सोसायटी व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा घरों में पालतू पशुओं को रखने पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ काफी शिकायतें मिली हैं। यहां तक कि इन संगठनों ने घर मालिकों को नोटिस भेजकर पालतू पशुओं का त्याग करने को कहा है। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत ऐसा करने के लिए मजबूर करना अपराध है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने 2015 में कहा था कि पालतू पशु किसी अन्य के लिए बाधक न बनें, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया था कि पालतू पशुओं को त्यागने के लिए मजबूर करना अपराध है।

5000 नए मामले रोज मिल रहे हैं फ्रांस में कोरोना के बीटा वैरिएंट के। यह वैरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला था। विशेषज्ञों के अनुसार, इस वैरिएंट पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रभावी होने की संभावना कम है।

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने निभाई पड़ोसी की भूमिका

एक पड़ोसी की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत ने अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही वहां फिर तालिबान पैर पसारने लगा है। तालिबान ने वहां के 85 फीसद इलाके में कब्जा करने का दावा किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के निर्देश पर तालिबान ने भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे वहां चल रहे कई प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा गए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर असर पड़ने की आशंका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2020 में जेनेवा में अफगानिस्तान कांफ्रेंस में कहा था, 'अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में हमारे 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वहां पूरे देश में फैले हैं।' 20 लाख लोगों को साफ पानी के लिए भारत की ओर से काबुल में शहतूत डैम बनाने और 600 करोड़ रुपये के करीब 100 प्रोजेक्ट पर भी समझौता हुआ है। अफगानिस्तान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर नजर :



दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल देता है सलमा बांध

42 मेगावाट का यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बना है। 2016 में इस हाइड्रोपावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। इसे अफगान-भारत मैत्री बांध के नाम से भी जानते हैं। पिछले कई हफ्तों में इसके आसपास तालिबान लगातार हमले कर रहा है, जिसमें कई सुरक्षाबलों की भी मौत हुई है।

स्टोर पैलेस : इसको पुनर्स्थापित करने के बाद वर्ष 2016 में अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल में इसका उद्घाटन किया था। भारत ने इसके निर्माण में सहयोग किया था।

अफगानिस्तानी संसद : भारत ने काबुल में अफगान संसद को करीब 675 करोड़ रुपये में तैयार कराया है। 2015 में अफगानिस्तान की संसद को खोला गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।





जेरांज-देलाराम हाईवे का निर्माण

218 किलोमीटर के इस हाईवे को बीआरओ ने बनाया था। इसे करीब 1125 करोड़ की लागत से बनाया गया। यह सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार के लिए यह ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में जाने का वैकल्पिक रास्ता है। कोरोना महामारी में भारत ने 75 हजार टन गेंहू इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया है। इस हाईवे के निर्माण में 11 भारतीय और 129 अफगानिस्तानी लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

परिवहन में मदद

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत ने अफगानिस्तान में 400 बस, 200 मिनी बस, नगर पालिकाओं को 105 गाड़ी दी है। साथ ही अफगान सेना को 285 वाहन दिए हैं। पांच शहरों को 10 एंबुलेंस भी दी गई है।

हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सहयोग

1972 में काबुल में बनाए गए बच्चों के अस्पताल का भारत ने फिर से निर्माण कराया। साथ ही अलग-अलग प्रांतों में भारत ने कई क्लीनिक बनाए हैं।

अन्य कई परियोजनाओं पर भी काम

भारत ने स्कूलों के लिए डेस्क, बेंच और पिछड़े इलाकों में सोलर पैनल के साथ ही काबुल में सुलभ टायलेट ब्लाक बनाए हैं।

बिजली क्षेत्र में कार्य

बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए पुल-ए-खुमरी से नार्थ काबुल तक 220 किलोवाट की डीसी ट्रांसमिशन लाइन की भारत ने पुनर्स्थापना की। साथ ही संचार सुविधाएं भी कई इलाकों में मजबूत की गईं। (मीडिया इनपुट)

जंग के बीच राजनीतिक समझौते के पक्ष में तालिबान

- आतंकी संगठन के सरगना हिबतुल्लाह ने 'डेली पाकिस्तान' से कही यह बात
- अफगानिस्तान के 15 प्रांतों में भीषण संघर्ष, 24 घंटे में 284 आतंकी मरे

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही वार्ता के शुरू होने के बाद तालिबान के सुर बदल रहे हैं। तालिबान के सुप्रीम नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा है कि वे मौजूदा संघर्ष को रोकने के लिए राजनीतिक समझौते का पुरजोर समर्थन करते हैं।

दोहा में एक दिन पहले ही तालिबान और अफगानिस्तार सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता शुरू हुई है। वार्ता का पहला दौर शुरू होने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ रही है कि हिंसा के वर्तमान हालात में समझौते की कोई राह निकल सकती है। इसको लेकर तालिबान ने भी सकारात्मक संदेश दिया है।

डेली पाकिस्तान के अनुसार ईद से पहले तालिबान प्रमुख का आधिकारिक बयान आया है। बयान में हिबतुल्लाह ने कहा है कि संघर्ष में आगे रहने के बाद भी इस्लामिक अमीरात देश में राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। हिबतुल्लाह ने कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन विपक्षी समय खराब कर रहे हैं। हमें विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय आपस में बात करके अपनी मातृभूमि को बचाना चाहिए। इससे पहले अफगान प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के बीच पहले दौर की वार्ता हुई। इस वार्ता में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी मौजूद थे।

दूसरी ओर 15 प्रांतों में जंग और तेज हो गई है। तालिबान ने परवान प्रांत के शेख अली जिले को आतंकियों से मुक्त करा लिया है। तालिबान ने कंधार प्रांत में दांड जिले पर कब्जा कर लिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 284 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हो गए हैं। कई प्रांतों में तालिबान सेना पर भारी पड़ रहे हैं। फरयाब प्रांत के सभी जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया है।

तालिबान की जीत से मजबूत होगा अलकायदा

काबुल, आइएएनएस : इस्लामिक राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि कि तालिबान इस बार अधिक मजबूती के साथ अफगानिस्तान में स्थापित हो सकता है। तालिबान की जीत का सीधा मतलब अलकायदा को मजबूती मिलना है। ग्लोबल इस्लामिक पालिटिक्स, डीकिन यूनीवर्सिटी के चेयरमैन ग्रेग बार्टन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबान अगर सत्ता पर काबिज होता है तो यह सीरिया और इराक में अलकायदा से ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा। अमेरिकी सेना की वापसी जिस तरह से हुई है, उससे अफगान सेना का मनोबल टूटा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल में पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने बिचौलिए के माध्यम से अलकायदा के प्रमुख नेता का साक्षात्कार प्रकाशित किया, उससे स्पष्ट है कि तालिबान का संबंध अलकायदा से बना हुआ है। अमेरिका के 2006 से 2011 तक रक्षा मंत्री रहे राबर्ट गेट्स ने भी अमेरिकी अखबार में लिखा है कि हमने अफगानिस्तान से सेना वापसी में रणनीतिक रूप से गलती की है। चुनौतियों को कम करके आंका है।

अफगान राजनयिक की पुत्री के अपहरण में पाक पर दबाव

अफगानिस्तान के राजनयिक की पुत्री सिलसिला अलीखिल के अपहरण और यातना देने के मामले में पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना में एक और टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पाक के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि दोषियों को 72 घंटे में पकड़ लिया जाएगा। इधर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस घटना की निंदा की है। अफगानिस्तान की महिला सांसदों ने पाकिस्तान की महिला सांसदों को इस शर्मनाक घटना पर पत्र लिखकर कहा है कि वह अपनी सरकार पर दोषियों को पकड़ने के लिए दबाव बनाएं।

तालिबान की छवि बनाने में लगे हुए हैं पाक राजनयिक

एएनआइ के अनुसार अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक बार फिर पाक को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि पाक के राजनयिक तालिबान की अच्छी छवि बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

अफगान सहयोगियों की निकासी कुछ दिन में ही

अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि सेना के साथ काम करने वाले अफगान सहयोगियों को जुलाई के अंतिम सप्ताह से सुरक्षित स्थानों पर बाहर भेजना शुरू कर दिया जाएगा।

महंगाई का मारा पाक, पेट्रोल के साथ आटा-चीनी के बढ़े दाम

इस्लामाबाद, एएनआइ : पेट्रोल-डीजल के बाद पाकिस्तान में अब बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच चीनी, गेहूं के आटे, घी समेत खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच, नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुलाम कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि पिछली सरकारों ने देश को अपने पैरों पर खड़े करने के बजाय हमेशा ही सहायता और कर्ज लेने पर ही भरोसा किया है। जबकि कोई भी देश भीख का कटोरा लेकर कभी भी महान नहीं बन सकता है।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन (यूएससी) में चीनी, गेहूं का आटा और घी (मक्खन) की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी। यूएससी में चीनी की कीमत 68 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 85 रुपये प्रति किलो, घी (मक्खन) 170 रुपये से 260 रुपये प्रति किलो और गेहूं का आटा 850 रुपये प्रति बैग से बढ़कर 950 रुपये प्रति बैग हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कारपेरिशन की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी वाली कीमतों और बाजार की मौजूदा कीमतों के बीच का अंतर बढ़ गया है।

समिति ने यूएससी द्वारा सब्सिडी के प्रविधान को युक्तिसंगत बनाने के लिए तीन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संशोधन को मंजूरी दी। द न्यूज इंटरनेशनल ने आगे बताया कि वित्त और राजस्व मंत्री शौकत तारिन ने समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने 200,000 टन चीनी के आयात, कपास और चावल की फसलों के लिए डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी और पाकिस्तान के व्यापार निगम द्वारा 200,000 कपास गांठों की खरीद को भी मंजूरी दी। इससे पहले गुरुवार को इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5.40 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 2.54 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। डान ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है। अभी तक पेट्रोल की नई कीमत 118.09 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 116.5 रुपये प्रति लीटर होगी।

इस बीच, मिट्टी के तेल और हल्के डीजल तेल (एलडीओ) की कीमतों में क्रमशः 1.39 रुपये और 1.27 रुपये की बढ़ोतरी हुई। केरोसिन की नई कीमत 87.14 रुपये और एलडीओ की 84.67 रुपये होगी। राजनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक (एसएपीएम) शाहबाज गिल ने यह घोषणा की।



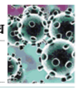
आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में भी महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हैं। एएफपी

ब्रिटेन में नहीं कम हुए मरीज, एक दिन में 54 हजार कोरोना संक्रमित

लंदन, एएनआइः ब्रिटेन में कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 54 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए। मरीजों में कमी न होने के बाद भी यहां 19 जुलाई से अधिकांश प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं।

ब्रिटेन में तेजी से चल रहे टीकाकरण के बाद भी शुक्रवार को 51870 मरीज मिले। यह संख्या जनवरी के मध्य में मिले मरीजों की संख्या से ज्यादा थी। अब पिछले 24 घंटों में यह संख्या 54674 हो गई है। यानी तीन में 2804 मरीज ज्यादा मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने ट्वीट करके कहा है कि उनके दोनों वैक्सीन लग गई थीं, इसलिये संक्रमण होने के बाद उनको हल्के लक्षण हैं। ब्रिटेन में 19 जुलाई सोमवार से लाकडाउन के अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। आइएएनएस के अनुसार ब्रिटेन के 87.8 फीसद वयस्क वैक्सीन की एक डोज और 67.8 फीसद वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। यहां 2 से 16 साल के बच्चों को फ्लू की वैक्सीन देने की योजना है। थाइलैंड में मरीजों की संख्या बढ़ने से लाकडाउन का विस्तार किया गया है। यहां एक दिन में 11 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले हैं।

- सोमवार से ही हटाए जाएंगे अधिकांश प्रतिबंध
- थाइलैंड में लाकडाउन का क्षेत्र बढ़ाया गया



ब्राजील : रोजाना 34 हजार से ज्यादा केस आ रहे हैं। 24 घंटे में 868 की मौत हुई।

आस्ट्रेलिया : सिडनी व विक्टोरिया में मरीजों की संख्या में कमी आई है, दोनों ही राज्यों में अभी लाकडाउन जारी है।

रूस : एक दिन में 764 की मौत हो गई। 25 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले हैं।

ब्रिटेन के पीएम फिर हुए क्वारंटाइन

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के पीएम बोरिस जानसन और वित्तमंत्री ऋषि सुनक भी में कोरोना संक्रमण की चपेट म आ गए हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, जिसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दोनों नेता क्वारंटाइन हो गए हैं। टेस्ट और ट्रेसिंग सिस्टम से जानसन व सुनक के कोरोना मरीज के संपर्क में आने का पता चला। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने ट्वीट किया पीएम को हल्के लक्षण हैं। ज्ञात हो, शनिवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री जाविद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पीएम निवास ने कहा है कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद जानसन व सुनक को वर्कप्लेस पाइलट स्कीम के तहत कार्यालय से कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।



बोरिस जानसन (फाइल)। रायटर

नेपाल में देउबा ने हासिल किया विश्वास मत

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। नेपाली कांग्रेस प्रमुख देउबा की सरकार के पक्ष में 165 वोट पड़े। 83 सांसदों ने नवगठित सरकार के विरोध में मतदान किया। इस तरह सरकार ने आसानी से संसद में अपना बहुमत साबित कर दिया। संसद की प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य हैं।

देउबा ने 13 जुलाई को रिकार्ड पांचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पांच माह के भीतर दूसरी बार संसद को बहाल करने का आदेश दिया था। संसद के निचले सदन में नेपाली कांग्रेस के 61 सदस्य हैं, जबकि उसकी गठबंधन साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 48 सदस्य हैं। मुख्य विपक्षी ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल के 121 सदस्य हैं, जबकि जनता समाजवादी पार्टी के 32 सदस्य हैं। इसके अलावा तीन छोटी पार्टियों के एक-एक सदस्य हैं। एक निर्दलीय सांसद भी है।

कोविड की लैब-लीक थ्योरी पर बाइडन सरकार की राय बदली

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका में जो बाइडन की डेमोक्रेट सरकार ने 'चीनी वायरस' के कथित लीक पर बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी राय बदल ली है। साल भर पहले ही डेमोक्रैटों ने लैब-लीक की थ्योरी का मजाक बनाया था। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के वायरस के वुहान की लैब से दुर्घटनावश फैलने के सिद्धांत वैध मानते हुए उसे उतना ही संभव माना है जितना कि जंगल में प्राकृतिक तरीके से आग लगना हो सकता है।

हाल के महीनों में लैब-लीक के सिद्धांत को इतनी अधिक हवा मिली कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से 90 दिनों के अंदर वायरस के संक्रमण के स्रोत का पता लगाने की जांच रिपोर्ट तलब की थी। सीएनएन के मुताबिक अब अमेरिकी खुफिया समुदाय भी इस बात को लेकर बंटा हुआ है कि वुहान की लैब से वायरस लीक हुआ है या फिर प्राकृतिक रूप से जानवरों से इंसानों में पहुंच गया है।

सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कोई भी एक दिशा निर्धारित करने के लिए नए सुबूत बहुत कम हैं। लेकिन बाइडन प्रशासन के बड़े अफसर लैब में वायरस के लीक होने के सिद्धांत को गंभीरता से ले रहे हैं और इस विचार को बेहद खुलेपन से देख रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना वायरस पर अध्ययन करने वाले और संक्रमण के स्रोत पर रीसर्च करने वाले कई वैज्ञानिक इसका स्रोत प्राकृतिक मानते हैं। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा समय में खुफिया प्रशासन का मानना है कि वायरस संभवतः प्राकृतिक तरीके से ही जानवरों से इंसानों के संपर्क में आया है। उनका मानना है कि इसे जानबूझकर लैब में तैयार नहीं किया गया है। लेकिन आम चर्चाओं में लैब-लीक की थ्योरी पर गहन विश्वास के चलते अब कई प्रख्यात वैज्ञानिक चाहते हैं कि वायरस के स्रोत को लेकर पूर्ण रूप से गहन जांच होनी चाहिए।

कान में जूलिया डुकोर्नी को टाइटेन के लिए पाम डओर अवार्ड

कान, प्रेट्र : इस साल हुए 74वें कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्देशक जूलिया डुकोर्नी को फिल्म 'टाइटेन' के लिए पाम डओर अवार्ड दिया गया। पूरे 28 सालों बाद किसी महिला को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। 37 वर्षीय फ्रेंच निर्देशक डुकोर्नी की यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई हारर और ड्रामा श्रेणी की है।

फ्रेंच फिल्म निर्देशक जूलिया डुकोर्नी ने अपनी फिल्म 'टाइटेन' के लिए पामे डओर जीता, जिसे नियान ने इस साल रिलीज किया। वह कान फिल्म फेस्टिवल का ये सबसे बड़ा अवार्ड जीतने वाली अब तक की दूसरी महिला निर्देशक बन गई हैं। इससे पहले साल 1993 में 'द पियानो' फिल्म के लिए जेन कैंपियन ने अवार्ड जीता था।

इस साल की जूरी के पास चुनने के लिए कई सारी फिल्में थीं, जिनमें लेओस कैरैक्स, वेस एंडरसन, जूलिया डुकोर्नी, पाल वेरहोवेन, असगर फरहादी, सीन बेकर की नई फिल्में और बहुत सारी फिल्में इस फेस्टिवल में मुकाबले का हिस्सा थीं। परंपरा के अनुसार, कान फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े विजेता रविवार को फ्रांस में रहने वालों के लिए एक बार फिर से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे।

जूरी ने इस साल भी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कान फेस्टिवल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार दिया है। पुरस्कार तय करने वाले जूरी मेंबर के अध्यक्ष स्पाइक ली थे और उनके साथ जूरी मेंबर्स में फिल्म निर्देशक माटी डियोप, गायक/गीतकार मायलेन फार्मर, अभिनेत्री/निर्देशक मैगी गिलेनहाल, लेखक/निर्देशक जेसिका हासनर, अभिनेत्री/निर्देशक मेलानी लारेंट, लेखक/निर्देशक क्लेबर मेंडोंका फिल्हो, अभिनेता ताहर रहीम और अभिनेता सांग कांग-हो शामिल थे।

28 सालों बाद किसी महिला को मिला फ्रांस फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड



जूलिया डुकोर्नी। एपी



रेनेट रीन्सवे। एपी



कालेब लैंड्री जोन्स। एपी

पायल कपाड़िया ने जीता सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र अवार्ड



आइएएनएस के मुताबिक कान फिल्म समारोह में मुंबई की फिल्मकार पायल कपाड़िया को उनके वृत्तचित्र 'ए नाइट आफ नोइंग नथिंग' के लिए सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री के अवार्ड ओल डओर (गोल्डन आइ) से सम्मानित किया गया है। 'ए नाइट आफ नोइंग नथिंग' एक ऐसी कालेज छात्रा की कहानी है जो अपने प्रेमी के दूर रहने पर उसे कई प्रेम पत्र लिखती है। इस बार इस वैश्विक समारोह में दुनिया भर से वृत्तचित्र की श्रेणी में 28 प्रविष्टियां थीं। अमेरिकी डाक्यूमेंट्री की निर्माता एजरा एडलमैन पांच सदस्यीय ज्यूरी की प्रमुख थीं। ज्यूरी के अन्य लोगों में फ्रांस की फिल्मकार जूली बर्टस्ली, फ्रांस के अभिनेता डेबरा फ्रैंकोसिस, फ्रांसीसी व अमेरिकी फिल्म आलोचक आइरिस ब्रे और ओरवा नारयरबिया शामिल हैं।

अवार्ड की सूची

- पाम डओर : 'टाइटेन'
- ग्रांड प्रिक्स : (टाई) 'ए हीरो' और 'कपार्टमेंट नंबर-6'
- जूरी प्राइज : (टाई): 'अहेड्स नी' और 'मेमोरिया'
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : रेनेट रीन्सवे, 'दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति'
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : कालेब लैंड्री जोन्स, 'निट्राम'
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : लेओस कैरैक्स, 'एनेट'
- सर्वश्रेष्ठ पटकथा : रयूसुके हमागुची, 'ड्राइव माई कार'
- कैमरा डओर : एंटोनेटा अलमत कुसीजानोविक की 'मुरिना'
- शार्ट फिल्म पाम डओर : तांग यी की 'तियान झिया वु या'
- स्पेशल जूरी मेंशन शार्ट फिल्म: जैस्मीन टेनुची की 'सेउ डे एगोस्टो'

यूरोप में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 184 हुई

फ्रैंकफर्ट, रायटर : पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से मरने वालों की संख्या रविवार को 183 से ऊपर पहुंच गई, जब बचावकर्मियों ने पानी घटने से छोड़े गए मलबे में गहराई तक खोदाई की।

पुलिस ने पश्चिमी जर्मनी के राइनलैंड-पैलेटिनेट राज्य के अहरवीलर इलाके में मरने वालों की संख्या 110 से अधिक बताई और कहा कि उन्हें आशंका है कि यह संख्या अभी भी बढ़ सकती है। जर्मनी के सबसे अधिक आबादी वाले नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य में, चार अग्निशमन वालों सहित 45 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और बेल्जियम ने 27 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है।

चांसलर एंजेला मर्केल रविवार को बाद में अहरवीलर के पास एक गांव शुल्ड का दौरा करने वाली थीं, जो बाढ़ से तबाह हो गया था। उनकी यात्रा जर्मनी के राष्ट्रपति के शनिवार को क्षेत्र में जाने और स्पष्ट करने के बाद हुई है कि उसे दीर्घकालिक समर्थन की आवश्यकता होगी।

जर्मनी के राज्य नार्थ राइन-वेस्टफेलिया में 45 लोगों की मौत और बेल्जियम में 27 लोग हताहत



जर्मनी की चांसलर एंजेल मर्केल ने रविवार को शुल्ड गांव का दौरा किया और बारिश-बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। एपी

वित्त मंत्री ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि वह बुधवार को एक कैबिनेट बैठक में तत्काल सहायता के पैकेज का प्रस्ताव देंगे। इसमें बिल्ड एम. सोनटैग अखबार को बताया गया है कि 30 करोड़ यूरो से अधिक की आवश्यकता होगी।

हालांकि जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में बारिश रुक गई है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के अन्य हिस्सों में तूफान और बारिश जारी है। जर्मनी-चेक सीमा क्षेत्र में, देश भर में, जहां से पिछले सप्ताह बाढ़ आई थी और जर्मनी के दक्षिण-पूर्वी कोने में और ऑस्ट्रिया में सीमा पर शनिवार की रात बाढ़ आ गई थी। जर्मनी के बेर्चटेस्गेडेन इलाके में आचे नदी में बाढ़ आने के बाद 65 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई।

आस्ट्रिया के निकटवर्ती शहर हैलेन में शनिवार देर रात अचानक बाढ़ आ गई, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आस्ट्रिया के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान ने गंभीर नुकसान पहुंचाया।

जलवायु विज्ञानियों का कहना है कि चरम मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के बीच की कड़ी अचूक है और जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ करने की तात्कालिकता को नकारा नहीं जा सकता है।

अमेरिका में कई स्थानों पर फायरिंग, वाशिंगटन में चार को मारी गई गोली

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका में फिर गोलीबारी की कई घटनाएं हुईं। वाशिंगटन के नेशनल स्टेडियम के बाहर चार लोगों को गोली मार दी गई। सैकरामेंटो में दो लोग मारे गए। पोर्टलैंड में गोलीबारी की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।

वाशिंगटन में गोलीबारी की घटना बेसबाल के मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर हुई। यहां वाशिंगटन नेशनल्स और सैन डिएगो पैड्रेस के बीच मैच चल रहा था। गोलियों की लगातार आ रही आवाज के साथ ही मैच को रोक दिया गया।

पुलिस के अनुसार गोलीबारी की जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर आगे कोई खतरे की बात नहीं है। जिन लोगों को गोली लगी है, उनमें से दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

इमरान खान ने किया पीएम मोदी और संघ पर हमला

- भाजपा और संघ की विचारधारा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा : पाक पीएम

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संघ (राष्ट्रीय स्वयं सेवक) फोबिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिनों के अंदर उन्होंने दूसरी बार संघ के विरुद्ध बयानबाजी की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान इमरान ने खुद को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर बताया।

इससे पहले 16 जुलाई को उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कांफ्रेंस में पहुंचे इमरान से जब सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकती है? इस पर पाकिस्तानी पीएम ने कहा, 'भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हम साया (सभ्य पड़ोसी) बनकर रहें। पर करें क्या, संघ की विचारधारा रास्ते में आ गई।' इमरान खान 17 जुलाई को गुलाम कश्मीर के बाघ इलाके में चुनाव से जुड़ी पहली जनसभा में गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, 'भाजपा और संघ की विचारधारा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा-संघ की विचारधारा केवल मुस्लिमों को ही निशाना नहीं बनाती, बल्कि ये सिखों, ईसाइयों को भी निशाना बनाती हैं, वो इन लोगों को भी बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं।'

इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि पांच अगस्त, 2019 के बाद कश्मीर में जुल्म बढ़ गए हैं। इमरान बोले कि वे हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके संघर्ष में हमेशा साथ खड़े रहेंगे।





अब क्या कहेंगे रणतुंगा

- जिस भारतीय टीम को दूसरे दर्जे की बताया वो जीती
- धवन व इशान के अर्धशतक, पृथ्वी की शानदार पारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जो भारतीय टीम गई है उसे श्रीलंका के विश्व विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने दूसरे दर्जे की टीम बताया था। रणतुंगा ने श्रीलंका क्रिकेट की आलोचना करते हुए इस टीम के खिलाफ खेलना अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का अपमान बताया था। इस भारतीय टीम ने रविवार को कोलंबो में पहले वनडे मैच में श्रीलंका को सात विकेट से ना सिर्फ हराया, बल्कि 263 रन का लक्ष्य सिर्फ 36.4 ओवर में हासिल कर लिया। अब रणतुंगा क्या कहेंगे?

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टास जीतकर भारत को पहले गेंदबाजी सौंपी। तेज गेंदबाज दीपक चाहर (2/37) और कुलचा के नाम से प्रसिद्ध कुलदीप यादव (2/48) और युजवेंद्रा सिंह चहल (2/52) की स्पिन जोड़ी के आगे श्रीलंका की टीम नौ विकेट पर 262 रन ही बना सकी। क्रुणाल पांड्या ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर एक विकेट लिया। श्रीलंका की ओर से आठवें नंबर के बल्लेबाज चमिका करुणारत्ने नाबाद 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। जवाब में भारत ने पहली बार कप्तानी करने वाले शिखर धवन और पदार्पण वनडे खेलने वाले युवा विकेटकीपर इशान किशन के अर्धशतकों की बदौलत एकतरफा जीत हासिल की। धवन 95 गेंदों पर छह चौकों व एक छक्के की मदद से 86 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि किशन ने 42 गेंदों पर आठ चौकों व दो छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा ने 24 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 43 रन बनाकर भारत की जीत की नींव तैयार की, जिसके लिए उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया।

भारत के लिए लक्ष्य आसान था एवं उसके बल्लेबाजों ने उसे और आसान बना दिया। युवा पृथ्वी शा ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई, लेकिन वह अपने अर्धशतक से चूक गए। वह छठे ओवर में बड़ा शाट खेलने की कोशिश में धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर लपके गए। उस समय भारत का स्कोर 58 रन था। किशन ने आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ वनडे क्रिकेट में आगाज किया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका भी जड़ा। इशान काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। उन्होंने आठवें ओवर में धनंजय पर लगातार तीन चौके जड़े। उन्होंने 15वें ओवर में चरित असलंका पर लगातार दो चौके जड़कर 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, इसके बाद वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और लक्षण संदाकन की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसके बाद धवन ने मनीष पांडे (26) और सूर्यकुमार यादव (नाबाद 31) के साथ दो उपयोगी साझेदारियां कर भारत को जीत दिलाई। इस दौरान धवन ने 25वें ओवर में 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।



साझेदारी के दौरान इशान किशन और शिखर धवन) • रायटर

इससे पहले अविष्का फर्नांडो (32) और मिनोद भानुका (27) ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 49 रन जोड़कर टीम को प्रभावी शुरुआत दिलाई। 10वें ओवर में चहल ने पहली ही गेंद पर फर्नांडो को एक्सट्रा कवर पर मनीष पांडे के हाथों कैच करा दिया। भानुका राजपक्षे (24) ने चहल के इसी ओवर में छक्के से खाता खोला, लेकिन 17वें ओवर में कुलदीप की गेंद पर धवन ने मिड आन पर पीछे की ओर दौड़ते हुए उनका कैच शानदार पकड़ा। कुलदीप के इसी ओवर में मिनोद भी स्लिप में पृथ्वी शा को आसान कैच दे बैठे। इस बीच क्रुणाल ने धनंजय डिसिल्वा (14) को चलता किया। भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाकर रन गति को नियंत्रण में रखा। शनाका ने 31वें ओवर में भुवनेश्वर पर चौके के साथ 59 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। चरत असलंका (38) और कप्तान दासुन शनाका (39) ने 35वें ओवर में टीम के 150 रन पूरे किए। असलंका ने हालांकि निराश किया और क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने के बाद चाहर की गेंद पर इशान को कैच दे बैठे।

स्कोर बोर्ड

टास : श्रीलंका (बल्लेबाजी) मैन आफ द मैच : पृथ्वी शा

श्रीलंका 262/9 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
अविष्का फर्नांडो का. पांडे बो. चहल	33	35	02	01
मिनोद भानुका का. शा बो. कुलदीप	27	44	03	00
राजपक्षे का. धवन बो. कुलदीप	24	22	02	02
डिसिल्वा का. कुमार बो. क्रुणाल	14	27	01	00
असलंका का. इशान बो. चाहर	38	65	01	00
शनाका का. हार्दिक बो. चहल	39	50	02	01
वानिंदु हसरंगा का. धवन बो. चाहर	08	07	01	00
चमिका करुणारत्ने नाबाद	43	35	01	02
इसुरु उदाना का. चाहर बो. हार्दिक	08	09	00	00
दुष्मंता चमीरा रन आउट	13	07	01	01

अतिरिक्त : (लेबा-2, नोबा-1, वा-12) 15, कुल : 50 ओवर में नौ विकेट पर 262 रन, विकेट पतन : 1-49 (अविष्का, 9.1), 2-85 (भानुका, 16.1), 3-89 (मिनोद, 16.4), 4-117 (धनंजय, 24.4), 5-166 (चरित, 37.2), 6-186 (हसरंगा, 39.3), 7-205 (दासुन, 43.5), 8-222 (उदाना, 46.5), 9-262 (दुष्मंता, 49.6)

गेंदबाजी : भुवनेश्वर कुमार 9-0-63-0, दीपक चाहर 7-1-37-2, हार्दिक पांड्या 5-0-34-1, युजवेंद्रा सिंह चहल 10-0-52-2, कुलदीप यादव 9-1-48-2, क्रुणाल पांड्या 10-1-26-1

भारत 263/3 (36.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
पृथ्वी शा का. फर्नांडो बो. डिसिल्वा	43	24	09	00
शिखर धवन नाबाद	86	95	06	01
इशान किशन का. भानुका बो. संदाकन	59	42	08	02
मनीष पांडे का. शनाका बो. डिसिल्वा	26	40	01	01
सूर्यकुमार यादव नाबाद	31	20	05	00

अतिरिक्त : 18 (लेबा-5, नोबा-1, वा-12), कुल : 36.4 ओवर में तीन विकेट पर 263 रन, विकेट पतन : 1-58 (शा, 5.3), 2-143 (किशन, 17.5), 3-215 (मनीष, 30.4)

गेंदबाजी : चमीरा 7-0-42-0, उदाना 2-0-27-0, डिसिल्वा 5-0-49-2, संदाकन 8.4-0-53-1, असलंका 3-0-26-0, वानिंदु हसरंगा 9-1-45-0, चमिका करुणारत्ने 2-0-16-0

धवन ने जीत का श्रेय आलराउंड प्रदर्शन को दिया

कोलंबो, प्रेट्र : भारतीय कप्तान शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में सात विकेट की जीत का श्रेय आलराउंड प्रदर्शन को दिया। धवन ने कहा, 'हमारे सभी खिलाड़ी काफी परिपक्व और आक्रामक हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और मैं इससे काफी खुश हूं। तीनों स्पिनरों चहल, कुलदीप और क्रुणाल ने अच्छी गेंदबाजी की और हमें मैच में वापसी दिलाई। दूसरे छोर पर खड़े होकर पृथ्वी और इशान को बल्लेबाजी करते हुए देखकर अच्छा लगा। असल में मैं उन्हें ध्यान से खेलने के लिए कह रहा था। इन खिलाड़ियों को आइपीएल में खेलकर काफी अनुभव मिला है और उन्होंने शुरुआती 15 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था।'

पिता बोले, इशान को मिल रहा धौनी से लिए टिप्स का फल

अरुण सिंह • पटना

अपने जन्मदिन पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में पदार्पण कर शानदार 59 रन की पारी खेलने वाले पटना के इशान किशन के पिता प्रणव पांडेय और उनका परिवार बेहद खुश है।

बेटे को क्रिकेटर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रणव ने जागरण को बताया कि जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में इशान ने शानदार आगाज किया था, उसी तरह वह श्रीलंका में जरूर सफल होगा। इस बार उसे विकेटकीपिंग का भी मौका मिला, जो उसके करियर को विस्तार देने के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना काल में इशान ने विकेटकीपिंग के साथ अपने खेल पर काफी मेहनत की है। श्रीलंका जाने से पूर्व उसने अपने आदर्श महेंद्र सिंह धौनी से भी जरूरी टिप्स लिए। अब उसका फल उसे मिल रहा है।

12 बजे केक काटकर मनाया जन्मदिन : पिता प्रणव पांडेय, मां सुचित्रा सिंह, भाई राज किशन व परिवार के अन्य सदस्यों ने शनिवार को रात 12 बजे पटना के खाजपुरा स्थित अपने घर पर केक काटकर इशान का जन्मदिन मनाया। उन्होंने वीडियो काल कर इशान को शुभकामनाएं भी दीं। इशान को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने क्रिकेट करियर का असमय त्याग करने वाले भाई राजकिशन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इशान से बात हुई थी। वह अभी टी-20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रहा है। उसका पहला लक्ष्य श्रीलंका में बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके बाद यूएई में आइपीएल।



इशान का जन्मदिन मनाते माता-पिता •

2 खिलाड़ियों इशान किशन व सूर्यकुमार ने वनडे पदार्पण किया। इन दोनों ने संयोग से टी-20 पदार्पण भी एक साथ इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल 14 मार्च को अहमदाबाद में किया था

236 खिलाड़ी अब भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं

59 रन बनाए इशान किशन ने। वह वनडे और टी-20 दोनों प्रारूपों में पदार्पण में अर्धशतक बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले रोबिन उथप्पा ने ऐसा किया था

जन्मदिन पर वनडे पदार्पण करने वाले भारतीय

खिलाड़ी	बनाम	जन्मतिथि	पदार्पण तिथि
गुरशरण सिंह	आस्ट्रेलिया	आठ मार्च 1963	आठ मार्च 1990
इशान किशन	श्रीलंका	18 जुलाई 1998	18 जुलाई 2021

इंग्लैंड ने पाक को हरा टी-20 सीरीज बराबर की

क्रिकेट डायरी

लीड्स, प्रेट्र : कप्तान जोस बटलर (59) की अर्धशतकीय पारी के बाद मोईन अली (36) और लियाम लिविंगस्टोन (38) की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने दूसरे टी-20 में रविवार को यहां पाकिस्तान को 45 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर ली। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर इंग्लैंड की पारी 19.5 ओवर में 200 रनों पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 155 रन ही बना सकी। बटलर ने मोईन के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़ने के बाद लिविंगस्टोन के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 39 गेंद की पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। मोईन ज्यादा आक्रामक रहे, जिन्होंने 16 गेंद की ताबड़तोड़ पारी में एक छक्का और छह चौके जड़े।

आइसीसी में शामिल हुए तीन नए सदस्य देश

दुबई, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने रविवार को अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया। आनलाइन तरीके से आयोजित की गई बैठक में मंगोलिया और ताजिकिस्तान का एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्यों के रूप में स्वागत किया गया, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है।

मुरली के नक्शेकदम पर बेटा

नई दिल्ली, जेएनएन : श्रीलंका के दिग्गज आफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक माना जाता है। अपने अनोखे एक्शन से उन्होंने दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया था। अब मुरलीधरन का बेटा नरेन भी उनकी राह पर चल निकला है, जिसका गेंदबाजी एक्शन भी पिता मुरली की तरह है। इंटरनेट मीडिया में मुरलीधरन ने अपने बेटे का एक वीडियो शेयर किया। मुरली ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पिता और पुत्र।'

अमेरिकन एथलीट ने ओलिंपिक बिस्तरों का उड़ाया मजाक

ओलिंपिक डायरी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और दुनियाभर से आने वाले एथलीटों ने टोक्यो के खेल गांव की सैर करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच रियो ओलिंपिक 2016 के विजेता अमेरिका के लंबी दूरी के धावक पाल चेलिमों ने कार्डबोर्ड के बने बिस्तरों को ना सिर्फ मजाक बताया, बल्कि उन्होंने इसकी मजबूती पर भी शक जताया है।

दरअसल, जापान के ओलिंपिक आयोजको की समिति ने कोरोना महामारी और शारीरिक दूरी से बचाव के लिए कार्ड बोर्ड के बिस्तर बनाए हैं। इन बिस्तरों का मजाक बनाते हुए पाल चेलिमो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'टोक्यो ओलिंपिक खेल गांव में लगाए जाने वाले बेड कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, इसका उद्देश्य एथलीटों को इंटीमेसी से बचाना है। खेल से परे परिस्थितियों से बचने के लिए बनाए गए बेड क्या एक व्यक्ति का भार झेलने में सक्षम होंगे। यह उनके लिए खतरनाक हैं जो कभी-कभार बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं, उससे कहीं यह गल ना जाए।'



खेल गांव में कार्डबोर्ड बेड • ट्विटर

तीरंदाजों की धड़कनें टीवी पर

टोक्यो : विश्व तीरंदाजी की पहल के तहत युमेनोशिमा पार्क में टोक्यो ओलिंपिक के दौरान तीरंदाजों के स्तर व दिल की धड़कन को नाकआउट दौर के दौरान टीवी पर देखा जा सकता है। यह तकनीक पहली बार इस्तेमाल होगी।

खेल गांव में तीन खिलाड़ी कोविड-19 संक्रमित

टोक्यो : ओलिंपिक खेल गांव में रह रहे दो खिलाड़ियों सहित कुल तीन खिलाड़ियों को कोविड-19 के लिए पाजिटिव पाया गया है। टोक्यो ओलिंपिक आयोजन समिति ने रविवार को यह जानकारी दी। यह पहला अवसर है जबकि खेल गांव में रह रहे खिलाड़ियों को संक्रमण हुआ है। खिलाड़ियों की पहचान उजागर नहीं की गई है। तीसरा खिलाड़ी खेलों के लिए नामित होटल में ठहरा हुआ है।

खेल गांव पहुंचा भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल



खेल गांव पहुंचने के बाद साथी के साथ पीवी सिंधू (दायें) • ट्विटर

टोक्यो : ओलिंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का पहला जत्था 23 जुलाई से होने वाले खेलों के लिए रविवार की सुबह यहां पहुंचा और हवाई अड्डे पर कोविड-19 से जुड़े कड़े दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद उन्होंने खेल गांव में प्रवेश किया। भारत के पहले जत्थे में 88 सदस्य हैं।

विश्वनाथन आनंद ने स्पार्कसन ट्राफी जीती

डोर्टमंड, प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक के खिलाफ नो कैसलिंग मुकाबले की चौथी और अंतिम बाजी ड्रा खेलकर स्पार्कसन ट्राफी जीत ली। पूर्व विश्व चैंपियन आनंद ने अंतिम बाजी सफेद मोहरों से खेली और दोनों खिलाड़ी 40 चाल के बाद बाजी ड्रा कराने को राजी हो गए जिससे भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2.5-1.5 से मुकाबला जीता। आनंद ने पहले दौर की बाजी में जीत दर्ज की थी जबकि बाकी तीन बाजियां बराबरी पर छूटीं। क्रैमनिक ने शनिवार को आनंद को तीसरी बाजी में बराबरी पर रोककर चार बाजियों के मुकाबले में बराबरी हासिल करने की उम्मीद जीवंत रखी थी।

हर साल बेहतर होता जा रहा है सिस्टम

साइना नेहवाल स्मैश



बहुत से लोगों में यह विश्वास काफी ज्यादा है कि हम टोक्यो 2020 में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, खासतौर से जब हमारे खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में वैश्विक स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सिर्फ क्रिकेट अकेला ही लाइमलाइट में नहीं रहता है। मुझे लगता है कि पिछले एक दशक में भारत में काफी शानदार बदलाव हुए हैं। अच्छे परिणाम के लिए यह सबसे अहम है।

मैं यह स्वीकार करती हूं कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं काफी व्यस्त रही हूं। इस वजह से सिस्टम को किसी अन्य नजरिये से देखने का समय नहीं मिला। मगर पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सकारात्मक बदलाव देखे हैं। खेलने के लिए की जाने वाली यात्राओं के लिए हमें हमेशा सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिली है। 2014-15 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टाप्स) की शुरुआत एक शानदार कदम रहा। एक समय था जब हमें किसी सामान की जरूरत होती थी तो हमें एनजीओ की मदद लेनी पड़ती थी। अब ज्यादा से ज्यादा एथलीटों को टाप्स मदद मिलना आसान हो गया है। खिलाड़ियों को हर महीने मिलने वाला आउट आफ पाकेट अलाउंस भी एक अच्छा कदम है। इससे उन्हें ट्रेनिंग, सप्लीमेंट और कम्पीटिशन के लिए मदद मिल रही है।

एक और अच्छी बात हुई है कि खिलाड़ियों के संपर्क में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें अपने गेम पर फोकस, कड़ी मेहनत और खुद को अच्छे से तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं कह सकती हूं कि सिस्टम हर साल बेहतर होता जा रहा है। इसलिए खिलाड़ियों को अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।



हम भाग्यशाली हैं कि भारत के पास पिछले 10-15 साल में अच्छे खिलाड़ियों का समूह रहा है, लेकिन मैं यह जरूर स्वीकार करना चाहूंगी कि जब लोग मुझे प्रणेता के रूप में देखते हैं, तो बेहद खास अनुभव होता है। भारतीय बैडमिंटन का स्टैंडर्ड भी पिछले कुछ साल में काफी ऊपर गया है और हमारे कई खिलाड़ी दुनिया भर के शीर्ष-50 खिलाड़ियों में शामिल हैं।

मैं बीजिंग में पदक जीत सकती थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि इंडोनेशिया की मारिया यूलिआंती के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 11-3 की बढ़त बनाने के बाद मैंने मैच गंवा दिया। 2008 में उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं थीं। अपने दूसरे ओलिंपिक खेल लंदन 2012 में जब मैंने कांस्य पदक जीता, तो मुझे पोडियम पर खड़े होने और वहां से तिरंगे को लहराते देखने का महत्व समझ में आया।

सब मिला, अब ओलिंपिक स्वर्ण की बारी : मेरी कोम

छह बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलिंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की स्टार मुक्केबाज एमसी मेरी कोम इस बार हर हाल में स्वर्ण पदक जीतना चाहती है। मेरी कोम का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया, लेकिन बस एक सपना ओलिंपिक का स्वर्ण पदक ही रह गया है। टोक्यो ओलिंपिक को लेकर **मेरी कोम** से **शुभम पांडेय** ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

साक्षात्कार



• टोक्यो ओलिंपिक के लिए कितनी तैयार हैं?

-एशियन चैंपियनशिप से भारत वापस आने के बाद मेरी तैयारी वास्तव में अच्छी चल रही थी। दूसरी लहर के कारण प्रशिक्षण में व्यवधान के बावजूद मेरे प्रशिक्षकों की निगरानी में नियमित प्रशिक्षण सत्र जारी रहा था, जिसके बाद अभ्यास का आखिरी चरण इटली में शुरू हुआ। मैं हमेशा की तरह अपना सबकुछ दे रही हूं।

• आप पुणे में अभ्यास कर रही थीं, अचानक फिर इटली ही जाना क्यों चुना?

-पुणे में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भारत से टोक्यो की यात्रा करने वालों पर सख्त यात्रा प्रतिबंध थे और मैं इससे बचना चाहता थी। इसलिए मैंने बाकी अपनी टीम के साथियों के साथ इटली जाना उचित समझा।

• 2012 लंदन ओलंपिक के बाद से अभी तक के अपने खेल में किस तरह का बदलाव देखती है ?

-मेरा मानना है कि इतने सालों में बहुत कुछ नहीं बदला है। कुछ भी हो, मुक्केबाजी के लिए मेरा प्यार और भूख अभी भी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ रही है। साथ ही मैं उम्र और समय के साथ अधिक अनुभवी और परिपक्व मुक्केबाज बन गई हूं।

• आप 2016 रियो ओलिंपिक में जगह नहीं बना पाई थीं, उससे क्या सीख मिली थी?

-मैं वास्तव में रियो ओलिंपिक के लिए जगह नहीं बना पाने से बहुत निराश थी, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, मैं बहुत जिद्दी हूं और इसी कारण निराशा ने मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मेरी जिद के कारण ही मेरा लक्ष्य था कि मैं कोई कसर न छोड़ूं और मजबूत होकर बेहतर वापसी कर सकूं। अब पांच वर्षों के बाद एक और ओलंपिक खेलों में पंच लगाने के लिए तैयार हूं।

• क्या इस बार पदक का रंग बदलने वाला है?

-मैंने सब कुछ जीता है जो जीतने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस बार मेरा सपना है कि ओलिंपिक स्वर्ण पदक पर कब्जा करूं और इसके लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हूं।

• किन देशों के मुक्केबाजों से कड़ी चुनौती मिलने वाली है?

-ओलिंपिक जैसे बड़े आयोजन में आसान मुकाबले नहीं होते। सभी प्रकार के विरोधियों के लिए समान रूप से तैयार रहना होगा क्योंकि कोई भी किसी भी दिन जीत सकता है।



2000

मल्लेश्वरी ने दिखाया दम

अटलांटा में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कांसा जीता तो सिडनी ओलिंपिक में भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। वह ओलिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।

मल्लेश्वरी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पैदा हुई मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही भारोत्तोलन का अभ्यास शुरू कर दिया था। भारतीय खेल प्राधिकरण की एक योजना के तहत मल्लेश्वरी को प्रशिक्षण मिला। उनको अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान मिल चुका है।



15 सितंबर से 01 अक्टूबर

10651 एथलीट | 199 देश | 28 खेल 300 मुकाबले

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	37	93
रूस	32	89
चीन	28	58
आस्ट्रेलिया	16	58
जर्मनी	13	56

पहली बार

- ट्रायथलन और ताइक्वांडो खेलों को ओलिंपिक में शामिल किया गया। भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलन में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने भी भाग लिया।
- उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने एक झंडे के तले स्टेडियम में प्रवेश किया।
- शक्तिवर्द्धक दवा इरिथ्रोपोएटिन के इस्तेमाल की जांच के लिए पहली बार परीक्षण किए गए



ईस्ट तिमोर के चार एथलीटों ने किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के बजाय ओलंपिक झंडे के तले एकल एथलीट के तौर पर आयोजन में हिस्सा लिया



2004

राज्यवर्धन की बंदूक से निकली चांदी

प्राचीन और आधुनिक युग के ओलिंपिक युग के खेलों के महाकुंभ के जनक ग्रीस में ओलिंपिक खेलों की वापसी हुई। एथेंस को मेजबानी करने का मौका मिला। भारतीय निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक पर निशाना साधा।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	36	101
चीन	32	63
रूस	28	90
आस्ट्रेलिया	17	50
जापान	16	37

13 अगस्त से 29 अगस्त

10625 एथलीट | 201 देश | 28 खेल 301 मुकाबले

छा गए राठौर

राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 1998 से ही निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया था। जल्द ही मुकाबलों में उनका दमखम दिखने लगा। सिडनी विश्व कप में भी राठौर ने स्वर्ण जीता था। 2004 में ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पहली बार

- महिला कुश्ती को पहली बार ओलिंपिक में शामिल किया गया
- रूस और चिली ने टेनिस में पहली बार पदक जीते

रिकार्ड देश

सबसे ज्यादा 201 देशों ने आयोजन में हिस्सा लिया और ओलिंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले हुए

रिकार्ड दर्शक

अब तक हुए सभी ओलिंपिक की तुलना में इसके दर्शक सबसे ज्यादा रहे। टीवी पर करीब 3.9 अरब लोगों ने इनका आनंद लिया

ऐतिहासिक पल : एथेंस के उसी पेनाथेनिक स्टेडियम में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1896 के ओलिंपिक हुए थे।

अर्जेंटीना चैंपियन : अर्जेंटीना की फुटबाल टीम ने कोई भी गोल खाए बिना पुरुषों का फुटबाल खिताब जीता।



2008

भारत को मिला गोल्डन ब्वाय

112 वर्ष के ओलिंपिक इतिहास में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के रूप में भारत को पहला गोल्डन ब्वाय मिला। कुश्ती में 56 साल बाद एक बार फिर सुशील ने कांस्य पदक जीता तो मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह ने कांसा जीतकर भारतीय मुक्केबाजी को नई पहचान दिला दी।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
चीन	51	100
अमेरिका	36	110
रूस	23	73
ब्रिटेन	19	47
जर्मनी	16	41

08 अगस्त से 24 अगस्त

10942 एथलीट | 204 देश | 28 खेल 302 मुकाबले

बिंद्रा निकले 'अभिनव'

बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। बिंद्रा क्वालीफाइंग दौर में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 596 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।



विजेंद्र ने कांसे पर लगया पंच



इस ओलिंपिक में मुक्केबाज विजेंद्र सिंह देश को पदक दिलाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने 75 किग्रा वर्ग में इक्वाडोर के मुक्केबाज कार्लोस गोंगोरा को 9-4 से हराकर पदक अपने नाम किया। वह मुक्केबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।

सुशील कुमार

66 किग्रा वर्ग में पहलवान सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश में कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को नई पहचान दी।

फेल्प्स बने रिकार्ड पुरुष

अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने किसी एक ओलिंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण जीतने का नया रिकार्ड बनाया। उन्होंने आठ स्वर्ण पदक जीते।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
साहित्यिक पुनर्नवा
सोमवार, 19 जुलाई, 2021



सबको थोड़ा नीर चाहिए

नवगीत



चित्रांश वाघमारे
भोपाल, मध्य प्रदेश



सबको थोड़ा नीर चाहिए
वन को भी और मन को भी।।

हरियाली संभव है तो फिर
क्यों मन को मरुथल रहने दें?
कुछ आंखों में, कुछ अंबर में
कुछ धरती पर जल रहने दें

क्योंकि प्यास के अटल नियम हैं
और असंभव फेरबदल
क्षीण बना सकती है क्षण में
सबसे अधिक सघन को भी।।

धरती पर हम बूंद बचाकर
अम्बर में बादल रोपेंगे
हम घाटों के बीच पहुंचकर
नदिया की कलकल रोपेंगे

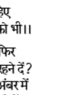
माना हमने राम नहीं हम
लेकिन धरा अहिल्या है
हम इस बार नहीं भूलेंगे
अपने दिए वचन को भी।।

देखें हम उस दिन का सपना
जब रेतीले भाव न होंगे
प्यास बुझाने के पथ में भी
इतने अधिक पड़ाव न होंगे।।

किंतु प्यास की गहराई जब
नदियों से गहरी होगी तब
समय नहीं होगा पल भर का
अपने पास मनन को भी।।

chitranshw1994@gmail.com

नवगीत



योगेन्द्र वर्मा 'व्योम'
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

एक हरापन रोपें भीतर



चलो निराशा के ऊसर में
एक हरापन रोपें भीतर

क्षणिक लाभ के लिए त्यागकर
मानवता, संवेदन सब कुछ
छल-फरेब ने गढ़े स्वार्थ के
कीर्तिमान, सम्मोहन सब कुछ
लुगदी सी हो चुकी सोच में
एक भलापन रोपें भीतर

कितना दूर किया आपस में
सबको दो गज की दूरी ने
लिखी मार्मिक व्यथा-कथा भी
दो रोटी की मजबूरी ने
अवसादों का व्यूह तोड़कर
एक नयापन रोपें भीतर

तन से तन की भले न हो, पर
रहे निकटता मन से मन की
तब महकेगी खिलकर-खुलकर
मीठी सी खुशबू जीवन की
हो न दिखावे भर का ही जो
एक सगापन रोपें भीतर

vyom70@gmail.com

कहानी



दीप्ति मित्तल
पुणे, महाराष्ट्र

एक मासूम ख्वाहिश

अपने पिता से मिली कठोर अनुशासनप्रियता के कारण अपनी बेटी के प्रति सख्त रुख अपनाने वाली युवती और अपनी बेटी को उसके पति से मिलने वाले स्नेह से परिवर्तित हुए युवती के मन की मार्मिक दास्तान...



रेखांकन-ब्रिज

पार्किंग में पहुंचकर जैसे ही स्नेहा ने अपनी छह साल की बेटी कुहू के लिए कार का बैक डोर खोला, वह मुंह चढ़ाकर फ्रंट डोर के सामने जा खड़ी हुई।

'कुहू बच्चे पीछे बैठते हैं, वहां मम्मा बैठेगी।' स्नेहा समझाते हुए बोली, मगर कुहू कहां सुनने वाली थी। उसका गोलू सा मुंह फूलकर और कुप्पा हो गया। कुहू का रुआंसा चेहरा देख मयंक ने भीतर से अपनी बगल वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। 'पप्पा के साथ बैठना है प्रिंसेस को...आ जा' और वो छलांग लगाकर बैठ गई। बैठते ही उसने कार के म्यूजिक सिस्टम पर अपनी मनपसंद नर्सरी राइम्स लगा दी। रोज की तरह आज भी स्नेहा को पीछे बैठकर संतोष करना पड़ा।

हफ्ते भर से ये इस छोटे से परिवार का रोज का रूटीन हो गया था। डिनर के बाद कुहू का आइसक्रीम के लिए जिद करना, स्नेहा का सर्दी का हवाला देकर मना करना और मयंक का दोनों के बीच में आकर यह कहते हुए कुहू की जिद मान लेना, 'आइसक्रीम तो पप्पा को भी खानी है...।'

बैक सीट पर बैठी स्नेहा दोनों को हंसते-गुनगुनाते देख रही थी, मगर वो चाहकर भी उनका हिस्सा नहीं बन पा रही थी। आजकल अजीब सी जलन महसूस करने लगी थी वो, कुहू अर्थात अपनी बेटी के लिए! यह एक ऐसा खयाल था, जो उसे भीतर ही भीतर शर्मिंदा भी कर रहा था, मगर वह करे भी तो क्या! कैसे नकारे मीठे मातृत्व की ओट से लुकाछिपी खेल रही इस कसैली भावना को?

स्नेहा आजकल कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रही थी कि मयंक जब-तब कुहू की हर सही-गलत जिद के आगे सहजता से झुकने लगा था और जब-जब ऐसा होता, स्नेहा अतीत के उन गलियारों में भटकने चली जाती जहां छोटी स्नेहा कोई गलती या जिद करने के बाद अपने पिताजी के सामने अपराधिनी बनी खड़ी होती और वह उसे आंखें चौड़ी कर तेज आवाज में डांट रहे होते।

उसे याद ही नहीं है कि कभी उसने अपने पिताजी का चेहरा नार्मल और हंसते हुए देखा हो। हमेशा 'ये करो, ये नहीं करो' की पट्टी पढ़ाते, अनुशासन का ढोल बजाते, जरा-जरा सी गलती पर डांटते और मम्मी को सुनाते, 'लड़की को जरा तमीज सिखाओ, इसे दूसरे के घर जाना है।' पिता के सामने स्नेहा न कभी अपने मन की कह पाई, न ही कर पाई। शुष्क हवाओं के बीच जैसे-तैसे ये बेल परवान चढ़ी और एक दिन ससुराल की क्यारी में रोप दी गई। सख्त परवरिश के असर से हर काम तमीज से करना, समय पर करना और अपनी हद में रहना स्नेहा के खून में आ गया था। मंयक अच्छा पति था। वह हर वो काम करता था, जो अच्छे पति किया करते हैं, मसलन घर की जरूरतों का खयाल रखना, कभी-कभी स्नेहा को सिनेमा, डिनर पर ले जाना, बर्थ डे-एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना... आदि।

दोनों में कभी किसी बात पर मतभेद नहीं हुए, क्योंकि घर वैसे ही चल रहा था जैसे मयंक चाहता था। कार में वे ही गाने चलते थे, जो मयंक ट्यून करता था। उसके हर निर्णय में स्नेहा की मौन स्वीकृति रहती।

सब कुछ सही चल रहा था, मगर उसकी बेटी ने, उसके भीतर दम तोड़ चुकी उस छोटी स्नेहा को फिर से जिंदा कर दिया था। उसे कुहू का बात-बात पर जिद करना अच्छा नहीं लगता था और उससे भी ज्यादा बुरा लगता था उसके पापा का हर बार उसके सामने खुशी-खुशी झुक जाना। स्नेहा को यकीन नहीं होता था कि पिता ऐसे भी हो सकते हैं! वह यह देखकर हैरान रह जाती थी कि यह वही मयंक है जिसे हर काम अपने मन मुताबिक करने की आदत है, जो किसी के लिए अपना रूटीन नहीं बदल सकता, मगर कुहू के सामने कैसा मोम सा पिघला रहता, वह जैसा चाहती, प्यार से ढल जाता।

आज रविवार था। लंच के वक्त स्नेहा ने अपनी और मयंक की थाली लगा ली। कुहू को एक कटोरे में दाल-चावल मिलाकर दे दिया गया, मगर कुहू अपने हाथ से न खाने की जिद करने लगी। स्नेहा ने उसे जोर देकर खुद खाने के लिए कहा तो उसने ठुनकना शुरू कर दिया। 'नई... आप ही खिलाओ...' स्नेहा नहीं मानी।

'आओ, पप्पा खिला देंगें।' मयंक ने झट से उसका खाना लिया और खिलाने लगा। बस आज स्नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह फट पड़ी, 'इसकी हर सही-गलत बात मानकर तुम इसे क्यों बिगाड़ रहे हो मंयक! इसकी उम्र में मैं खाना खाकर मेज भी पोछ दिया करती थी।'

'अरे थोड़ा खिला दिया तो क्या हुआ, हमेशा हमारे हाथ से थोड़े ही खाएगी?' मयंक खिलाने लगा तो स्नेहा ने रोक दिया।

'नहीं, तुम आज खुद से ही खाओगी!' कहते हुए उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी हो चलीं जितनी उसके पिता की हुआ करती थीं, स्वर वैसा ही कर्कश हो गया जैसे उसके पिता का हो जाया करता था। फर्क बस इतना था, वह चुपचाप खड़ी रह जाती थी, मगर कुहू दहाड़ें मारकर रोने लगी।

इस पर मयंक चिल्ला पड़ा, 'ये क्या जिद लगा रखी है तुमने! वो तो बच्ची है जिद करेगी ही, मगर तुम तो बड़ी हो, तुम्हारा यूं जिद करना अच्छा लगता है क्या? देख रहा हूं आजकल कुछ ज्यादा ही सख्त होती जा रही हो' कहकर उसने कुहू को गोद में बैठा लिया और पुचकारते हुए खाना खिलाने लगा।

स्नेहा सन्न खड़ी रह गई। आज मैं बड़ी हूं। इसलिए जिद नहीं कर सकती और जब मैं छोटी थी तब! तब भी अपने मन की कहां कुछ कर पाई थी। उसे लगा जैसे पलकों पर बंधा बांध आज टूटने की कगार पर है तो वह कमरे में चली आई।

स्नेहा आज खुद से डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। लग रहा था जैसे कंधे पर पिताजी की छाया आ बैठी हो, जो उसे अपने जैसा बनाती जा रही हो। नहीं! ये सही नहीं है। मैं कुहू को दूसरी स्नेहा नहीं बनने दे सकती! उस दिन के बाद से स्नेहा कुहू से संभलकर व्यवहार करने लगी। एक खामोश रात तारों की चादर ओढ़ सुस्ताने चली थी। मयंक पास सोई कुहू के बालों को सहला रहा था। स्नेहा सोने से पहले हाथों पर नाइट क्रीम मलते हुए बिस्तर के सिराहने आकर बैठ गई। मयंक ने उसे अपनी ओर खींच लिया और प्यार से बोला, 'दो दिन बाद तुम्हारा बर्थ डे है, बताओ क्या गिफ्ट लोगी इस बार?'

'क्या लूं? सब कुछ तो है मेरे पास', स्नेहा ने उसके कंधे पर हौले से सिर टिका दिया।

'छोड़ो भी, अब इतना भी रानी बनाकर नहीं रखा हुआ। कुछ तो होगा जिसे पाने को मन ललचाता होगा?' सुनकर स्नेहा कहीं भीतर डूब गई जहां कुछ अधूरी ख्वाहिशें अर्द्धमृत पड़ी ऊंघ रहीं थीं। कैसे कहूं क्या चाहिए! मन क्या पाने को ललचाता है आजकल! थोड़ा सा लाड़, थोड़ा दुलार, बेवजह की मनुहार।

'कहां खो गई, गिफ्ट के लिए इतना सोचना पड़ रहा है? अरे बोलकर तो देखो! तुम्हारे लिए तारे तोड़कर न ले आऊं तो कहना...' मयंक प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी अंगुलियां सहलाने लगा।

'सुनो! बस एक वादा दे दो इस बार', स्नेहा धीमे से फुसफुसाई।

'क्या?'

'अगर कभी कुछ ऐसी जिद करूं जिसमें तुम्हारी सहमति न हो, जो तुम्हें ठीक न लगे तो भी ऐसे झुक जाना जैसे अपनी प्रिंसेस के सामने झुक जाते हो। बस यही चाहिए...' स्नेहा की सजल आंखों में एक मासूम ख्वाहिश उभर आई। उन आंखों से एक दमित बचपन झांक रहा था जिसे देख मयंक सिहर गया। उसने स्नेहा के दोनों हाथों को कसकर थाम लिया।

'पहले तुम भी एक वादा करो, मुझसे उसी हक से जिद करोगी जिस हक से प्रिंसेस करती है...' सुनकर स्नेहा की आंखों से दो मोती ढुलक पड़े, जो उसके नहीं, उस छोटी स्नेहा के थे जिसे आज मुद्दतों बाद अपनों से जिद करने का हक मिला था।

deeptimittal403@gmail.com

स्मरण



जयश्री पुरवार
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के समर्थक

'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक न केवल 'स्वराज' और 'स्वदेशी' वरन स्वभाषा के भी प्रबल समर्थक थे...

स्वतंत्रता पूर्व भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान देने की पुरजोर वकालत करने वालों में हिंदेतर भाषी प्रांतों के व्यक्तित्वों में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने गृह शासन आंदोलन के लक्ष्यों में राष्ट्रीय शिक्षा को भी जोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही हो। उनका कहना था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जा सकता है। भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। एक समान भाषा के द्वारा हम परस्पर विचार प्रकट करते हैं।

उन्होंने जनसामान्य तक अपने विचार पहुंचाने के लिए मराठी भाषा में 'केसरी' नाम से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। जिसे पंडित माधवराव सप्रे ने तिलक की अनुमति और सहयोग से अप्रैल, 1907 से 'हिंद केसरी' नाम से हिंदी भाषा में छापना आरंभ किया। हिंदी भाषा का यह पत्र उन दिनों पर्याप्त लोकप्रिय हुआ था। स्वयं मराठी भाषी होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी में भाषण देने के लिए हिंदी सीखी, जीवन भर हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगे रहे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के लिए बार-बार आग्रह करते रहे। अपने विचार और उसूलों पर बराबर अडिग रहने वाले तिलक साहसी और निर्भीक पत्रकारिता के मानदंड थे।



जन्मतिथि 23 जुलाई

तिलक ने अपने पत्र केसरी में 'देश का दुर्भाग्य' शीर्षक से लेख लिखा था जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना थी। तब उनको राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर छह वर्ष के कठोर कारावास में माण्डले, बर्मा (अब, म्यांमार) जेल भेज दिया गया। कारावास के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर ऐसा कुछ पढ़ने और लिखने पर रोक लगा रखी थी जिसमें कोई राजनैतिक तथ्य हो। अतः जेल में रहते हुए उन्होंने गीता की व्याख्या पर पुस्तक 'गीता रहस्य' लिखा जिसका हिंदी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ।

बाल गंगाधर तिलक, एक शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के कर्मठ नेता थे। तिलक ने अपने त्याग, सेवा और निष्ठा के माध्यम से देशवासियों का हृदय जीता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह भारतीय जनमानस में इतने समादृत और स्वीकृत हुए कि उन्हें देश ने 'लोकमान्य' की उपाधि से विभूषित किया।

jayshreepurwar@gmail.com

लघुकथा

भावों की भाषा

मेरे आस-पड़ोस में कोरोना महामारी विकराल रूप धर चुकी थी। कुछ एक घर छोड़कर हर घर में संक्रमित मरीज, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे।

मेरे घर से लगे हुए घर में शर्मा जी का परिवार रहता है। उनका पांच वर्ष का बेटा मेरे पास रोज आकर खेलता, पढ़ता और खूब बातें करता। उसके बालसुलभ आकर्षण ने मुझे स्नेह की डोर में बांध लिया था। दुर्भाग्यवश उनका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे को लेकर मेरी चिंताएं बढ़ गईं।

मैं दूरी बनाते हुए नाश्ता, खाना आदि उनके दरवाजे पर रख आती और पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करने लगी। वह बच्चा मेरे दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन अपने परिवार को संक्रमण से बचाए रखने के लिए मैं दरवाजा न खोलती। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह मायूस होकर वापस चला जाता। इस प्रकार मैं अपने और उनके परिवार की सहायता कर रही थी, लेकिन बालमन तो भावों की भाषा समझता है।

ईश्वर की कृपा से उनके परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार होता गया और लगभग एक माह में वे सभी पूर्ण स्वस्थ हो गए।

आज वह बच्चा अपने घर के छज्जे पर मौन खड़ा था। मैंने उसे अपने घर आने के लिए प्यार से बुलाया, लेकिन अब उसकी आंखों में न वो चमक थी और न ही मेरे घर आने की ललक। इस कोरोना ने भावों की भाषा बोलने वाले बच्चे के मन से भाव चुरा लिए थे।

मेरी आंखों से दो बूंद आंसू लाख रोकने के बाद भी न रुके।

कविता तिवारी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
betumili20@gmail.com

व्यंग्य



राजेंद्र त्यागी
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

मूंग की दाल

आम रसोईघरों में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री महंगी होती जा रही है। महंगाई से उपजी तंगहाली पर एक तीखा व्यंग्य...



बास की झाड़ और राह की धूल, दोनों झाड़ने के बाद मुन्नालाल खाना खाने बैठ गया। रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी की कटोरी में भिगोया। टुकड़ा कटोरी में ऐसे डूब गया जैसे नदी में बिना पतवार की नाव।

मुन्नालाल का जायका बे-जायका हो गया। उसने चिल्लाकर पत्नी से पूछा, 'भाग्यवान! आज यह क्या बना लाई?'

पत्नी ने रसोई ही से जवाब दिया, 'दाल!'

पत्नी का जवाब सुन मुन्नालाल आसन से खड़ा हुआ और बदन के कपड़े उतारने लगा। तभी दूसरी रोटी लेकर पत्नी रसोई से बाहर आई और पति की हरकत देख अवाक रह गई। आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसने पूछा, 'क्यों जी! खाना खाते-खाते यह क्या, जी?'

मुन्नालाल ने जवाब दिया, 'कुछ नहीं! बस कपड़े उतारकर कटोरी में डुबकी लगाने की सोच रहा हूं। तुम्हारी बनाई दाल में दाल के दाने खोजने के लिए।'

पत्नी पहले तो खिल-खिलाकर हंस दी और फिर खिन्न भाव से बोली, 'दस हजार रुपल्ली की तनख्वाह में दाल मक्खनी के ख्वाब देखते हो, जी!'

निरीह भाव से मुन्नालाल बोला, 'मक्खनी दाल मैंने कब मांगी? मूंग-मसूर जिसकी भी दाल बनानी थी, दाल के दो-चार दाने तो गरम पानी में डालने की मेहरबानी कर देती।'

महंगाई की तरह पत्नी ने नाक-भौं चढ़ाई और फिर कटाक्ष किया, 'यह मुंह और मसूर की दाल। महंगाई के आईने में थोबड़ा देखे कितने दिन हो गए हैं? कभी-कभी घर के पिछवाड़े जाकर दुकानदार का आईना भी झांक आया करो। पता है, मूंग की दाल भी मंगल ग्रह की सैर पर निकली है। दाल के दो-चार दाने ही डिब्बे में बचे हैं, उन्हें हारी-बिमारी में खिचड़ी बनाने के लिए बचाकर रखा है।'

महंगाई पुराण की कथा सुन मुन्नालाल का चेहरा झरबेरी के बेर की तरह सिकुड़कर रह गया, बदन के कपड़ों पर से पकड़ ढीली पड़ गई। वह अनमने मन से पनियल दाल में भिगो रोटी का टुकड़ा सटकने बैठ गया।

उसने फटाफट भोजन किया और चारपाई पकड़ी। आंख लगी ही थी कि सपने में एक सुंदरी ने प्रवेश किया। मंद-मंद मुस्कुराते हुए मुन्नालाल ने अपने मुख पर हाथ फेरा और सुंदरी की तुलना मसूर की दाल के सौंदर्य से करते हुए पूछा, 'भद्रे! आप कौन हैं? कौन-सी दाल का प्रतिनिधित्व करती हैं?'

सुंदरी मुस्कुरा कर बोली, 'प्रिय मुन्नालाल, ठीक पहचाना! मैं दाल ही हूं, मगर मूंग की।'

मुन्नालाल बीच ही में बोला, 'किंतु, भद्रे! तुम्हें तो पत्नी ने हारी-बीमारी में खिचड़ी के लिए डिब्बे में बंदकर रखा है!

'चिंता मत करो, प्रिय! मैं यहां भोग के लिए उपस्थित नहीं हुई हूं। जब तुम बीमार पड़ोगे तो अवश्य ही खिचड़ी में दर्शन दूंगी! अभी तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारी शंका निवारण करने के लिए उपस्थित हुई हूं, प्रिय!'

'कहो, शीघ्र कहो, जो भी कहना है! देश के कर्णधारों को पता चल गया कि तुम मुन्नालाल के सपनों में जाती हो तो उस पर भी पाबंदी लगा देंगे।'

'चिंता न करो, प्रिय! दिवास्वप्न पर पाबंदी लग सकती है। रात्रि-स्वप्न देखने से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर पाएगा। सरकार ने तुम्हें गरीबी रेखा से ऊपर खींचने का भरसक प्रयास किया, किंतु तुम फेवीकोल के जोड़ की तरह वहीं चिपके रहे। जब अहसास हुआ कि लक्ष्मण रेखा पार न करने के लिए तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो तो सरकार ने लक्ष्मण रेखा का दायरा सीमित करने का प्रयास किया, किंतु खेद कि तुम फिर भी सीमा रेखा से बाहर नहीं आए।'

सुंदरी ने आगे कहा, 'बताओ, प्रिय तुम्हीं बताओ! मैं या प्याज, आलू या टमाटर, कब तक तुम्हारे साथ चिपके रहते। अपना-अपना मुकद्दर! तुम गरीबी की लक्ष्मण रेखा लांघ न सके, इंतजार के बाद हम रेखा लांघ ऊपर वालों की जमात में शामिल हो गए। आखिर हमारे भी तो अपने अरमान हैं, सपने हैं।'

इतना कहकर मूंग की दाल मुन्नालाल के सपने से भी गायब हो गई। उसने करवट बदली और गहरी नींद लेने का महंगा प्रयास किया। तभी दूसरा सपना उसे घेर बैठा, घास की रोटी का एक टुकड़ा उसके हाथ में था, जिसे वह डिब्बे में छिपाने जा रहा था, तभी एक ऊदबिलाव उसकी ओर झपटा और उसके हाथ से टुकड़ा छीनकर भाग गया!

भयभीत मुन्नालाल के मुंह से चीख निकली। चीख सुनकर उसकी पत्नी भी जाग गई। सपने की बात उसने पत्नी को बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना दी, 'डरो मत, सो जाओ। ऊदबिलाव नहीं था, महंगाई थी।'

rtyagi49@gmail.com





राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 19 जुलाई, 2021
आजकल
14
www.jagran.com

इंदिरा गांधी ने किया देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण

वर्ष 1969 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इनमें से ज्यादातर बैंकों पर बड़े औद्योगिक घरानों का नियंत्रण था। उस समय बैंकों की जमा पूंजी का 85 फीसद इन्हीं बैंकों में था।



ब्रिटिश इतिहास की सबसे कम समय की महारानी को हटाया गया



1553 में आज ही इंग्लैंड की महारानी लेडी जेन ग्रे को सिर्फ नौ दिन बाद ही पद से हटा दिया गया। 15 साल की जेन ग्रे को नौ दिन की रानी भी कहा जाता है। वह हेनरी ग्रीक की सबसे छोटी बेटी और इंग्लैंड के किंग हेनरी सात की परपोती थीं।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे



अंग्रेजी हुकूमत के सामने क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे का जन्म आज ही वर्ष 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इंफैंट्री में पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस को लेकर विरोध जताया था। 29 मार्च, 1857 को अंग्रेजी अफसर ह्यूसन को मार दिया। इन्हें छह अप्रैल को मौत की सजा सुनाई गई और आठ को फांसी दे दी गई।

इधर-उधर की

मनपसंद डिश खाइए भी और कमाइए भी

वाशिंगटन, एजेंसी : मनपसंद डिश सभी खाना चाहते हैं और लोग इसके लिए पैसे खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते। क्या हो अगर किसी को कोई डिश खाने के लिए पैसे देने न पड़ें, बल्कि बहुत सारे पैसे मिलें। अमेरिका की मैक्रोमिक कंपनी का नौकरी का विज्ञापन कुछ ऐसा ही है। यहां पारंपरिक मैक्सिकन डिश 'टैको' खाने वाले को नौकरी पर रखा जाएगा। इस पद पर काम करने वाले को चार महीने में करीब 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। कंपनी ने अपने विज्ञापन में कहा, इस पद पर काम करने वाले को देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर 'टैको' के ट्रेंड्स के बारे में पता करना होगा। इसके साथ ही इसकी नई-नई रेसिपी के बारे में भी शेफ से चर्चा करनी होगी।



चार महीने में मिलेंगे करीब 75 लाख रुपये। इंटरनेट मीडिया

प्रदूषण से प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई

आया सामने ▶ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर लगाया पता

वाशिंगटन, एएनआइ : धरती पर बढ़ता प्रदूषण कई समस्याओं का कारण बन रहा है। अब इस क्रम में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर पता लगाया है कि जो बच्चे अधिक वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं उनके शैक्षणिक कौशल, वर्तनी, पढ़ने की समझ व गणित पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में किए गए इस अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई में प्रदूषण के कारण आने वाली परेशानी का पता लगाना और उससे निजात पाने के लिए सुझाव देना था। यह अध्ययन कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेलमैन स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ के कोलंबिया सेंटर फार चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल हेल्थ (सीसीसीईएच) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इरविंग मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इस अध्ययन को एनवायरमेंटल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इरविंग मेडिकल सेंटर में मनोचिकित्सा विभाग में चिकित्सा मनोविज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर व इस अध्ययन की प्रमुख लेखक एमी मार्गोलिस के मुताबिक, हमारे अध्ययन में सामने आया कि खराब आबोहवा में रहने वाले बच्चे सामान्य चीजों पर भी सही से प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। जैसे जब चिह्न को ऊपर की ओर दिखाया गया या हरी लाइट दिखाई गई तो वे उन्हें सही अर्थों में समझ नहीं पाए। हमारा अध्ययन बताता है कि बचपन में अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में बिताए गए समय का असर आगे चलकर शिक्षा पर देखने को मिलता है। इससे बच्चों में वे कौशल अच्छे से विकसित नहीं हो पाते जो बेहतर आबोहवा वाले क्षेत्र में बचपन बिताने वाले बच्चों में होते हैं।

मार्गोलिस के मुताबिक, जब माता-पिता व शिक्षक बच्चों को पढ़ाई में आने वाली बाधाओं पर विचार करते हैं तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। खराब वातावरण यानी अधिक वायु प्रदूषण वाला क्षेत्र उनके कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करता है।

सीसीसीईएच की निदेशक और कोलंबिया मेलमैन स्कूल में एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर व इस अध्ययन की सह लेखक जूली हर्बस्टमैन के मुताबिक, हमारा यह अध्ययन वायु प्रदूषण के बच्चों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को दर्शाता है। हमारे अध्ययन में वायु प्रदूषण और शिक्षा के बीच संबंध साफ दिखाई देता है। वहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बच्चों की परवरिश अच्छे वातावरण में की जाए तो वे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।



वायु प्रदूषण का शैक्षणिक कौशल, गणित आदि के ज्ञान पर पड़ता है असर। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इस तरह से किया अध्ययन

सीसीसीईएच के शोधकर्ताओं ने उत्तरी मैनहट्टन और द ब्रोंक्स में 200 बच्चों पर अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने गर्भावस्था के दौरान से डाटा एकत्र किए और बच्चों के 10 वर्ष की आयु होने तक उनकी निगरानी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि बचपन में जो बच्चे अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहे उनमें शिक्षा संबंधी कौशल कम विकसित हुए। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि यदि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करवाना है तो माता-पिता को न सिर्फ उनकी अच्छी परवरिश करनी होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि वे किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं।



ढोल की थाप पर लोकनृत्य

बोलीविया के अल आल्टो शहर में वर्जिन आफ कारमेन के सम्मान में आयोजित उत्सव के दौरान कलाकारों के अलग-अलग ग्रुपों ने लोकनृत्य एंडियन नृत्य मोरेनाडा का प्रदर्शन किया। ढोल, झांझ और तुरही की ताल पर नृत्य करते कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। मोरेनाडा बोलिवियन संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह पेरू, चिली, अर्जेंटीना और अन्य देशों मे भी काफी लोकप्रिय है। इसमें कलाकार खास तरह से तैयार किए गए कास्ट्यूम का इस्तेमाल करते हैं। एएफपी

अनियंत्रित शुगर को नियंत्रित करने का उपाय खोजा

कुमार संजय, लखनऊ

सफलता

- पैंक्रियाज से स्रावित शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन को रोक कर होगा डायबिटीज पर नियंत्रण
- पीजीआइ लखनऊ के इंडोक्राइनोलाजी विभाग के विज्ञानी कर रहे चुनिंदा मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी

पीजीआइ लखनऊ के विज्ञानियों ने अनियंत्रित शुगर के निदान का उपाय खोज लिया है। इसके साथ ही डायबिटीज के इलाज का नया रास्ता भी खुल गया है। संस्थान के इंडोक्राइनोलाजी विभाग के विज्ञानियों ने इलाज की इस विधि को प्रयोगशाला में स्थापित किया है, जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है।

संस्थान के इंडोक्राइनोलाजी विभाग के विज्ञानी डा. रोहित सिन्हा के मुताबिक, चूहों और अल्फा सेल पर परीक्षण के बाद जल्द ही कुछ चुनिंदा शुगर के मरीजों पर भी इस दवा का परीक्षण करने की तैयारी है। दरअसल, पैंक्रियाज (अग्नाशय) से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो पैंक्रियाज में बीटा सेल का निर्माण करता है। इस सेल की कार्य प्रणाली में कमी आने पर इंसुलिन कम बनता है, जिससे शुगर का उपापचय नहीं हो पाता। यह सामान्य शुगर होने की प्रक्रिया है। पैंक्रियाज से ग्लूकागन हार्मोन का भी स्राव होता है, जो अग्नाशय में स्थित अल्फा सेल से स्रावित होता है। यह हार्मोन लिवर में जाकर अधिक शुगर बनाने को प्रेरित करता है। इंसुलिन लेने के बाद भी यदि ग्लूकागन अधिक मात्रा में बनेगा तो शुगर भी ज्यादा बनेगा। इससे डायबिटीज इंसुलिन देने के बाद भी कई बार अनियंत्रित रहती है। शुगर के कुल मरीजों में से 0.5 से 0.8 में अनियंत्रित शुगर की परेशानी होती है। पैंक्रियाज में एमटीओआरसी-1 (मम्मलियान टारगेट आफ रैपामायसिन) प्रोटीन ग्लूकागन को स्रावित करता है। इस प्रोटीन को ब्लाक कर दिया जाए तो यह पैंक्रियाज से बाहर नहीं निकलेगा और शुगर भी अधिक नहीं बनेगा। इससे शुगर का स्तर निर्यंत्रित रहेगा।

ऐसे किया शोध

चूहों में खास दवा देकर पहले उनके बीटा सेल को नष्ट किया, जिससे उनमें इंसुलिन बनना बंद हो गया। शुगर का स्तर बढ़ गया तो इन चूहों में ग्लूकागन हार्मोन के स्राव को रोकने के लिए उन्हें रैपामायसिन त्वचा में दिया तो देखा उनमें शुगर का स्तर कम हो गया। इसके साथ लैब में सेल पर यह प्रक्रिया कर इसे स्थापित किया गया। इस शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल मालिक्यूलर मेटाबालिज्म में प्रकाशित किया गया है। इस शोध में छात्र डा. संगम रजक, डा. अर्चना तिवारी और डा. सना रजा ने विशेष भूमिका निभाई।

खतरे की जद में आईं 15 वानस्पतिक प्रजातियों को किया गया संरक्षित

केदार दत्त, देहरादून

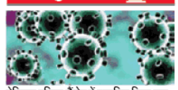
जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में बदली परिस्थितियों की मार से तमाम वानस्पतिक प्रजातियां भी अछूती नहीं रही हैं। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल 16 प्रजातियों में से 15 को वन विभाग के अनुसंधान वृत्त ने नर्सरियों में सहेजने में कामयाबी पाई है। इन प्रजातियों को अब अन्य स्थानों पर भी रोपने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उत्तराखंड में पुष्पीय वनस्पतियों (आवृत्तजीवी) की लगभग 4,700 प्रजातियां विद्यमान हैं। जड़ी-बूटियों का विपुल भंडार माने जाने वाले इस राज्य में अनेक औषधीय महत्व की वनस्पतियां हैं और इनका यही गुण इन पर भारी पड़ रहा है। औषधीय वनस्पतियों के अनियंत्रित दोहन समेत अन्य कारणों से इनके अस्तित्व पर संकट के बादल छाने लगे। इसे देखते हुए उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने प्रदेश में पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में अधिसूचित किया। वर्ष 2018 से वन विभाग के अनुसंधान वृत्त ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए मुहिम शुरू की। इसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं।

यहां संरक्षित हैं संकटग्रस्त प्रजातियां : मीठा विष, अतीस, कड़वी (त्रायमाण), मासी-जटामासी (मंडल, मुनस्यारी व देववन), छोटा अतीस, बटरफ्लाई आर्किड, (मंडल), बन पलास (हल्द्वानी व लालकुआं), रेड क्रेन आर्किड (हल्द्वानी), साला ट्री (टंगसा), गैंती (भुजियाकोट), पटवा (सेड़ियाताल), थाकल (मुनस्यारी), एरमोस्टैकस सुपेर्बा (हल्द्वानी व देहरादून), बटरवर्ट (माणा), स्नो आर्किड (ज्योलीकोट)।

मनोरोगियों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है कोरोना वायरस

अनुसंधान



मेडिकल पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित किया गया है अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कोरोना वायरस का असर हर इंसान पर अलग-अलग होता है। इसका घातक होना प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही पुरानी बीमारियों से भी सीधा संबंध रखता है। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि कोरोना वायरस से सामान्य व्यक्ति की तुलना में मनोरोगियों के मरने या अस्पताल में भर्ती होने की संभावना दोगुना ज्यादा होती है। यह अध्ययन मेडिकल पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित हुआ है। इसमें 22 देशों के 33 अध्ययन शामिल किए गए हैं। अध्ययन में 14,69,731 कोरोना (कोविड-19) रोगियों को शामिल किया गया। इनमें से 43,938 मरीज मनोरोगी थे। इन मनोरोगियों के द्वारा एंटीसाइकोटिक्स या एंक्जियोलाइटिक्स दवा ली जा रही थी। ऐसे मरीजों में कोरोना से मरने या अस्पताल पहुंचने का खतरा ज्यादा देखा गया। मादक पदार्थों के सेवन से बीमार होने वाले रोगियों में भी कोरोना के खतरे और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना ज्यादा रही। अध्ययन में पाया गया कि मनोरोगियों को उनकी बीमारी दूर करने के लिए जो दवाएं दी जा रही थीं,उससे भी प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण कोरोना के खतरे बढ़ गए। साथ ही हृदय रोग होने की भी संभावना देखी गई। अध्ययन में शामिल पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरियन लेबोयर ने कहा कि जीवन शैली से भी कोरोना के घातक होने का सीधा संबंध है। खराब खानपान, शारीरिक श्रम का न होना, ज्यादा शराब और तंबाकू का सेवन, अनिद्रा जैसे कारण भी कोरोना वायरस की तीव्रता पर असर डालते हैं। अध्ययन में स्वास्थ्य अधिकारियों से मनोरोगियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने की संस्तुति की है। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

हिंदी फिल्मों में काम करने का स्टारडम बड़ा है : सई



फिल्म इंडिया लाकडाउन में नजर आएंगी सई। इंस्टाग्राम

अब क्षेत्रीय सिनेमा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार एक-दूसरे की सिनेमा में काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में काम करने के अपने तरीके होते हैं। मराठी फिल्मों की अभिनेत्रा सई ताम्हणकर हिंदी फिल्मों में भी अब लगातार काम कर रही हैं। मिमी फिल्म के बाद वह मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लाकडाउन में नजर आएंगी। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर सबसे बड़ा फर्क सई को स्टारडम में नजर आता है। दैनिक जागरण से बातचीत में सई ने बताया कि बतौर एक्टर मुझे कोई बदलाव मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं नजर आता है। अभिनय दोनों ही इंडस्ट्री में करना है, लेकिन बजट और स्टारडम का बहुत बड़ा अंतर है। मराठी में बड़े बजट की जो फिल्में अब बन रही हैं, वह एक अच्छा बदलाव है, लेकिन अब भी जिस तेजी के साथ वह फिल्में बननी चाहिए, वह तेजी अब तक नहीं आई है। हिंदी और मराठी दोनों ही सिनेमा में मेहनती कलाकार हैं। बालीवुड और रीजनल सिनेमा के बीच की लाइन अब मिट रही है। कई बार दो इंडस्ट्री के बीच दूरी की वजह से गठबंधन नहीं बन पाता है, लेकिन कलाकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा गठबंधन दूसरी भाषा के सिनेमा से करें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और हमारे पास यही एक मौका होता है। स्टारडम की जहां तक बात है तो वह अंतर मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जरूर है। हिंदी फिल्में पूरा भारत देखता है। ऐसे में फिल्म की पहुंच बढ़ जाती है। दर्शक ज्यादा मिलते हैं। हिंदी फिल्में जब हिट होती हैं तो उससे जो स्टारडम मिलता है, वह मराठी फिल्मों से बड़ा होता है।

आइबी 71 होगी विद्युत जामवाल के प्रोडक्शन में बनने वाली पहली फिल्म

जंगली, कमांडो और खुदा हाफिज जैसी फिल्मों के अभिनेता विद्युत जामवाल ने कुछ महीनों पहले अपने प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स की घोषणा की थी। अब उनके प्रोडक्शन के अंतर्गत बनने वाली पहली फिल्म आइबी 71 का नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया गया है। इस फिल्म कि निर्माण वह रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर करेंगे, जबकि फिल्म के निर्देशन की बागडोर संकल्प रेड्डी के हाथों में होगी। संकल्प इससे पहले द गाजी अटैक और कुछ तेलुगु फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें विद्युत स्वयं मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म का कहानी साल 1971 में भारत पाकिस्तान-युद्ध के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की जड़ें हिला देने वाली घटनाओं को दिखाया जाएगा। इस युद्ध की जीत में खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा अंजाम दी गई कई घटनाओं का अहम योगदान रहा। विद्युत इस फिल्म में खुफिया विभाग के अधिकारी का किरदार निभाएंगे। निर्देशक संकल्प रेड्डी ने जारी बयान में कहा, 'फिल्म आइबी 71 साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले की घटनाओं और भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारियों की वीरता की कहानी बताती है। मुझे बहुत खुशी है कि निर्माताओं ने मेरे नजरिए पर भरोसा दिखाया है।'



आइबी 71 में खुफिया विभाग के अधिकारी का किरदार निभाएंगे विद्युत। सौ. टीम विद्युत

एक्टर के लिए प्लानिंग जरूरी है : अनूप

हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों का कहना होता है कि सिनेमा जगत में पूर्वनियोजित ढंग से कुछ नहीं होता है। यहां परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बदलती रहती हैं। हालांकि, रात बाकी है, प्रस्थानम और गंगाजल जैसी फिल्मों के अभिनेता अनूप सोनी के विचार इससे अलग हैं। एक लाइव चैट के दौरान उन्होंने कहा, 'कई लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्लानिंग काम नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्टर के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग उन चीजों के लिए होनी चाहिए कि आप किस तरह के किरदार निभाना चाहते हैं और आपकी अपनी पसंद क्या है? अपनी बात करूं तो मैंने काफी समय तक टेलीविजन के लिए काम किया अब मैं उससे ब्रेक लेकर फिल्मों और वेब सीरीज पर फोकस कर रहा हूं। इस साल मेरी तांडव और 1962 : द वार इन द हिल्स जैसी वेब सीरीज रिलीज हुईं। डिजिटल प्लेटफार्म पर फिल्म रात बाकी है रिलीज हुई। अब मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा अलग किरदार निभाऊं। टेलीविजन में अगर हमारा निभाया कोई किरदार लोकप्रिय हो जाता है तो हम कई वर्षों तक वही किरदार निभाते रहते हैं। इससे बतौर एक्टर आपका विकास नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप फिल्म या वेब सीरीज जैसी सीमित अवधि वाले प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो अलग-अलग किरदार निभाते हुए आपको भी विकास करने का मौका मिलता है। मेरी कोशिश भी कुछ यही है। मैंने आगे दो-तीन वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग करने जा रहा हूं।' अनूप आगामी दिनों में फिल्म सत्यमेव जयते 2 में पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे।



फिल्म सत्यमेव जयते 2 में पुलिस आफिसर के किरदार में नजर आएंगे अनूप। इंस्टाग्राम

किसी का भाई या बेटा होने की वजह से 25 साल तक काम नहीं मिलता

सात सवाल

सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। अपने सफर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। अब उनकी मेजबानी वाले चैट शो पिंच बाई अरबाज खान का सीजन 2 आ रहा है। इस बार उनके मेहमानों की फेहरिस्त में सलमान खान, आयुष्मान खुराना, टाइगर श्राफ, अनन्या पांडे, कियारा आडवाणी जैसे कई सितारे नजर आएंगे। यह शो जी5 और क्यूप्ले टीवी पर 21 जुलाई से उपलब्ध होगा। अरबाज से हुई बातचीत के प्रमुख अंश :



खुद पर फोकस कर रहे हैं अरबाज ● पीआर टीम

● **इस बार सलमान खान भी आपके शो की शोभा बढ़ाएंगे। उनके साथ विवाद भी जुड़े हैं...**

-दूसरे सीजन में सलमान का आना मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। पहले सीजन में मैं उन्हें ला सकता था, मेरा हक भी बनता था मगर मैं चाहता था कि वह पहले मुझे बतौर होस्ट पसंद करें, शो का कांसेप्ट पसंद करें। हम जब स्टार्स को बुलाते हैं तो उनसे क्या पूछना है, इस पर काम करते हैं। सलमान को छोड़ दें तो यह बात सब पर लागू होती है। जब हम कोई सेंसिटिव चीज पूछना चाहते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वही चीजें पूछें जिसमें स्टार सहज हों। उनका नो कमेंट आता है तो वह भी एक किस्म का जवाब ही है। हालांकि हमारे शो में किसी ने नो कमेंट नहीं कहा है।

● **पिता सलीम खान और भाई सलमान खान की किस बात ने आपको पिंच किया है?**

-इसे पिंच तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों का मानना है कि जितना मुझमें पोटेंशियल दिखा है, मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। उन्हें लगता था कि थोड़ा सा लक या मेहनत ज्यादा होती तो मैं अलग मुकाम पर होता। वे मुझे करीब से जानते हैं। मेरे टैलेंट से वाकिफ हैं। मैं भी कभी-कभी सोचता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को हल्के में लिया या देर की। टैलेंट मुझमें भले ही होगा, लेकिन डेडिकेशन और प्रयास करने की एकाग्रता कहीं न कहीं टूट जाती थी। उन्हीं चीजों पर उन्हें थोड़ा सा एतराज होता था। देर से ही सही मैंने उन चीजों को सीख लिया। अब मैं अपनी चीजों पर प्रोफेशनली काम करता हूं। उस वक्त जो चीजें मैंने मिस की थीं, जैसे- अपने आप पर काम करना, मेहनत करना, खुद पर फोकस रखना वो अब मैंने पकड़ ली हैं। मुझे 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। किसी के भाई और बेटे होने की वजह से कोई आपको 25 साल तक काम नहीं देगा।

● **करियर की शुरुआत में क्या कभी सलीम खान के बेटे और सलमान के भाई होने का दबाव रहा है?**

-मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं। लोगों को मुझसे उम्मीदें रही हैं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि खुद से ही सब करना है। प्रतियोगिता खुद से है, पिता और भाई से नहीं। वे अपनी मेहनत और किस्मत से आगे बढ़े हैं। मुझे खुद पर मेहनत करनी है। मैं जहां हूं, वहां खुश हूं, बतौर निर्माता-निर्देशक मैंने अपना नाम बनाया है। (हंसते हुए) मुन्ना भाई की तरह लगा हूं।

● **इंटरनेट मीडिया पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। इसके पीछे क्या वजह है?**

-अगर मैं रोज ट्वीट कर रहा होता, तभी मुझे इंटरनेट मीडिया पर शो करने का हक होता, ऐसा नहीं है। यह बात सही है कि मेरे इंटरनेट मीडिया पर बहुत ज्यादा फालोअर्स नहीं हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह नहीं है कि इंटरनेट मीडिया पर जो हो रहा है मैं उससे वाकिफ नहीं हूं। मैं उन स्टार के इंटरव्यू लेता हूं जो इंटरनेट मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं या पापुलर हैं। ऐसे भी स्टार हैं जो बहुत एक्टिव नहीं हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सलमान खान। उनके भले ही करीब 25 मिलियन फालोअर्स हैं, लेकिन वह भी इंटरनेट मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हैं। कोरोना महामारी के दौर ने लोगों को इंटरनेट मीडिया की अहमियत सिखाई है।

● **आपका परिवार अपने बच्चों को स्टारडम से दूर रखता आया है...**

-हम जानबूझ कर बच्चों को बहुत ज्यादा आगे नहीं लाते हैं। वे खुद भी नहीं आना चाहते हैं। अब वे कहीं समारोह से निकलते हैं और लोग तस्वीरें खींचते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वे अपना चेहरा छुपाते हैं, लेकिन ऐसा खुद कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वे मीडिया में बने रहें। मेरा बेटा 18 साल का है, लेकिन वह फेसबुक और ट्विटर पर नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सक्रिय नहीं है। उसने तीनों पीढ़ियों का स्टारडम देखा है। उसके लिए तस्वीरें खींचा जाना सामान्य है, यह समझ उसमें है। हमने तो जवानी में जब काम करना शुरू किया, तब यह बातें समझ में आई थीं।

● **डिजिटल पर आपने प्वाइजन शो किया था, उसके बाद कुछ और कर रहे हैं?**

-अप्लाज फिल्म्स के लिए मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में शो आ जाएगा।

● **दबंग 4 का काम कहां तक पहुंचा है? सलमान ने कहा था स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है...**

-अभी दो-तीन चीजों पर काम कर रहा हूं। भाई (सलमान खान) तो आइडियाज देते रहते हैं, उसे फिर विकसित करना पड़ता है। दबंग 4 जरूर बनेगी, लेकिन कब तक, यह फिलहाल नहीं पता है। (स्मिता श्रीवास्तव)

ट्विंकल ने पिता राजेश खन्ना को किया याद

माता-पिता द्वारा दिए संस्कारों के अलावा बच्चों के कई भौतिक गुण भी उनके माता-पिता से मिलते-जुलते हैं। अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना भी अपनी आंखों में पिता राजेश खन्ना की झलक देखती हैं। रविवार को हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना की नौवीं पुण्यतिथि पर ट्विंकल ने उन्हें याद किया। इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर राजेश खन्ना की साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म आप की कसम के सेट का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में राजेश खन्ना सुनो कहो, कहा सुना... गाने की शूटिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान जब उनसे रीटेक के बारे में पूछा जाता है तो वह कहते हैं मुझे बार-बार टेक करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें इससे (रीटेक) परेशानी होती है तो वह इससे इन्कार कर देते हैं। इसके बाद वह गाने के बीट पर अपनी परफार्मेंस और निर्देशक से मिलने वाली सराहना के बारे में बताते हैं। इसके साथ ट्विंकल ने लिखा, 'मेरे पास उनकी आंखें हैं, मेरे बेटे के पास उनकी मुस्कान है और उनका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा पूरी दुनिया के दिलों में है। वह अब भी जिंदा हैं...।' ट्विंकल के इस पोस्ट पर रितेश देशमुख, बाबी देओल, ताहिरा कश्यप और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत कई हस्तियों ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने भाव प्रकट किए। जय ओम प्रकाश निर्देशित फिल्म आप की कसम में राजेश खन्ना के साथ मुमताज और संजीव कुमार अहम भूमिकाओं में थे।



नौवीं पुण्यतिथि पर ट्विंकल ने पिता से जुड़ीं यादें साझा कीं। इंस्टाग्राम

श्रीलंका में हो सकती है राम सेतु की शूटिंग

कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने से पहले कई निर्माता अपनी फिल्में पूरी करने में जोर-शोर से जुटे हैं। फिलहाल आनंद एल राय निर्देशित फिल्म रक्षा बंधन की शूटिंग कर रहे अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल में अपनी अगली फिल्म राम सेतु के निर्देशक अभिषेक शर्मा और क्रिएटिव निर्माता चंद्रप्रकाश द्विवेदी से मुलाकात की। मुंबई स्थित प्रोडक्शन कंपनी अबुर्दंतिया प्रोडक्शन के आफिस में हुई इस मुलाकात में फिल्म की अभिनेत्रियां नुसरत भरुचा और जैकलिन फर्नांडीज भी शामिल हुईं। सूत्रों के मुताबिक राम सेतु की टीम ने इस मौके पर फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग तथा जैकलिन और नुसरत के लुक समेत कई विषयों पर चर्चा की। फिल्म के कुछ हिस्सों को श्रीलंका में भी फिल्माने पर चर्चा हुई। इसे लेकर श्रीलंकाई सुंदरी जैकलिन काफी उत्साहित रहीं। जैकलिन अपने मूल देश श्रीलंका के स्थानों और परिस्थितियों से भली-भांति वाकिफ हैं। हालांकि श्रीलंका शेड्यूल की शूटिंग डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले फिल्म के निर्माता विक्रम मल्होत्रा भी कह चुके हैं कि कुछ हिस्सों की शूटिंग विदेश में भी की जाएगी।



फिल्म में पुरातत्वविद की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय ● इंस्टाग्राम

Vikas Divyakriti Sir Hindi literature Full Course

Year - 2020-21
Total - 157 Video lectures + 20 Booklet Pdf

👉(Real Price - 40000/-)
👉We Provide only ₹1499 ✅

दृष्टि The Vision

Contact on Telegram 👉 @prakashstudy24

